इंडिया पब्लिक खबर

वर्ष: 08 ▪ अंक : 36 ▪ पृष्ठ : 12 ▪ 06 सितम्बर से 11 सितम्बर तक ▪ दिन: मंगलवार ▪ मूल्य: 4 रुपये

लखनऊ से प्रकाशित व प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर से प्रसारित

साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र

गौतम अडानी बने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति

www.indiapublickhabar.in

सुष्मिता सेन एक 'पावर-पैक' बायोपिक में निभाएंगी मुख्य भूमिका

खास खबरें

खेलों में वैश्विक स्तर पर छाने को तैयार यूपी-हरियाणा

आईपीके, लखनऊः वर्तमान समय में देश में खेलों को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। वैसे तो हमेशा से ही भारत में कई ऐसे खेल हैं, जिन्हें काफी पसंद किया जाता रहा है, लेकिन उन विश्व स्तर पर उतनी पहचान नहीं मिल पाती थी। फिर एक समय ऐसा है, जब क्रिकेट की लोकप्रियता ने बाकी सभी खेलों को अपने अंदर ढक लिया। अब पिछले कुछ सालों से देश में न सिर्फ क्रिकेट, बल्कि हर तरह के खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ताकि विश्व स्तर पर भारत का परचम.... शेष पेज 10 पर

2023 से उड़ान भरेगा स्वदेशी एलसीए मार्क-2 लड़ाकू विमान

नई दिल्लीः दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में शुमार लाइट कांबैट एयरक्राफ्ट मार्क-2 (एलसीए) के अगले साल 2023 के अंत में पहली उड़ान भरने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने एलसीए एमके-2 लड़ाकू विमान विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस मंजूरी से उन्नत 17.5-टन एकल-इंजन विमान विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। नए विमानों का विकास 2027 तक पूरा होगा। इसके बाद तेजस डिफेंसिव एयरक्राफ्ट का तमगा खोकर अटैक करने वाले लड़ाकू विमानों की श्रेणी में शामिल हो .... शेष पेज 11 पर

'ब्रह्मास्त्र' से दूर होगा बॉलीवुड पर लगा फ्लॉप का ग्रहण !

आईपीके, लखनऊः बॉलीवुड पर लगा फ्लॉप का ग्रहण हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। आधे से ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी बॉलीवुड के खाते में सिर्फ 2 से 3 हिट फिल्में ही आई हैं। इस बीच बड़े बैनर और बड़े स्टार्स की फिल्में भी रिलीज हुईं, मगर वो भी दर्शकों को रिझा पाने में पूरी तरह से नाकाम ही साबित हुई हैं। आलम ये है कि इस समय न एक्शन का तड़का काम आ रहा है, न हीरो का टशन, न .... शेष पेज 12 पर

खबरों से अपडेट रहने के लिए स्कैन करें।

सूचना

सभी सुधी पाठकों को सूचित किया जाता है कि तकनीकी कारणों की वजह से समाचार पत्र को सोमवार के स्थान पर मंगलवार को प्रकाशित किया जा रहा है।

लेवाना होटल में लगी आग, चार ने घुटकर तोड़ा दम

मुख्यमंत्री योगी ने दिए उच्चस्तरीय जांच के निर्देश, ध्वस्त किया जाएगा होटल, गिरफ्तार हुए मालिक बंधु

आईपीके, लखनऊः प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित लेवाना सुइटस होटल की तीसरी मंजिल पर सोमवार की सुबह लगभग 07 बजकर 30 मिनट पर शार्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग की चपेट में आए चार लोगों ने घुटकर दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मी और एनडीआरएफ की टीम ने 09 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में होटल में फंसे 24 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सिविल अस्पताल पहुंचकर भर्ती हुए घायलों का हाल-चाल लिया और मंडलायुक्त व पुलिस कमिश्नर को उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं।

शहर के पॉश इलाके हजरतगंज में स्थित लेवाना होटल में करीब 30 कमरे है, जिसमें कि 18 कमरे बुक थे। सोमवार 05 सितम्बर की सुबह करीब सवा आठ बजे के दरम्यान होटल लेवाना सुईट में शार्ट सर्किट से आग लग गई। द्वितीय और तृतीय तल को चपेट में लेने के बाद होटल में धुंआ भर गया, जिससे लोगों का दम घुटने लगा। होटल में इमरजेंसी व्यवस्था न होने की वजह से होटल में ठहरे लोग मदद को लेकर चीखने-चिल्लाने लगे। घटना की जानकारी होने पर 15 से अधिक दमकल की गाड़ियां और कर्मचारी पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गए।

फायर कर्मचारी और पुलिस ने होटल का शीशा तोड़कर सीढ़ियों की मदद से लोगों को बाहर निकाला। लोगों को बचाने में फायरकर्मी चन्द्रेश कुमार भी झुलस गए। सभी झुलसे लोगों को इलाज के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल पहुंचा गया। झुलसे लोगों अंश कौसिक, कामिनी, मोना, राजकुमार, आनंद उपाध्याय, श्रवण और फायर कर्मी प्रदीप का इलाज चल रहा है। इस अग्निकांड में चार लोगों की मृत्यु हुई है, उनमें गणेशगंज के सराय फाटक पर रहने वाले गुरनूर आनंद और उनकी मंगेतर साहिबा कौर है। एक साथ दोनों इसी होटल में ठहरे हुए थे। दोनों की लाश तीसरी मंजिल की गैलरी में मिली है। इसके अलावा इंदिरानगर निवासी अमान गाजी उर्फ बॉबी और श्रीविका सिंह उर्फ चिया है, जिनके शव तीसरी मंजिल के कमरे से निकाले गए। होटल में ठहरे अंश कौसिक के मुताबिक, होटल में सुबह 08 बजे के दरम्यान आग लगी, जब वे सो रहे थे। अचानक जब चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनी, तो उनकी नींद खुल गई। बाहर देखा तो ही धुंआ ही धुंआ था। थोड़ी देर में धुंआ उनके कमरे में भी पहुंचा तो उनका भी दम घुटने लगा। घटना की जानकारी पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि शार्ट सर्किट के चलते होटल में आग लग गई है। सभी को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल-चाल जाना। हजरतगंज पुलिस ने

मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए होटल मालिक रोहित और राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है।

ध्वस्त किया जाएगा होटल

आग लगने और उसमें हुई लोगों की मृत्यु के बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरु हो गई है। मंडलायुक्त जैकब रोशन ने होटल को नियमानुसार सील कर ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। एलडीए से मिली जानकारी के बाद मंडलायुक्त ने नक्शा पास हुए बिना संचालन कराने में लिप्त अधिकारियों-कर्मियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए।

अलर्ट हुआ एलडीए, शहर के सभी होटलों की होगी जांच

लेवाना होटल में अग्निकांड की घटना के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बैठक की और अधिकारियों को अलर्ट करते हुए कहा कि होटलों की वर्तमान स्थिति की जांच कराएं। लखनऊ में मानक के अनुसार चल रहे होटलों के अतिरिक्त होटलों को चिह्नित करते हुए उसकी सूची बनाएं। आग से निपटने के उचित इंतजाम को पूरा कराने के लिए होटल मालिक व संचालक को निर्देशित करें। लालबाग स्थित एलडीए कार्यालय की बैठक में उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि ने कहा कि होटल के मालिकों को स्वयं से ही आग से निपटने के लिए हर प्रयास रखने चाहिए। जो होटल मालिक व्यवस्थाओं को अपनाने के स्थान पर दुर्व्यवस्था फैलाने का कार्य कर रहे हैं, वो कार्यवाही के अंतर्गत आएंगे। उन्होंने कहा कि लेवाना होटल मामले में सम्बंधित क्षेत्र को देख रहे सहायक अभियंता, अवर अभियंता को उक्त मामले में अपनी सफाई देनी होगी। इस तरह की लापरवाही के साथ चल रहे होटल में आग लगने के बाद उसे बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। जिसके कारण लेवाना अग्निकांड जैसी घटना हो गई। एलडीए की एक टीम उक्त घटना की पूरी जानकारी करके उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अर्शदीप के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश का हुआ खुलासा

नई दिल्लीः एशिया कप में पाकिस्तान से भारत को मिली हार के बाद से तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब उनके खिलाफ पाकिस्तान द्वारा रची जा रही साजिश का भंडाफोड़ हुआ है।

सूत्रों के मुताबिक, क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को लेकर पाकिस्तान की आईए-सपीआर की तरफ से अर्शदीप को खालिस्तानी बताने की साजिश रची गई थी। ऐसी साजिश पंजाब में सिख लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए रची गई थी। इसके लिए पाकिस्तान से सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से खालिस्तानी वाले ट्वीट किए गए। दरअसल, सुपर-4 के मैच में अर्शदीप सिंह ने रवि बिश्नोई की बॉल पर आसिफ अली का बेहद आसान कैच छोड़ दिया था। इसके बाद टीम इंडिया जब मैच हारी, तो लोगों ने ट्विटर पर अर्शदीप सिंह को निशाने पर ले लिया। हालांकि, पाकिस्तान से मैच हारने के बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली समेत तमाम दिग्गज खिलाड़ियों ने अर्शदीप का बचाव किया। कोहली ने युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि दबाव में कोई भी गलती कर सकता है। आगे कहा कि जब मैंने चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था, तब भी मैंने खराब शॉट खेला और आउट हो गया। दबाव में कोई भी गलती कर सकता है और बुरा लगना स्वाभाविक है।

लिज ट्रस बनीं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, सुनक को हराया

लंदनः ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को खासा झटका दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का स्थान लेने के लिए हुए चुनाव में ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने सुनक को हरा दिया है। अब ट्रिस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनेंगी।

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुनने की दौड़ में बने पूर्व वित्त मंत्री व भारतीय मूल के ऋषि सुनक और वर्तमान विदेश मंत्री लिज ट्रस के बीच मुकाबला था। ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के एक लाख साठ हजार मतदाताओं में से 57 प्रतिशत ने लिज ट्रस को समर्थन दिया। 43 प्रतिशत लोग ऋषि सुनक के साथ थे। इससे यह भी स्पष्ट है कि ऋषि सुनक ने इस चुनाव में कड़ी टक्कर दी। लिज ट्रस को कंजर्वेटिव पार्टी के पिछले कुछ नेताओं की तुलना में सर्वाधिक कठिन प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ा और उन्हें अन्य विजेताओं की तुलना में कम समर्थन मिला। इससे पहले बोरिस जॉनसन को 66 प्रतिशत, डेविड कैमरून को 68 प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन मिला था।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में सफल हुईं ट्रस की जिंदगी भी काफी रोचक है। ट्रस इस समय ब्रिटेन की विदेश मंत्री हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ी 47 साल की ट्रस के पिता गणित के प्रोफेसर और मां एक नर्स थीं। लेबर पार्टी समर्थक परिवार से आने वाली ट्रस ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए अकाउंटेंट के रूप में भी काम किया। इसके बाद वह राजनीति में आ गईं। सबसे पहला चुनाव उन्होंने पार्षद का जीता था। परिवार लेबर पार्टी का समर्थक था, लेकिन ट्रस को कंजर्वेटिव पार्टी की विचारधारा पसंद आई। 2010 में ट्रस पहली बार सांसद चुनी गईं। ट्रस शुरुआत में ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से अलग होने के मुद्दे खिलाफ थीं। हालांकि, बाद में वे ब्रेग्जिट के हीरो बनकर उभरे बोरिस जॉनसन के समर्थन में आ गईं।

एचएएल अब एलएंडटी के साथ मिलकर बनाएगा रॉकेट

नई दिल्लीः हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) अब भारतीय लड़ाकू विमानों के साथ-साथ देश के लिए पीएसएलवी रॉकेट भी बनाएगा। एचएएल और एलएंडटी कंसोर्टियम ने न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआ-ईएल) के साथ पांच पीएसएलवी रॉकेट बनाने के लिए 860 करोड़ रुपए का सौदा किया है। यह समझौता ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों (पीएसएलवी) के एंड-टू-एंड उत्पादन में पहला प्रयास है।

एचएएल के मुताबिक, यह अनुबंध पांच पीएसएलवी रॉकेटों का निर्माण करने के लिए किया गया है, जो भारत का बहुमुखी प्रक्षेपण यान है। तीन बोलियों के तकनीकी-व्यावसायिक मूल्यांकन के बाद एचएएल-एलएंडटी कंसोर्टियम पीएसएलवी के एंड-टू-एंड उत्पादन के लिए तकनीकी रूप से योग्य और एल1 बोलीदाता के रूप में उभरा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड ने पीएस-एलवी रॉकेट उत्पादन के लिए एचएएल और एलएंडटी कंसोर्टियम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंसोर्टियम की ओर से बताया गया है कि इस सौदे में एचएएल की 52 और एलएंडटी की 48 फीसदी साझेदारी होगी। दो साल से भी कम समय में

- दोनों के बीच हुआ 860 करोड़ का सौदा

इसरो को पहला स्वदेशी रॉकेट देने में सक्षम होंगे। अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में भारत की तीसरी पीढ़ी के प्रक्षेपण यान पीएसएलवी के लगभग 80 प्रतिशत मैकेनिकल सिस्टम और 60 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उद्योग से आते हैं। कंसोर्टियम अब सरकारी स्वामित्व वाली ठेकेदार संचालित 'गोको' मॉडल के तहत इसरो की मौजूदा सुविधाओं का उपयोग करके लॉन्चर के उत्पादन, संयोजन और एकीकरण के लिए जिम्मेदार होगा। एनएसआईएल के अनुसार, उसकी अगली योजना पूरी तरह से स्वदेश निर्मित जीएसएलवी-मार्क III रॉकेट को साकार करने की है। इस साल जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनएसआईएल को 10 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों के हस्तांतरण को मंजूरी दी थी। सरकार ने एनएसआईएल की अधिकृत शेयर पूंजी 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए करने को भी मंजूरी दी थी। अंतरिक्ष विभाग ने एनएसआईएल को शुरू से अंत तक वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों और पूर्ण उपग्रह ऑपरेटर के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी है। एनएसआईएल ने 2020-21 में 432.67 करोड़ रुपए के परिचालन से राजस्व और 121.84 करोड़ रुपए के कर के बाद लाभ हासिल किया है।

झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन ने जीता विश्वास मत

सदन में हंगामे के बीच पक्ष में पड़े 48 वोट

रांचीः झारखंड की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का पटाक्षेप हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार 05 सितम्बर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें हेमंत सरकार ने विश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा और विश्वास मत हासिल कर लिया है। 81 सदस्य वाली विधानसभा में सरकार के पक्ष में 48 वोट पड़े। प्रस्ताव के विरोध में किसी ने भी मत नहीं दिया। इस दौरान भाजपा ने वॉकआउट किया। विश्वास मत पर वोटिंग के बाद विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो ने विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चि-तकाल के लिए स्थगित कर दी।

इसके पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैसे ही विश्वास मत के प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया, तभी भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया। विश्वास मत के प्रस्ताव पर हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि विश्वास प्रस्ताव लाने की वजह भाजपा है, जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं होती है, वहां

भाजपा की तरफ से गृह युद्ध जैसा माहौल बना दिया जाता है इसलिए यूपीए को विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष से निवेदन है कि बहस के दौरान नोक-झोंक होती रहती है। आग्रह यह है कि आज का प्रस्ताव सुनें और मैदान छोड़कर भागने का प्रयास न करें। राज्य की सवा तीन करोड़ जनता में आप भी शामिल हैं। जब भी मैं सवा तीन करोड़ जनता की बात करता हूं, तो आप भी उसमें शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि आज विश्वास मत को लेकर चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार के पास बहुमत है, तो विश्वास मत की क्या जरूरत है।

कांग्रेस सरकार बनने पर माफ होंगे किसानों के कर्ज : राहुल

- गुजरात चुनाव को लेकर भरी हुंकार, 10 लाख रोजगार का वादा
- कोरोना मृतकों के परिजनों को भी 04 लाख मिलेगा मुआवजा

अहमदाबादः राज्य में विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीने दूर हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं के गुजरात दौरे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी सोमवार 05 सितम्बर को अहमदाबाद के दौरे पर हैं। रिवर फ्रंट में आयोजित संकल्प सम्मेलन में राहुल गांधी ने कई चुनावी घोषणाएं की हैं।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कोरोना से तीन लाख लोगों की मौत हुई है। क्या सरकार ने कोई मुआवजा दिया ? कोरोना में मरने वालों के परिवारों को हम 04 लाख का मुआवजा देंगे। हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हम तीन हजार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बनाएंगे और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देंगे। राहुल गांधी ने अपने सम्बोधन में कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए आज यहां गुजरात के कोने-कोने से हजारों बब्बर शेर आए हैं, जो वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई। सरदार पटेल केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे गुजरात और हिंदुस्तान के किसानों की आवाज थे। यदि आप सरदार पटेल जी के भाषण सुनते या पढ़ते हैं, तो उन्होंने किसानों

के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। उनके बिना गुजरात में अमूल का उदय नहीं होता। भाजपा एक तरफ सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाती है और दूसरी तरफ उनके लिए काम करने वालों के खिलाफ हमेशा काम करती है।

रिवर फ्रंट पर कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दूसरे राज्यों के किसानों का कर्ज माफ किया है। यहां भी हम हर किसान का 03 लाख तक कर्ज माफ करेंगे। भाजपा ने 03 काले कानून लाकर किसानों के अधिकार छीनने का प्रयास किया था, इसलिए किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। राहुल ने कहा कि गुजरात नशे का केंद्र बन गया है। मुंद्रा बंदरगाह से मादक पदार्थों की सप्लाई हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। गुजरात के युवाओं का भविष्य तबाह किया जा रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गुजरात के गरीब जमीन मांगते हैं, तो कुछ नहीं मिलता। भूमि उद्योगपतियों को दी जाती है। गुजरात देश का ऐसा राज्य है, जहां आंदोलन के लिए अनुमति लेनी पड़ती है।

लिंगायत संत ने की आत्महत्या

बेलागवीः कर्नाटक के बेलगावी जिले के नेगीनाहला गांव में गुरु मदीवलेश्वर मठ के पुजारी बसवा सिद्धलिंग स्वामीजी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वह सेक्स स्कैंडल में अपना नाम घसीटे जाने से काफी आहत थे।

दरअसल, यौन शोषण पर चित्रदुर्ग मठ में महिलाओं और लड़कियों के बीच कथित बातचीत वाली एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि दोनों महिलाओं ने चर्चा में मृतक बसवा सिद्धलिंग स्वामीजी का नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान पर ठेस पहुंची। मठ के भक्तों ने बेलगावी जिले के बाइलाहोंगला के पुलिस उपाधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई और लिंगायत संतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने बताया कि बसवा सिद्धलिंग स्वामीजी रविवार 04 सितम्बर की देर रात तक श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि उन्हें कथित ऑडियो में अपना नाम सुनकर काफी दुख पहुंचा है। यह बेहद अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि अब जीने का मन नहीं कर रहा है। पुलिस ने कहा कि वे स्वामीजी के सुसाइड नोट की तलाश कर रहे हैं, ताकि आत्महत्या के सही कारणों का पता चल सके। आगे की जांच जारी है।

सॉफ्टवेयर पर नहीं ब्रेक, प्रतिबंधित जनपदों को जारी हो जा रही एनओसी

आईपीके, लखनऊः प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रदेश के 40 जनपदों में पुराने वाहनों की एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) पर रोक लगा रखी है, बावजूद इसके एनजीटी द्वारा प्रतिबंधित जनपदों के लिए भी एनओसी जारी हो जा रही है। इसकी वजह यह है कि एनआईसी (नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर) के सॉफ्टवेयर में प्रतिबंधित जनपदों को एनओसी जारी करने के दौरान किसी प्रकार के रोक की व्यवस्था नहीं बनाई गई है। ऐसे में एनजीटी द्वारा प्रतिबंधित जनपदों के लिए भी आसानी से एनओसी जारी हो जा रही है।

समस्या तब और अधिक बढ़ जाती है, जब वाहनस्वामी एनओसी जारी होने वाले उक्त जनपद में अपना वाहन पंजीकृत कराने जाता है और उसे पता चलता है कि प्रतिबंधित जनपद के चलते वाहन पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। जानकारी के अभाव में हो रही यह चूक वाहन स्वामियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है, बावजूद इसके परिवहन विभाग मुख्यालय एनआईसी के सॉफ्टवेयर में बदलाव को लेकर कदम नहीं उठा रहा है। जानकारी के अनुसार, एनआईसी के सॉफ्टवेयर में कहीं पर भी प्रतिबंधित किए गए जनपदों के लिए एनओसी जारी करने के दौरान रोक की व्यवस्था

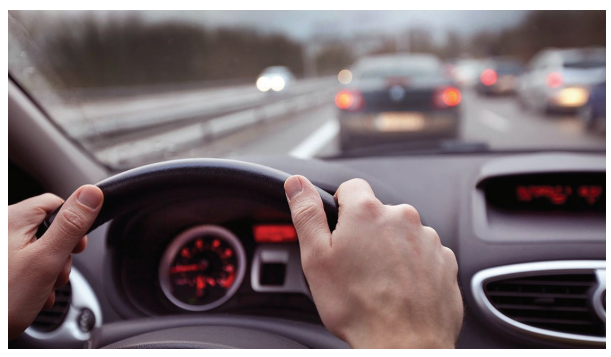

- परिवहन विभाग की लापरवाही, परेशान हो रहे वाहनस्वामी
- 40 जनपदों में पुराने वाहनों की एनओसी पर लगा है प्रतिबंध

नहीं है। अगर किसी कॉमर्शियल वाहन का टैक्स बकाया है अथवा उसका चालान हुआ है तो जब तक टैक्स या चालान नहीं जमा होंगे, तब तक एनओसी नहीं बनेगी। एनओसी बनाने के दौरान चालान या टैक्स का बकाया होने पर एनआईसी का सॉफ्टवेयर उक्त कार्य को वहीं रोक देता है। जब तक बकाया जमा नहीं होता, तब तक सिस्टम काम को आगे नहीं बढ़ने देता। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कॉमर्शियल वाहन की एनओसी महीने की आखिरी तारीख को बनने के लिए दी जाती है और किसी कारणवश उस दिन एनओसी नहीं जारी हो पाती है, तो अगले दिन एनओसी जारी करने के दौरान उक्त वाहन के टैक्स का बकाया सिस्टम पर दिखाने लगता है। ऐसे में एनओसी का काम सिस्टम पर वहीं रूक जाता है। इसी प्रकार वाहन का चालान होने की स्थिति में भी काम रूक जाता है। एनओसी बनाने के दौरान एनआईसी के सॉफ्टवेयर में भी प्रतिबंधित जनपदों को लेकर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए तो काफी सहूलियत होगी यानी एनओसी बनाने के लिए जैसे ही सिस्टम पर प्रतिबंधित जनपद का चयन किया जाए, वैसे ही काम वहीं रूक जाए। इससे वाहन स्वामियों को काफी सहूलियत होगी।

35 जनपदों में मान्य है एनओसी

एनजीटी के प्रतिबंध के बाद परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर 35 जनपदों को एनओसी के लिए अनुमन्य किया है। इनमें मथुरा, इटावा, बिजनौर, संत-कबीरनगर, अम्बेडकरनगर, कुशीनगर, फर्रूखाबाद, जौनपुर, कन्नौज, बलिया, सुलतानपुर, गाजीपुर, मैनपुरी, प्रतापगढ़, सिद्धार्थ-नगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, औरैया, सोनभद्र, फतेहपुर, पीलीभीत, शाहज-हांपुर, लखीमपुर, बदायूं, बलरामपुर, हरदोई, बहराइच, उरई, एटा, कासगंज, महोबा, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, अमेठी जनपद शामिल हैं।

एनजीटी ने दिया था आदेश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जुलाई 2016 में 10 वर्ष पुरानी डीजल व 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की एनओसी के लिए 37 जनपदों को सूचीबद्ध किया था। इसके तहत एनसीआर जनपदों से उक्त पुराने वाहनों की एनओसी सूचीबद्ध जनपदों को ही जारी किए जाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, आगे चलकर दो और जनपदों को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके बाद प्रदेश के 35 जनपद एनओसी के लिए अनुमन्य किए गए। सॉफ्टवेयर की व्यवस्था में गड़बड़ी के चलते अभी भी प्रतिबंधित जनपदों के लिए एनओसी जारी हो जा रही है, जिसके चलते वाहन स्वामियों को परेशान होना पड़ रहा है।

एकदिवसीय शिक्षक कार्यशाला का हुआ आयोजन

आईपीके, प्रयागराजः जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज में नगर क्षेत्र एवं चाका ब्लॉक के सहायक अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शिक्षकों को 'शिक्षा में कहानी और रोलप्ले विधि' विषयक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला डायट प्रयागराज और एच.पी.पी.आई संस्था के संयुक्त तत्वाधान में डायट सभागार में सम्पन्न हुई। कार्यक्रम प्राचार्य डायट प्रयागराज के राजेंद्र प्रताप के निर्देशन में सम्पन्न हुआ। उद्घाटन वरिष्ठ प्रवक्ता डायट रत्ना यादव एवं ममता यादव ने किया। कार्यक्रम में हरिकेश कुमार, शिब्बा राय, गगन चंद्र, मास्टर ट्रेनर के रूप में भूमिका निभाई तथा कार्यक्रम में समस्त वरिष्ठ प्रवक्ता, प्रवक्तागण एवं डायट मेंटर अखिलेश सिंह, निधि मिश्रा, कुलभूषण मौर्य, नीलम चतुर्वेदी, अंबालिका मिश्रा, वीरभद्र प्रताप सिंह, रिचा राय, वर्तिका कुशवाहा, विवेक त्रिपाठी, शबनम, तथा डी.एन.एस. शिक्षक में अंशिका सक्सेना, घनश्याम सिंह आदि उपस्थिति रहे। अंत में सभी को कार्यशाला में प्रतिभाग करने के उपरांत प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन अखिलेश सिंह तथा कार्यक्रम का संचालन संजय यादव ने किया। कार्यक्रम के आयोजक मुकेश लोमड (प्रभारी नेट) रहे।

भाजपा में नहीं दिया जाएगा परिवारवाद को बढ़ावाः भूपेंद्र चौधरी

नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कहा जल्द भरे जाएंगे निगमों व बोर्डों के पद, प्रदेश में नहीं दिख रहा है कोई विपक्ष

लखनऊः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। संगठन की गतिविधियों को समझने के लिए उन्होंने दौरे भी शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं के हित सर्वोपरि हैं और उनके अथक परिश्रम से ही परिणाम मिलता है। उन्हें इसका मूल्य मिलेगा। तमाम बोर्डों और निगमों में जो पद खाली हैं, उन्हें भरने की प्रकिया शुरू की जाएगी।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आईएएनएस से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि निगम, बोर्डों, निगमों और आयोगों में जो पद खाली पड़े हैं, उन पर कार्यकर्ताओं का समायोजन जल्द होगा। यह विषय पार्टी के संज्ञान में है। हमारे पास इसकी सारी सूची है। कार्यकर्ताओं का सारा डेटा संगठन के पास है। इसका होमवर्क भी है। इस बारे में सामूहिकता के साथ मिल-बैठकर निर्णय किया जाएगा। सूची सरकार को मनोनयन के लिए भेजी जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय, जल्द ही इसको हल कर लिया जाएगा।

नरम रवैया अपना सकती है पार्टीः चौधरी

लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले निकाय चुनाव के लिए टिकट वितरण नीति के सवाल पर भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी में किसी भी तरह के परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय आने पर इस बारे में फैसला लिया जाएगा कि नगर निकाय चुनाव में सांसद, विधायकों के परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जाएगा या नहीं। इस दौरान भूपेंद्र ने इशारों ही इशारों में ये संकेत जरूर दे दिया कि जरूरत पड़ी तो पार्टी नरम रवैया अपना सकती है। भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि पंचायत चुनाव में पार्टी ने तय किया था कि किसी भी बड़े नेता या जनप्रतिनिधि के परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा। पंचायत चुनाव के समय पार्टी ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया था। हालांकि, अभी इस बारे में कोई नियम नहीं बना है इसलिए जब भी चुनाव आएगा, इस बारे में बैठकर तय किया जाएगा। लेकिन पार्टी की मूलभावना परिवारवाद के खिलाफ है। मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार पार्टी का एजेंडा पूरा कर रही है। पार्टी के एजेंडे पर सरकार चल रही है। हमने संकल्प

पत्र में जो बाते कहीं हैं उसको सरकार पूरा कर रही है। कुछ व्यक्तिगत विषय होंगे, तो हम लोग सामूहिक रूप से बैठकर निपटा लेंगे। उन्होंने खुद भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 'एक पद-एक विधान' नियम का पालन किया और तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अभी पार्टी में बहुत से लोग दो पदों पर आसीन हैं। इस पर चौधरी ने कहा कि चूंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, जब तक त्याग पत्र न देता तो व्यवस्था नहीं बनती। मिल बैठकर नई व्यवस्था तय कर देंगे कि लोग दूसरा पद मिलने पर एक पद से अपने आप कार्य मुक्त हो जाएं।

भाजपा के मुकाबले में नहीं है कोई पार्टी

आने वाले समय में आपका किस पार्टी से मुकाबला है, इस सवाल पर चौधरी ने कहा कि अभी तो भाजपा के सामने मुकाबले में कोई नहीं है। सपा प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन उनके गठबंधन के पूर्व सहयोगी ओपी राजभर ही बता रहे हैं कि वे कहां रहते हैं और उनकी राजनीति में सक्रियता कितनी है। बसपा मुखिया कहां हैं? कांग्रेस की भाई-बहन की जोड़ी दिखाई नहीं दे रही है। विपक्ष कहीं नहीं है, हम जनता के बीच हैं। जनता से हमारे कार्यकर्ता का सम्पर्क, सम्वाद बना हुआ है। गन्ना किसानों के भुगतान के सवाल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछली सरकारों ने चीनी मिलों को बेचा है, जबकि हमारी सरकार ने कोरोना जैसी महामारी में मिलों को चलाकर किसानों के हितों का ख्याल रखा है। भाजपा सरकार ने किसानों को गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान कराया है। गन्ना भुगतान को लेकर कोई आंदोलन अब नहीं हो रहा है। विपक्षी दल किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर निशाना साध रहे थे। कथित किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा था कि उन्होंने अखिलेश को पिच तैयार करके दी थी, वह बैटिंग नहीं कर पाए तो क्या करें? विपक्षियों को जनता ने विधानसभा चुनाव में नकार दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि किसान आंदोलन तीन कृषि कानून वापस लेने के बाद समाप्त हो गया। यह अब जो बातें हो रही है, यह सब भड़काऊ गैंग के सदस्य हैं। यह अपने हित के लिये ऐसी बात करते हैं। पश्चिम में सपा-रालोद गठबंधन के असर के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं जाट समाज से आता हूं। खराब समय में भी सबसे ज्यादा वोट भाजपा को पश्चिम जिले से मिले हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में पहला चरण सपा-रालोद के प्रभाव वाला क्षेत्र था, लेकिन भाजपा ने 58 में से 46 सीटें जीतीं। पहले चरण में 80 प्रतिशत वोट इसी समुदाय से आते हैं। वहां भाजपा को बढ़त मिली है। पश्चिमी यूपी को 06 मंडलों में 70 प्रतिशत सीटें भाजपा को ही मिली हैं।

आवश्यकता

इंडिया पब्लिक खबर को अपने न्यूज पोर्टल के लिए अनुभवी न्यूज कोऑर्डिनेटर और यूट्यूब चैनल के लिए स्क्रिप्ट राइटर व एंकर की तत्काल आवश्यकता है।

सम्पर्क करें-
8795811984, 8795822217

फर्जी मदरसों पर होगी कार्रवाईः गुलाब देवी

मेरठः प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि फर्जी मदरसों और विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। त्यागी समाज के आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सपा की त्यागी पॉलिटिक्स को सभी लोग समझ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी शुक्रवार 02 सितम्बर को मेरठ पहुंचीं। सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकारी अनुदान लेने के लिए चलाए जा रहे मदरसों और विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। फर्जी संस्थान भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। छात्रवृत्ति घोटालों को रोकने के लिए मदरसों और विद्यालयों की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है। सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड के विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षण उपलब्ध कराने की तैयारी हो रही है।

होटल-रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस शराब मिलने पर होगी कार्रवाई

आईपीके, झांसीः जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जनपद में आबकारी विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अगस्त माह की प्रगति की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग की राजस्व वसूली के वार्षिक लक्ष्य की जानकारी लेते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी व पुलिस हुक्का बार के संचालन को सख्ती से रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाएं। इसके अतिरिक्त जनपद में मादक पदार्थों के परिवहन को भी रोके जाने के लिए बड़े वाहनों की चेकिंग करना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने समस्त होटल/रेस्टोरेंट के स्वामी/मैनेजर को ताकीद करते हुए कहा कि होटल परिसर, रेस्टोरेंट परिसर में शराब पिलाना आबकारी नियमों के विरुद्ध है। बिना अधिकृत बार लाइसेंस के अवैध रूप से शराब परोसते यदि कोई पकड़ा जाता है, तो सम्बंधित के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को लगातार जांच किए जाने के भी निर्देश दिए और कहा कि नशीली दवाओं के इस्तेमाल

- जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग की बैठक में दिए निर्देश

और मादक पदार्थों की बिक्री के सम्बंध में भी लगातार छापामार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी व उप आबकारी आयुक्त, झांसी प्रभार के निर्देशन में 01 से 30 अगस्त तक प्रशासन, पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा छापेमारी में 18,247 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 39 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए कुल 101 अभियोग पंजीकृत किए गए। साथ ही मौके पर 71,700 किग्रा लहन नष्ट किया गया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि प्रवर्तन अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण करें और ऐसे स्थान जहां अवैध शराब निर्मित किए जाने की सम्भावना है या भंडारण है, उन स्थानों पर दल बल के साथ दबिश देते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे अवैध शराब के निर्माण के अड्डों को नष्ट कर दिया जाए, ताकि भविष्य में शराब निर्मित न की जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित होटल व ढाबों की भी लगातार चेकिंग की जाए, ताकि अवैध शराब के कारोबार को रोका जा सके। उन्होंने आबकारी विभाग के अधिकारियों को अवैध शराब की बिक्री न होने पाए के सम्बंध मे चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र भ्रमण में सम्वेदनशील होकर कार्य करें। इस मौके पर आबकारी विभाग की टीम में शामिल शिशुपाल सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1, हर्ष बाबू आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 व आनंद कुमार सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4, अशोक कुमार आबकारी निरीक्षक सहित स्टॉफ को किए गए कार्य पर बधाई देते हुए आगे भी इसी मनोयोग से काम करने की सलाह दी।

रैली निकालकर हुई राष्ट्रीय पोषण माह की शुरूआत

आईपीके, जौनपुरः बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत सितम्बर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह 01 सितम्बर से शुरु होकर 30 सितम्बर तक चलेगा। राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कलेक्ट्रेट से रैली निकाल कर की गई। रैली को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं ने भाग लिया।

राष्ट्रीय पोषण माह की थीम 'सशक्त, सबल नारी, साक्षर बच्चा, स्वस्थ भारत' है। राष्ट्रीय पोषण माह में 05 विभागों बाल-विकास, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, खाद्य एवं रसद तथा ग्राम विकास विभाग द्वारा मिलकर काम किया जाएगा। इस माह पोषण पंचायत, पोषण वाटिका का निर्माण, स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा, गृह भ्रमण, सामुदायिक

गतिविधि का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह में महिला एवं स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा-पोषण भी पढ़ाई भी, लैंगिक संवेदनशीलता जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत 25 सितम्बर से 30 सितम्बर तक जन सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। जनपद में सभी 5,321 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सितम्बर माह में प्रत्येक दिन स्वास्थ्य एवं पोषण से सम्बन्धित कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. आर.बी. सिंह, तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी नगर-जौनपुर मनोज कुमार वर्मा उपस्थित रहे।

भाजयुमो ने मनाया 'एक साल सफल कार्यकाल' कार्यक्रम

आईपीके, मिर्जापुरः शहर के लालडिग्गी स्थित राजश्री पैलेस के सभागार में भारतीय जनता युवा मोर्चा मिर्जापुर के द्वारा 'एक साल सफल कार्यकाल' का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम युवा मोर्चा मिर्जापुर के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रखा गया था, जिसके मुख्य अतिथि नगर विधायक रत्नाकर मिश्र व भूपत मिश्र रहे।

कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि द्वारा भारत माता व मां विंध्यवासिनी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ मिश्रा 'मोंटी' ने मुख्य अतिथि व वरिष्ठ भाजपा नेताओं को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी युवा मोर्चा राजेश सिंह व उनके पदाधिकारी महामंत्री पुष्पेंद्र द्विवेदी, जिला मीडिया प्रभारी आशीष मिश्र, जिला मंत्री शशांक दुबे, जिला मंत्री शशांक जैन, अनुराग दुबे, सह मीडिया प्रभारी, जिला मंत्री रोहित त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष अभिनव सिंह, जिला मंत्री नगर पूर्वी

अध्यक्ष आकाश गुप्ता, नगर पश्चिमी अश्वनी गुप्ता, विनानी डिग्री कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष अंशुमालि मिश्रा, के.बी. कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष प्रवीण दुबे, छात्रसंघ महामंत्री शिवा पाण्डेय, पूर्व महामंत्री अतुल गुप्ता, विशाल दुबे, रत्नेश यादव, संदीप तिवारी, नगर मंत्री उत्कर्ष मिश्र, मृतुंजय सिंह, अमरेश केशरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने पूरी भाजपा युवा मोर्चा की टीम को शुभकामनाएं व बधाई दीं। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रबि पाण्डेय, जिला मंत्री हेमंत त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी, नगर अध्यक्ष पूर्वी मनीष गुप्ता, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष निर्मला राय, नगर महामंत्री श्याम सिंह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थित होकर युवा मोर्चा टीम का मार्गदर्शन करते हुए निरन्तर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। एक वर्ष पूर्व जब भारतीय जनता युवा मोर्चा को नया जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ मिश्र के रूप मिला, तो युवा वर्ग में जोश आ गया। स्थानीय निकाय व विधानसभा का चुनाव भाजयुमो जिलाध्यक्ष के लिए एक चुनौती के रूप मिला। मिर्जापुर जिले का विधानसभा चुनाव परिणाम जहां बीजेपी व उसके सहयोगी दलों को मिला, वहीं विरोधी दलों का तो सूपड़ा ही साफ हो गया। युवा मोर्चा की टीम ने गांवों, शहर के हर मोहल्ले में जाकर सरकार की लोकप्रिय, लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसका सारा श्रेय भारतीय जनता युवा मोर्चा टीम को मिला।

अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताः जिलाधिकारी

आईपीके, झांसीः जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आई.टी.आई. में आयोजित वृहद रोजगार मेले का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को देखा। रोजगार मेले का निरीक्षण करते हुए बताया कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है और उनके द्वारा विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान आमंत्रित 20 कम्पनियों के प्रतिनिधियों से वार्ता की एवं चयनित अभ्यर्थियों, उनके वेतन एवं कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी ली।

जिलाधिकारी ने विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों से कहा कि संवेदनशील होकर साक्षात्कार लेना सुनिश्चित करें, ताकि खुशनुमा माहौल में अभ्यर्थी आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। रोजगार मेले के दौरान क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी हिमांशु यादव द्वारा अवगत कराया गया कि अभी तक लगभग 250 अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने 1,000 अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान किए जाने के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्षेत्रीय

- डीएम द्वारा किया गया रोजगार मेले का निरीक्षण

सेवायोजन अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने यह भी देखा कि रोजगार मेला में काफी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसके कारण अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसे जल्द ही व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रधानाचार्य आई.टी.आई. के लिए निर्देश दिए कि मेले का ले-आउट तैयार करके मेले को सुनियोजित ढंग से आयोजित किया जाए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान यह भी पाया कि आई.टी.आई के वर्कशॉप में जगह-जगह गंदगी व्याप्त है, बैंच/टेबिल रखी हुई है एवं वॉटर कूलर के पास अत्यधिक पानी फैला हुआ है, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि प्रधानाचार्य आई.टी.आई. का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अंकुर श्रीवास्तव, सेवायोजन अधिकारी हिमांशु यादव, सहायक सेवायोजन अधिकारी वसीम मोहम्मद एवं कार्यदेशक, आई.टी.आई. उपस्थित रहे।

बुंदेलखण्ड को मिली ओडीओपी की सौगात

आईपीके, झांसीः सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हाल ही में हुई हाई पावर्ड कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें मुलायम खिलौने एवं वस्त्र उद्योग को जनपद के लिए एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। यह जानकारी व्यापारी नेता एवं भाजपा कानपुर बुंदेलखण्ड क्षेत्र लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक पुनीत अग्रवाल ने दी। उन्होंने इसे बुंदेलखण्ड क्षेत्र के कपड़ा उद्योग के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि रानीपुर और आस-पास इस वस्त्र उद्योग से जुड़े लोगों के दिन बहुरेंगे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले यह मांग जिला उद्योग बंधु की बैठक में उठाई थी, फिर मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक के बाद जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्त के साथ-साथ सदर विधायक रवि शर्मा, महापौर रामतीर्थ सिंघल, सांसद अनुराग शर्मा, प्रदेश के उद्योग मंत्री नंदगोपाल नंदी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता आदि ने अपने स्तर से इस मांग को आगे बढ़ाया। अंततः इस मांग को सरकार की मंजूरी मिल गई। सांसद अनुराग शर्मा ने आगे बताया कि यह एकमात्र ऐसी योजना है, जिससे जनपद में उद्यमियों सहित व्यापारियों, बुनकरों को लाभ मिलेगा तथा नए उद्योग स्थापित होंगे।

नैक ग्रेडिंग में टॉप रैंकिंग के लिए अच्छा प्रतिवेदन तैयार करेंः प्रो. गुप्ता

मुक्त विश्वविद्यालय में पीपीआर पर हुई कार्यशाला

आईपीके, प्रयागराजः उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के शिक्षक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के तत्वावधान में शुक्रवार 02 सितम्बर को कार्यक्रम परियोजना प्रतिवेदन विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के मुख्य वक्ता आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चियन प्रकोष्ठ सीका के निदेशक प्रोफेसर आशुतोष गुप्ता ने प्रतिभागियों को प्रोग्राम प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीपीआर की अवधारणा से अवगत कराया।

प्रोफेसर गुप्ता ने पीपीआर में समाहित बिंदुओं की समझ विकसित करने के लिए पीपीटी के माध्यम से नई शिक्षा नीति के परिपेक्ष्य में जानकारी दी। उन्होंने नैक ग्रेडिंग में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए एक अच्छा प्रतिवेदन तैयार करने के विविध पक्षों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रोफेसर पी.पी. दुबे, समन्वयक, शिक्षण प्रशिक्षण प्रकोष्ठ ने प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन डॉ. श्रुति एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर विनोद कुमार गुप्ता, संयोजक, शिक्षण प्रशिक्षण प्रकोष्ठ ने किया। इस अवसर पर अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए निदेशक प्रबंधन अध्ययन प्रोफेसर ओमजी गुप्ता ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की विशेषताओं की अवधारणा पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में प्रोफेसर गिरिजा शंकर शुक्ल, प्रोफेसर सत्यपाल तिवारी, प्रोफेसर रुचि बाजपेई, प्रोफेसर छत्रसाल सिंह, डॉ. आनंदानंद त्रिपाठी, डॉ. देवेश रंजन त्रिपाठी आदि शिक्षक प्रतिभागी उपस्थित रहे।

किराये से भी कम EMI पर लखनऊ में खरीदें अपने सपनों का घर

Member CREDAI

माधव रेजीडेन्सी

खुशियों का रास्ता....

निकट- किसान पथ, चिनहट, लखनऊ

1 BHK EMI ₹15,500/- से शुरू*

2 BHK EMI ₹23,000/- से शुरू*

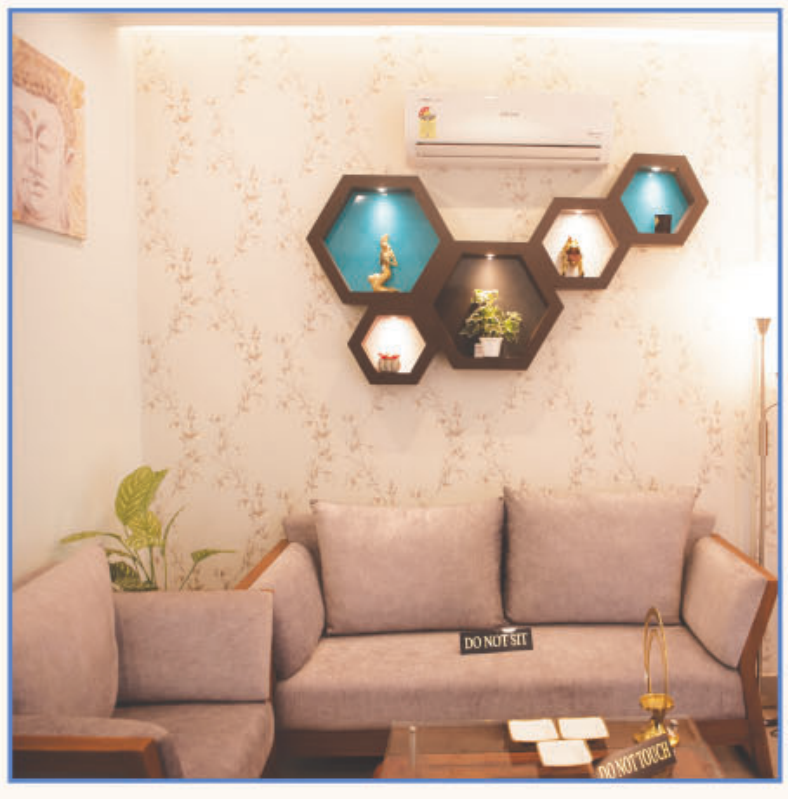

होम लोन उपलब्ध

SBI | pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon ! | केनरा बैंक Canara Bank | ICICI Bank Business Banking | Punjab & Sind Bank | Bank of India Relationship beyond banking | बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

Disclaimer: Loans at Sole Discretion of Banks

ARSHA INFRA DEVELOPERS PVT. LTD.

RERA Reg.No:- UPRERAPRM2725

ARSHA INFRA DEVELOPERS PVT.LTD.

Corporate Office:- Kamdhenu 2/169, Railway Station road, Vivek Khand, Gomti Nagar, Lucknow, U.P.-226010

Mobile No:- 9513355582

Strategic Partner ANAROCK RESIDENTIAL

ANAROCK RERA No. UPRERAAGT10265

Website: www.arshainfra.com, E-mail:info@arshainfra.com

* शर्त लागू

महिलाओं-बच्चों के लिए यूपी सबसे अधिक सुरक्षित

एनसीआरबी ने जारी किए अपराध के आंकड़े, साइबर क्राइम में आई 22 फीसदी की गिरावट

आईपीके, लखनऊः देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति और साइबर अपराध में बढ़ोत्तरी के विपरीत यूपी में 2019 की तुलना में 2021 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपराधिक मामलों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं और बच्चों के लिए यूपी देश का सबसे सुरक्षित राज्य माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 56,083 और बच्चों के खिलाफ अपराध के 16,838 मामले ही दर्ज किए गए। साइबर अपराध के मामलों में यह संख्या 8,829 है। बात अगर 2019 में दर्ज आंकड़ों की हो, तो इस साल की तुलना में तीनों श्रेणियों में गिरावट दर्ज की गई है। अपराधों की तुलना 2019 से की गई है, जो 2020 के विपरीत एक सामान्य वर्ष था। 2020 में लॉकडाउन के कारण अपराध दर में तेज गिरावट देखी गई। एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों के अनुसार, देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.28 लाख से अधिक मामले और बच्चों के खिलाफ अपराध की 1.49 लाख घटनाएं दर्ज की गईं। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध के कम से कम 52,974 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि वर्ष 2019 में इन्हीं श्रेणियों में यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.05 लाख मामले व बच्चों के खिलाफ 1.48 लाख मामले दर्ज हुए। इसी तरह साइबर क्राइम में भी वर्ष 2019 में 44,735 मामले ही दर्ज हुए थे। यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर समान श्रेणियों में 2019 में दर्ज हुए अपराधों से तुलना करते हैं, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगभग 5.66 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। बच्चों के खिलाफ अपराध में लगभग 0.88 फीसदी की वृद्धि और साइबर अपराधों में लगभग 18.41 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, तीनों श्रेणियों में यूपी के आंकड़े बेहतर स्थिति में हैं। 2021 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 56,083 और बच्चों के खिलाफ अपराध के 16,838 मामले दर्ज किए गए। साइबर अपराध के मामलों की संख्या 8,829 थी। महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगभग 6.3 फीसदी की कमी दर्ज की गई और बच्चों के खिलाफ अपराध में 11.11 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। साइबर अपराध के मामलों में 22.67 फीसदी की गिरावट आई है।

दोषियों को सजा दिलाने के मामले में यूपी अव्वल

प्रभावी पैरवी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों की तुलना में दोषियों को दोगुनी संख्या में सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में 59.1 प्रतिशत की दर से दोषियों को सजा दिलाई गई। यह देश में सजा दिलाने के औसत 26.6 प्रतिशत से दोगुने से अधिक है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में यूपी में पूरे देश के मुकाबले सर्वाधिक 7,713 मामलों में आरोपितों को सजा दिलाई गई। यह अन्य सभी राज्यों में सजा कराए गए 22,874 मामलों का दो तिहाई है। दूसरे स्थान पर राजस्थान में 4,180 आरोपितों को सजा दिलाई गई।

राज्य सरकार के प्रयासों से आई अपराध में गिरावट

एनसीआरबी के आंकड़ों पर एडीजी कानून और व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि 2017 से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए महिला पावरलाइन को मजबूत किया गया है और यूपी 112 से जोड़ा गया है। हमने छेड़खानी करने वाले तत्वों की धर-पकड़ के लिए एंटी रोमियो दस्ते भी तैनात किए हैं। एडीजी ने कहा कि यूपी के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। राज्य स्तर पर एक समर्पित साइबर सेल का गठन किया गया है, जबकि साइबर अपराध के लिए 18 पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे, जबकि साइबर अपराध के लिए पुलिस को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

बच्चों के खिलाफ अपराध

वर्ष	राष्ट्रीय स्तर पर	यूपी के आंकड़े
2019	1,48,090	18,943
2021	1,49,404	16,838 (-11.11फीसदी)

महिला अपराध

वर्ष	राष्ट्रीय स्तर पर	यूपी के आंकड़े
2019	4,05,326	59,853
2021	4,28,278	56,083 (-6.30 फीसदी)

साइबर मामले

वर्ष	राष्ट्रीय स्तर पर	यूपी के आंकड़े
2019	44,735	11,416
2021	52,974	8,829 (-22.66 फीसदी)

मानव मूल्यों की समझ है सबसे बड़ी शिक्षा : आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल ने शिक्षक दिवस पर 10वीं की छात्राओं को दी छात्रवृत्ति

लखनऊः प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार 05 सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राजधानी के इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 75 छात्राओं को 10,000 रुपये की एकमुश्त छात्रवृत्ति का वितरण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल ने महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मरण किया और कहा कि मानव-मूल्यों की समझ जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है।

राज्यपाल ने कहा कि विश्व में ऐसे अनेक महापुरूष हुए हैं, जिन्होंने कभी विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की लेकिन समाज में बड़े आदर्श मूल्यों की स्थापना की। उन्होंने कहा कि विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। प्रधानाध्यापक से लेकर सफाई कर्मचारी तक विद्यालय की नियमित व्यवस्था में अहम् भूमिका निभाते हैं। इसलिए शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के साथ-साथ विद्यालय के अन्य कार्यों में लगे कर्मचारी भी सम्मान के पात्र हैं। राज्यपाल ने कहा कि गुरु का ये दायित्व है कि वह अपने शिष्य की शिक्षा के साथ-साथ उसके सामाजिक, मानसिक और स्वास्थगत विकास का भी ध्यान रखें। गुरु का कार्य देश को स्वस्थ, शिक्षित और सभ्य नागरिक देना है। इसी क्रम में राज्यपाल ने स्कूलों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य जांच को आवश्यक बताते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों की स्वास्थ्य जांच आवश्यक है। उन्होंने कार्यक्रम में आई कुछ छात्राओं के दुर्बल स्वास्थ्य को लक्ष्य करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को उचित पोषण और सही स्वास्थय की जानकारी देनी चाहिए। यहां बताते चलें कि इण्डियन ऑयल द्वारा आयोजित अपनी मेधा छात्रवृत्ति योजना, 2022 के अंतर्गत यूपी वोर्ड की 10वीं कक्षा की मेधावी छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए आयोजित इस समारोह में प्रदेश के विभिन्न स्कूलों की बालिकाएं अपने शिक्षकों के प्रतिनिधित्व में समारोह में आईं। राज्यपाल ने छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में अपनी शिक्षा को अधूरा न छोड़ें, लगन और निरन्तर परिश्रम से ही जीवन में सफलता प्राप्त होगी। राज्यपाल ने समारोह में बालिकाओं को छात्रवृत्ति के प्रतीकात्मक चेक के साथ प्रशस्ति पत्र और एक स्कूल बैग प्रदान किया। समारोह में इण्डियन ऑयल कारपो-रेशन के कार्यकारी निदेशक एवं स्टेट हेड संजीव कक्कड़ ने बालिकाओं का उत्साहवर्द्धन करते हुए प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उनके लिए सफलता का एक जीवंत उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला राज्यपाल सभी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने राज्यपाल की प्रेरणा से बालिकाओं को इण्डियन ऑयल के डिपो टर्मिनल में भ्रमण के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम में वाराणसी घराने से अनुज अर्जुन डांस कम्पनी द्वारा 105 चक्र का मनोहारी कथक नृत्य प्रस्तुत किया गया।

'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों से गूंज रहा शहर

- भव्य पंडालों की छटा देखकर भाव-विभोर हो रहे श्रद्धालु
- देर रात तक भक्ति गीतों से हो रहे सराबोर

आईपीके, लखनऊः इन दिनों लम्बोदर महाराज और गजानन भगवान के जयकारे शहर की तमाम बस्तियों में सुने जा रहे हैं। चारों ओर भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। सुबह-शाम पंडालों में गजानन की आरती के साथ घंटे-घड़ियाल की धुन गूंज रही है। तमाम स्थलों पर जागरण का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां देर रात तक श्रद्धालु गणपति बप्पा के भजनों में सराबोर होकर भक्ति रस में डुबकी लगा रहे हैं।

शहर में इस बार भी गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। सबसे खास आकर्षण मवैया आलमबाग का है। यहां हर साल की तरह विशाल पंडाल लगाया गया है, जिसमें भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा विराजमान है। शाम से ही यहां की रौनक चौराहे तक बिखरी रहती है। हजारों की संख्या में पहुंच रही महिलाएं पहले मेले में खरीदारी करती हैं और फिर यहां भजन प्रस्तुत करने वाले कलाकारों का उत्साह बढ़ाती हैं। कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को खूब लुभाते हैं। पिछले दिनों बुंदेलों की कथा को कलाकारों ने कठपुतलियों के माध्यम से दिखाया, तो दर्शक भी झूम उठे। सुबह यहां आरती की जाती है। यह आयोजन दस दिनों का है। कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी देख रहे विजय गुप्ता ने बताया कि यहां प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दस दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं।

पारा क्षेत्र के यादव चौराहा और बालकृष्णनगर में भी भव्य पंडाल सजाया गया है। यहां बैठे गजानन की पूजा करने के लिए भक्त देर रात तक पहुंचते रहते हैं। आरती के बाद प्रसाद वितरण होता है। इसके बाद महिलाएं ढोल और मजीरे के साथ सुर मिलाती हैं। आरती कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। खास बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इस पंडाल को लगाने में काफी सहयोग किया है। अताउल्ला यहीं के निवासी हैं। वह कहते हैं कि उन्हें ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में मदद से काफी आनंद मिलता है। आशियाना, राजाजीपुरम, आलमबाग, मानकनगर, पारा, आरडीएसओ, इंदिरानगर, डालीगंज और विकास नगर के अलावा पुराने लखनऊ में तमाम जगहों पर इन दिनों गणपति बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। गोमतीनगर के पत्रकारपुरम चौराहे पर पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे देखकर लोग अपलक नेत्रों से निहारते ही रहते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा भव्य पंडाल भी सजाया गया है। शाम 07 बजे यहां पर गणपति बप्पी के आरती में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इसके बाद जागरण कलाकारों द्वारा भक्तिमय गीतों की प्रस्तुतियां दी जाती हैं, जिसमें देर रात 12 बजे तक श्रद्धालु भक्ति रस में गोता लगाते रहते हैं। संचालन व्यवस्था देख रहे रमेश अग्रवाल कहते हैं कि पंडाल के अंदर और बाहर श्रद्धालुओं के बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। हर साल की तरह ही इस वर्ष भी गणेश जी की सबसे भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। यहां दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।

कई स्थानों पर हुआ गणपति बप्पा का विसर्जन

ऐशबाग जल संस्थान कॉलोनी की ओर से आयोजित श्रीगणेश महोत्सव की प्रतिमा की रविवार 04 सितम्बर को विदाई कर दी गई। भक्तों ने गाजे-बाजे के साथ विसर्जन यात्रा निकाली और गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आना' की पुकार के साथ विदा किया। प्रतिमा विसर्जन से पूर्व पंडित ललित मिश्रा ने मंगलमूर्ति का वैदिक मंत्रोच्चार से हवन एवं पूजन किया। भक्तों के हाथों में रक्षासूत्र बांध यजमान जनों ने प्रसाद वितरित किया और इसके बाद भंडारा भी आयोजित हुआ। उपेन्द्र पांडेय के नेतृत्व में विसर्जन शोभा यात्रा में गणेश प्रतिमा को फूलों की मालाओं एवं सिंदूर से अलौकिक श्रृंगार करके वाहन पर रखा गया, ढोल-नगाड़े की धुनों एवं गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आना के जयकारे के बीच भगवान गणेश को रंग-गुलाल वर्षा करते हुए भक्तजन झूमते-नाचते हुए कुड़िया घाट विसर्जन स्थल के लिए निकल पड़े। कुडिया घाट विसर्जन स्थल पर धूमधाम से गणेश प्रतिमा का विसर्जन करके सभी के लिए सुख समृद्धि की मनोकामना मंगलमूर्ति से की।

बिना नम्बर प्लेट शहर में घूम रहीं निगम की कचरा गाड़ियां

यातायात नियमों का जमकर उड़ा रहीं माखौल

आईपीके, लखनऊः राजधानी में घर-घर कूड़ा इकट्ठा करने वाली नगर निगम की कूड़ा गाड़ियां यातायात नियमों का जमकर माखौल उड़ा रही हैं। अधिकतर कूड़ा गाड़ियां बिना नम्बर प्लेट के ही शहर की सड़कों पर फर्राटा भर रही हैं, पर प्रशासनिक जिम्मेदार मूकदर्शक बने हुए हैं।

देश में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो चुका है और इसके लागू होने के बाद वाहन चालकों के मन में चालान को लेकर डर व्याप्त है, लेकिन नगर निगम के कूड़ा वाहनों पर कोई नियम लागू होता नजर नहीं आ रहा है। निगम के कई कूड़ा वाहन बिना नम्बर प्लेट के ही सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे हैं, जबकि तीन महीने पहले वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस मुद्दे को तुरंत हल करने का आश्वासन दिया गया था। यही नहीं तमाम वाहनों का यातायात विभाग में पंजीकरण भी नहीं हुआ है, ऐसे में यह नियमों की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं और दुर्घटना का सबब भी बन रहे हैं। अलीगंज, महानगर, हजरतगंज, गोमतीनगर, इंदिरानगर, पुराने लखनऊ और अन्य सड़कों पर ऐसे कई वाहन दौड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि एलएमसी या यहां तक कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर ऐसे वाहन वर्षों से इधर-उधर घूम रहे हैं। अलीगंज निवासी रमेश चन्द्र का कहना है कि सारे नियम आम जनता के लिए ही हैं। जनता यातायात के नियमों का गलती से भी उल्लघंन कर दे, तो भारी-भरकम जुर्माना लग दिया जाता है लेकिन यह वाहन धड़ल्ले से बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। इन्हें कोई रोक भी नहीं रहा है और न ही यातायात विभाग इन पर जुर्माना ही लगा रहा है। नम्बर न होने के कारण कोई इनकी शिकायत भी नहीं कर सकता है।

इंदिरा नगर के रहने वाले अमित सिंह का कहना है कि यदि इन वाहनों से कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इसकी शिकायत कैसे की जाएगी। यातायात विभाग पूरी तरह से निरंकुश हो चुका है। कुछ ड्राइवरों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उनकी गाड़ी में ही नहीं, बल्कि नगर निगम की ज्यादातर गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं लगी हैं। ऐसे में हम लोग ही क्यों नंबर प्लेट लगाएं। इसके अलावा अन्य चालकों ने बताया कि उन्हें जैसी गाड़ी दी गई है, वे वैसी ही तो चलाएंगे। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि नगर आयुक्त द्वारा पिछले दिनों कहा गया था कि हर वाहन पर नम्बर प्रिंट करने के सख्त निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, लेकिन यह आदेश सिर्फ खानापूर्ति ही साबित हो रहा है। इसको लेकर यातायात उपायुक्त रईस अख्तर ने कहा कि हमने बिना नम्बर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ चालान जारी किया है। यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि सभी वाहनों पर नम्बर ठीक ढंग से लिखे हों।

जल्द बदली जाएगी कूड़ा निस्तारण करने वाली कम्पनी

देश के कई शहरों में कूड़ा आय का स्रोत बना रहा है, लेकिन राजधानी लखनऊ में यह लोगों के लिए अभिशाप बना हुआ है। सिर्फ कूड़ा उठाने में ही हर साल नगर निगम 50 से 60 करोड़ रूपए फूंक रहा है। बीते दिनों कई शहरों में कूड़े का प्रबंधन देख रही 18 कम्पनियों ने अधिकारियों के सामने कूड़े से आय करने वाले प्रोजेक्ट को सामने रखा। उन्होंने बताया कि कूड़े से सीएनजी, खाद और कोयला बनाया जा सकता है। मुम्बई की एक कम्पनी ने बताया कि वह कूड़े से बिजली बना रही है। नगर निगम में भी अब वर्तमान में कूड़ा निस्तारण करने वाली कम्पनी को जल्द बदलने की कवायद शुरू की जाएगी।

शिक्षा ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी बच्चों को मिले प्राथमिकता

- बच्चों के मन को पढ़ने की करनी चाहिए कोशिश
- गैजेट्स के अधिक प्रयोग से बढ़ रही हैं हिंसक घटनाएं

आईपीके, लखनऊः बदलते समय के साथ जिस तरीके से तकनीकी बढ़ती जा रही है, उसने हमारे जीवन जीने के तरीके को काफी आसान बना दिया है। बच्चों की पढ़ाई का तौर-तरीका भी अब लगभग पूरी तरह बदल गया है। गैजेट्स से घिरे बच्चे अब ऐसे-ऐसे कदम उठा रहे हैं, जिसे देख कर हर कोई हैरान है। पिछले दिनों कई किशोरों द्वारा हत्या जैसे जघन्य अपराध की घटना को अंजाम देने के बाद लोगों की चिंताएं काफी अधिक बढ़ गई हैं। इसी को लेकर **इंडिया पब्लिक खबर** के **संवाददाता पवन सिंह चौहान** ने शहर के मनोचिकित्सकों व लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से बातचीत की और उनसे इसके कारणों, निदान व अभिभावकों की भूमिका को लेकर जानकारी प्राप्त की।

केजीएमयू के मनोचिकित्सक डॉ. आदर्श त्रिपाठी का कहना है कि एक समाज के तौर पर हमारा यह सोचना और मानना अनिवार्य है कि सभी में अलग-अलग विशेषताएं और प्रतिभाएं होती हैं। किसी की आर्ट अच्छी है, तो कोई किसी विषय में टॉप कर रहा है। कोई खेल में अव्वल है, तो कोई संगीत का जादूगर है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में सभी के लिए मौके हों, ऐसा सिस्टम तैयार होना चाहिए। आज की शिक्षा व्यवस्था में जो बच्चे पढ़ाई में अव्वल होते हैं उन्हीं को ज्यादा मान्यता मिलती है, बाकियों को कमजोर और सम्मानित भाव से नहीं देखा जाता। बहुत से बच्चे समाज और विद्यालय के द्वारा अनदेखी, अपमानित होने पर निराश हो जाते हैं। इस कमी को समाज को दूर करना चाहिए और पढ़ाई के अलावा बच्चों को दूसरे क्षेत्रों में भरपूर अवसर मिलने चाहिए। डॉ. त्रिपाठी का मानना है कि जब किशोर अवस्था में बच्चे निराश होते हैं, तो वह अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार बहुत दूर की नहीं सोच पाते हैं। वह अपनी परेशानी का हल चाहते हैं, उसका परिणाम क्या होगा, वह इसके बारे में विचार नहीं कर पाते। अपनी समस्याओं का वह शॉर्ट टर्म हल ढूंढते हैं। इसके अलावा मीडिया, गेम और फिल्मों में बड़ी से बड़ी हिंसा को बहुत ही सामान्य तौर पर दिखाया जाता है। इससे बच्चों में हिंसा के प्रति सोच बदल जाती है और वह हिंसा को सामान्य व्यवहार के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं।

केसः 1

01 जून 2022- अयोध्या में गर्भवती शिक्षिका की हत्या के आरोप में 17 वर्षीय किशोर गिरफ्तार।

केसः 2

22 अगस्त 2022 - मेरठ में कक्षा 10वीं के छात्र ने दोस्त की हत्या कर दी, क्योंकि वह स्कूल जाने से बचना चाहता था।

केसः 3

11 जुलाई 2022- बुलंदशहर में घर से बुलाकर कक्षा दस के छात्र की दोस्तों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी।

बच्चों में दिखे ऐसा व्यवहार, तो हो जाएं सतर्क

अगर बच्चे के व्यवहार में अचानक कोई बड़ा बदलाव दिखाई दे, जैसे- बच्चा सबसे जल्दी न घुले-मिले और अकेले समय ज्यादा बिताने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए कि बच्चे की स्थिति सामान्य नहीं है। इसके अलावा जल्दी झुंझलाना, चिड़चिड़ापन, सामान्य सी बात को भी मानने से इंकार करने या उसका उल्टा करने, नशे की तरफ रूझान आदि लक्षण दिखते ही सतर्क हो जाना चाहिए।

रूचि और क्षमता को पहचानें

परिवार को बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात नहीं करनी है, बल्कि उसे पसंद आने वाली एक्टिविटी के साथ भी उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बच्चे की रूचि और क्षमता आपके अनुरूप हो, ऐसी स्थिति में बच्चे की क्षमता और रूचि को पहचानने की जरूरत है न कि किसी प्रकार के ताने देने की या पड़ोस के किसी बच्चे से उसकी तुलना करने की। इसी प्रकार का माहौल परिवार और समाज को बच्चे को देना चाहिए। सभी बच्चे क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकते, सभी बच्चे खेल में अव्वल नहीं हो सकते, इसलिए बच्चे को उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाते हुए बच्चे का पालन-पोषण करना चाहिए।

हर विद्यालय में हो एक काउंसलर

हर एक स्कूल में चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी सभी स्कूलों में एक कांउसलर अनिवार्य तौर पर होना ही चाहिए। अब तो सरकार ने भी इसे अनिवार्य कर दिया है। निजी स्कूलों में तो काउंसलर रखने की शुरूआत हो भी चुकी है। बच्चे और उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए काउंसलर बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं। अगर किसी बच्चे के व्यवहार में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, तो स्कूल में इसको पहचानना आसान होता है। शिक्षक व सहपाठी आदि भी काउंसलर की इसमें मदद कर सकते हैं। बच्चा अपने सहपाठियों के सामने बहत जल्दी खुल जाता है और उसका बदला हुआ व्यवहार सबसे पहले उन्हीं के सामने आता है।

विशेषज्ञों की सुनिए

- इस तरह का हिंसात्मक कदम अगर कोई बच्चा उठा रहा है, तो यह सामान्य बात नहीं है। हो सकता है कि बच्चे को कोई पहले से मानसिक दिक्कत हो, जिसको परिवार नहीं देख सका। बच्चा सही और गलत की पहचान ही नहीं कर पा रहा है। बहुत से बच्चे आपको मिल जाएंगे, जो पढ़ना नहीं चाहते, स्कूल नहीं जाना चाहते लेकिन मां-बाप उन्हें जबरदस्ती स्कूल भेज रहे हैं। ऐसे में सभी बच्चे तो हत्या करने जैसा कदम नहीं उठाते, लेकिन अभिभावकों को खासकर बच्चे के हाव-भाव पर ध्यान देना चाहिए।

डॉ. अभिनव पांडेय, मनोचिकित्सक, लखनऊ

- कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले छात्र द्वारा एक नाबालिग लड़के की हत्या की यह घटना किशोरों में बढ़ते आवेग, आत्मकेंद्रितता, कम भावनात्मक बुद्धिमत्ता, माता-पिता-बच्चे से जुड़ाव की कमी को दर्शाता है। किशोरावस्था अपने आप में पहचान संकट और भावनात्मक उथल-पुथल (एरिकसन) का युग है, इसके लिए बहुत धैर्य, सम्वेदनशीलता, खुले संचार और स्मार्ट हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। अनुशासन और स्नेह के बीच संतुलन बनाए रखते हुए बच्चों का पालन-पोषण करना चाहिए।

डॉ. मानिनी श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय

- परिवार को बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई के बारें में ही नहीं, बल्कि बच्चे के पसंद की एक्टिविटी के साथ उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बच्चे की रूचि और क्षमता आपके अनुरूप हो, ऐसी स्थिति में बच्चे की क्षमता और रूचि को पहचानने की जरूरत है न कि किसी प्रकार के ताने देने की।

डॉ. आदर्श त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, केजीएमयू

छह पीपीएस और सात जिलों के सीएमओ बदले

लखनऊः उत्तर प्रदेश में लगातार तबादले हो रहे हैं। राज्य सरकार ने शुक्रवार 02 सितम्बर को सात जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) और छह पीपीएस अफसरों का स्थानान्तरण किया है। इससे पहले 10 पुलिस उपाधीक्षकों को तबादला हुआ था। शासन की ओर से किए गए तबादले में निष्ठा उपाध्याय को पुलिस उपाधीक्षक एनटीएफ गोरखपुर बनाया गया है। इनके अलावा शैलेंद्र सिंह परिहार पुलिस उपाधीक्षक कासंगज से हटाकर पुलिस उपाधीक्षक एनटीएफ मेरठ, राजकुमार त्रिपाठी को सोनभद्र से एनटीएफ वाराणसी, इरफान नासिर खान को एटा से एनटीएफ आगरा, राजवीर सिंह गौर को फतेहगढ़ से एनटीएफ मुख्यालय लखनऊ और अमर बहादुर को एनटीएफ मुख्यालय लखनऊ भेजा गया है। पीपीएस अफसरों के तबादले के बाद स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल हुआ है। शासन ने सात जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी का तबादला किया गया है। इनमें डॉ. नरेश अग्रवाल को मऊ भेजा गया है। संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कानपुर मंडल से डॉ. रामकिशोर गौतम को मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर, डॉ. गीताराम को मुख्य चिकित्साधिकारी इटावा बनाया गया है। डॉ. राजेश कुमार तिवारी को हरदोई का मुख्य चिकित्साधिकारी, डॉ. अवधेश कुमार यादव को बाराबंकी का मुख्य चिकित्साधिकारी, डॉ. राजेश झा देवरिया का मुख्य चिकित्साधिकारी और डॉ. रूद्र प्रसाद मिश्रा को बस्ती का मुख्य चिकित्साधिकारी बनाया गया है।

नेडा और वेंडरों की खींचतान में फंसे सोलर पैनल आवेदक

आठ माह बाद भी वेंडर व रेट नहीं तय कर सका नेडा, वेंडरों के चयन की टेंडर प्रक्रिया भी नहीं कर सका पूरी

आईपीके, लखनऊः सोलर पैनल आवेदकों पर यूपी नेडा (उप्र नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण) और वेंडरों की आपसी खींचतान भारी पड़ रही है। इसके चलते आवेदकों के सोलर पैनल आवेदन के साथ उनकी सब्सिडी भी अटकी हुई है। वेंडरों का चयन न होने से आवेदकों को यह जानकारी ही नहीं मिल पा रही है कि वह पैनल किससे लगवाएं, साथ ही उन्हें यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी एजेंसी नेडा से अनुबंधित है और कौन नहीं। इसके अलावा अगर वह किसी एजेंसी से सोलर पैनल लगवा लेते हैं, तो उन्हें सब्सिडी मिलेगी अथवा नहीं।

बीते कई माह से सोलर पैनल लगवाने के इच्छुक आवेदक इसी उधेड़बुन में फंसे हुए हैं, वहीं जिन लोगों ने इस दौरान सोलर पैनल लगवा लिया है, उनका सब्सिडी मिलने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। केंद्र सरकार की पहल पर ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगवाने के इच्छुक लोगों के लिए सेंट्रलाइज व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत सोलर पैनल के आवेदन के लिए एक पोर्टल तैयार कराया गया, साथ ही सोलर पैनल लगवाने पर मिलने वाली सब्सिडी को सीधे आवेदक के खाते में भेजने की भी व्यवस्था बनाई गई, बावजूद इसके यूपी नेडा न तो वेंडरों का चयन कर पाया और न ही सब्सिडी की दरें तय कर सका। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग चाह कर भी ऑन ग्रिड सोलर प्लांट नहीं लगवा पा रहे हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रूफटॉप सोलर प्लांट योजना का फेज-2 बीते करीब 08 माह पूर्व शुरू हुआ था। हालांकि, आठ महीनों बाद भी लोग इस सुविधा से वंचित हैं। जानकारी के अनुसार योजना में वेंडरों के चयन के लिए यूपी नेडा ने बीते वर्ष नवम्बर से टेंडर प्रक्रिया शुरू करवाई थी, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो सकी। हाल ही में फिर से टेंडर निकाला जाना सुनिश्चित किया गया था, मगर फिर से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है। विभागीय सूत्रों की मानें तो यूपी नेडा और वेंडरों के बीच चल रही खींचतान के चलते टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। बीते 29 अप्रैल को यूपी नेडा ने करीब 70 एजेंसियों की सूची और सब्सिडी की दर को वेबसाइट पर अपलोड किया था, हालांकि इस सूची को कुछ दिनों बाद ही हटा लिया गया।

नेशनल पोर्टल भी नहीं हुआ शुरू

केंद्र सरकार के निर्देश पर ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगवाने के लिए नेशनल पोर्टल बनाया गया था। आठ माह पूर्व बनाया गया यह पोर्टल भी अब तक शुरू नहीं हो सका है, वहीं यूपी नेडा के पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों के चलते सोलर पैनल के रजिस्टेशन नहीं हो पा रहे हैं। आवेदकों को विभागीय पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध होने की बात कही जा रही है, जबकि विभाग के पोर्टल पर न तो एजेंसी की जानकारी उपलब्ध है और न ही रेट ही तय किया गया है। जिन आवेदकों ने सब्सिडी दिलाने का दावा करने वाली एजेंसी से सोलर पैनल लगवा लिया, अब उन्हें यूपी नेडा की वेबसाइट पर सब्सिडी की जानकारी ही नहीं मिल पा रही है।

यूपीपीसीएल और नेडा की है जिम्मेदारी

प्रदेश में रूफटॉप सोलर प्लांट योजना के फेस टू के संचालन की जिम्मेदारी यूपी नेडा और उप्र पावर कॉर्पोरेशन की है। नेडा को जहां सोलर पैनल लगाने वाली एजेंसियों का चयन और सब्सिडी की दरें तय करना होता है, तो यूपीपीसीएल को नेट मीटरिंग की सुविधा शुरू करने के साथ पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी होती है। यूपीपीसीएल के अफसरों का कहना है कि वेंडरों के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया नेडा को पूरी करनी है। जानकारी मिली है कि टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में है और जल्द ही एजेंसियों के नाम की सूची पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

38 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य

अभी तक 2,200 शहरवासियों ने ऑनग्रिड सोलर पैनल लगवाया है, वहीं प्रदेश भर में करीब 4,500 की संख्या में ऑनग्रिड सोलर पैनल लग चुके हैं। सोलर प्लांट योजना फेज-2 में 38 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। इसके पूर्व सोलर प्लांट योजना से करीब 70 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया था। उल्लेखनीय है कि 01 से 03 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है, वहीं 03 किलोवाट से अधिक व 10 किलोवाट तक 20 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से हाउसिंग सोसाइटी के लिए 500 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने पर 20 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।

तीन जिलों में तेज चलते पाए गए 84 स्मार्ट मीटर

स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता पर एक बार फिर उठे सवाल

लखनऊः बिजली के स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। मध्यांचल डिस्कॉम के तीन जनपदों में स्मार्ट मीटर तेज चलने के साथ ही धीमी गति से भी चलते पाए गए। जांच में लखनऊ, बाराबंकी और बरेली में जहां 84 स्मार्ट मीटर तेज चलते पाए गए, तो वहीं 06 मीटर धीमी गति से चलते पाए गए। शिकायत मिलने पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस मामले में उ.प्र. पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक से 07 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

उपभोक्ता परिषद की ओर से नियामक आयोग में दायर याचिका में अवगत कराया गया कि 1911 स्मार्ट मीटर की जांच में खराब मीटरों की संख्या 4.7 प्रतिशत है। परिषद ने ईई-एसएल और घटिया स्मार्ट मीटर बनाने वाली कम्पनियों को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की मांग की। पावर कॉर्पोरेशन के नियमों के तहत दो प्रतिशत मीटरों में कमी सामने आने पर कम्पनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि करीब दो वर्षों बाद प्रदेश में फिर से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने शुरू हो गए हैं। वहीं दो वर्ष पूर्व जन्माष्टमी पर स्मार्ट मीटर में बत्ती गुल व भार जम्पिंग जैसे मामले सामने आ चुके हैं। जिसके बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना बंद कर दिया था। हालांकि, इस मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। लेसा में कुल 1,614 स्मार्ट मीटर की जांच की गई और इनमें से कुल 59 मीटर तेज चलते पाए गए, जबकि 06 मीटर धीमे चलते पाए गए। वहीं बाराबंकी जनपद में 47 व बरेली जनपद में 23 स्मार्ट मीटर की जांच की गई और इनमें क्रमशः 02 व 23 मीटर तेज चलते पाए गए। उल्लेखनीय है कि दो वर्ष बाद प्रदेश में एक बार फिर से 4जी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने शुरू हो गए। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा केस्को कानपुर में इसकी शुरूआत की गई है।

अनुबंधित बस योजना का निजी ऑपरेटर्स ने किया विरोध

खामियों को दूर करने के लिए एएमडी को सौंपा प्रस्ताव

आईपीके, लखनऊः परिवहन निगम की अनुबंधित बस योजना का निजी ऑपरेटर्स ने विरोध किया है। निजी ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने योजना से सम्बंधित सुझाव व प्रस्ताव भी निगम प्रबंधन को सौंपे हैं। बीते दिनों निगम मुख्यालय पर इस बाबत बैठक आयोजित की गई थी।

उप्र अनुबंधित बस ऑनर्स एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक राकेश बाजपेई ने बताया कि बैठक में बसों के अनुबंध की नई योजना की खामियों को संशोधित करने और पूर्व में संचालित बसों के संचालन में आ रही समस्याओं को अपर प्रबंध निदेशक डॉ. अन्नपूर्णा गर्ग के सामने रखा गया। परिवहन निगम की नई अनुबंधित बस योजना में 1,100 रिक्तियों के सापेक्ष सिर्फ 114 टेंडर पूरे प्रदेश में डाले गए हैं। नई अनुबंध योजना में प्रतिस्थापन का प्रस्ताव ही नहीं बनाया गया है, वहीं बस की प्रतिभूति राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। एसोसिएशन ने मांग की है कि पांच वर्ष पुरानी बसों को लगाए जाने के प्रस्ताव को समाप्त किया जाए। इसकी वजह यह है कि निगम बीएस 6 और एआरएआई अप्रूव्ड बॉडी की मांग कर रहा है, जबकि प्रदेश में ऐसा कोई वर्कशॉप ही नहीं है, जिसमें इस प्रकार की बॉडी बन सके। नई बस की कीमत 35 से 40 लाख रुपए है और पुरानी बीएस 3 बस 05 से 06 लाख रुपए में मिल जा रही है। ऐसे में पुरानी ही बसों को लगाने का प्रावधान किया जाना है, तो बीएस 6 मॉडल की पुरानी बसें लगाई जाएं। बसों का प्रशासनिक शुल्क 4.50 रुपए की जगह 7.50 रुपए कर दिया गया है। यह काफी अधिक है और इसे कम किया जाना चाहिए। एसोसिएशन के अध्यक्ष एसपी सिंह ने बताया कि 2016-17 में अनुबंधित बसों की संख्या जहां 3,200 के आस-पास पहुंच गई थी, तो वहीं निगम की गलत नीतियों और आर्थिक व मानसिक शोषण के चलते वर्तमान में यह संख्या 2,200 ही रह गई है। बसों का अनुबंध 10 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन अगर कोई छह साल में पुरानी बस हटाकर नई बस लगाना चाहता है तो उससे फिर शेष बचे चार साल का ही अनुबंध किया जाता है। इस व्यवस्था में संशोधन किया जाना चाहिए।

स्थापना दिवस पर भंडारे का आयोजन

लखनऊः कैसरबाग इलाके में अवध डिपो परिसर स्थित श्री सिद्ध कल्याणेश्वर महादेव मंदिर के 45वें स्थापना दिवस के मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन मंगलवार 30 अगस्त को किया गया। स्थापना दिवस में प्रमुख रूप से नागा अखाड़ा, संन्यासी अखाड़ा समेत अन्य अखाड़ों के साधु-संत शामिल हुए। स्थानीय लोग, अविधवक्तागण व बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मचारियों ने भी भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से भंडारे में पधारे सभी साधु-संतों को दान-दक्षिणा देकर विदा किया गया। इस दौरान मंदिर समिति के प्रबंधक एसएन सिंह, अध्यक्ष राकेश दीक्षित, मंत्री आशीष पांडेय, मंदिर के पुजारी राजा भइया, भाजपा के पूर्व महानगर संयोजक तुषार साहू, आरएस दीक्षित, राम कुमार सिंह, सुनील तिवारी, सुनील कुमार मेहरोत्रा, अनिल निगम, सुरेंद्र सिंह, निशाकांत सरोज बलदेव यादव समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे।

अब स्मार्ट सिटी के कार्यों की कदम-कदम पर होगी जांच

- विकास कार्यों की धीमी गति पर सख्त हुए नगर आयुक्त
- कार्यान्वयन समिति हर हफ्ते के काम की सौंपेगी रिपोर्ट

आईपीके, लखनऊः स्मार्ट सिटी योजना की रफ्तार इतनी धीमी है कि अब आला अधिकारियों को इसकी निगरानी खुद करनी पड़ रही है। निर्देश देकर थक चुके नगर आयुक्त ने बीते महीने बनाई गई कार्यान्वयन समिति को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस समिति से कहा गया है कि वह निर्माण स्थल पर जाकर हर सप्ताह के काम की समीक्षा करें और उसकी गति बढ़ाने के लिए कार्यदाई संस्था को बाध्य करें।

कार्यान्वयन समिति का गठन इसलिए किया था, ताकि वह अपनी रौ में रहे। इसके बाद भी महीनों बीत चुके हैं और संस्था अपना काम नहीं कर पा रही हैं। जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के लिए भी अधूरे काम परेशानी बन चुके हैं। इस सम्बंध में कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं, इसीलिए एक बार फिर नगर आयुक्त अपने मातहतों को यह निर्देश देने के लिए विवश हुए हैं कि कार्यान्वयन समिति निष्ठा का पालन करे और जो काम कार्यदाई संस्था कर रही है, उसके हर पहलू की जांच कर काम गतिशील कराएं। इस बात की जानकारी भी करें कि काम की गति इतनी धीमी क्यों रही है। कई स्थान ऐसे हैं, जहां पर अधूरे काम होने से लोगों को परेशानी हो रही है।

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का कहना है जो निगरानी टीम बनाई गई है, वह खुद परियोजनाओं की जानकारी करें और इसकी रिपोर्ट उन्हें दें। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के चौराहों का सुंदरीकरण करना है। इनमें से वह चौराहे भी हैं, जहां पर पहले भी काम हो चुका है। योजनानुसार करीब 53 करोड़ खर्च कर कई काम किए जाने हैं। जो काम 30 जून 2022 को पूरे होने थे, वह अभी तक लटके हुए हैं। इसमें अभी और कितना समय लगेगा, यह भी तय करना संस्था के बस की बात नहीं है।

15 दिसम्बर 2021 को जिन कार्यों का लक्ष्य दिया गया था, वह 2022 में पूरे किए जाने थे लेकिन संस्था की काम करने की गति इतनी सुस्त रही कि आज भी निर्धारित शहर की तमाम सड़कों को स्मार्ट नहीं बनाया जा सका है। हालत यह है कि गड्ढों पर चल-चल कर लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि वह सड़कों पर निकलना नहीं चाहते हैं। करीब 276 करोड़ रुपए खर्च कर सड़कों को स्मार्ट किया जाना था। 2019 में इस काम के लिए आदेश पारित हुए थे, लेकिन अभी तक इनमें गड्ढे ही गड्ढे हैं। डीएम दफ्तर की पार्किंग भी कच्छप गति से बन रही है। हालांकि, अब नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के तेवर काफी सख्त हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि कार्यदाई संस्था को जल्द ही अपने अधूरे काम पूरे करने होंगे। मौके पर जाकर अधिकारी देखेंगे कि काम चल रहा है या नहीं।

किसानों को आय बढ़ाने के जरिए बता रहे विशेषज्ञ

किसान क्रय केंद्रों पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम

आईपीके, लखनऊः किसान क्रय केंद्रों पर इन दिनों सरकार के निर्देश पर कृषक गोष्ठियां एवं किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिसमें विशेषज्ञ किसानों को खेती-बाड़ी की तकनीकी की जानकारी दे रहे हैं। पहली गोष्ठी का आयोजन रहीमाबाद में बुधवार 31 अगस्त को किया गया था, जिसमें खुद कृषि मंत्री भी शामिल हुए थे। उसके बाद से कई स्थानों पर विशेषज्ञ पहुंचे और किसानों को आय बढ़ाने के तमाम सुझाव दे रहे हैं। वैज्ञानिक अब मछली, मुर्गी, केंचुए, मधुमक्खी के अलावा बतख, बकरी पालन, निबौली से तेल निकालने और फूलों की खेती के लिए भी किसानों को प्रेरित कर रहे हैं।

किसानों को समझाते हुए वैज्ञानिक सत्येंद्र सिंह ने कहा कि गन्ना एक विकल्प है, इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। किसान इसके साथ सह फसली जरूर करें। रहीमाबाद के बाद कृषि भवन सिकंदराबाद में वैज्ञानिकों की उपस्थिति में आय बढ़ाने पर चर्चा हुई। किसानों की चिंता को जायज बताते हुए वैज्ञानिक महिपाल ने कहा कि फसलों में संतुलित उर्वरक न डालने पर उत्पादन को खतरा पहुंच रहा है। इसका प्रयोग करने के लिए रसायनिक खाद के प्रयोग से दूर रहें, साथ ही मृदा परीक्षण न होने से भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका खामियाजा किसान ही नहीं, पशु और उनके पालनहार भी उठाते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि सरकार की मंशा है कि किसानों की आय बढ़े, जिस पर किसानों ने कहा कि खरीफ मौसम में लगने वाली सब्जियां कीड़े खाते हैं लेकिन सरकारी मंशानुरूप उसमें दवा का छिड़काव करने के लिए मदद नहीं मिलती। किसानों ने कहा कि किसान उच्च गुणवत्ता एवं विश्वसनीय संस्था से बीज खरीदते हैं, इसके बाद भी परिणाम भिन्न होते हैं। बिजनौर के किसान उपेंद्र साहू ने बीज का जिक्र किया और बताया कि अप्रैल में बोई गई तरोई में अब फूल निकल रहे हैं। परखने के लिए ही एक-दो पौधे बचाए थे, बाकी सब उजाड़ दिए गए तो बाजार में ऐसी सामग्री बिकती ही क्यों है ? किसानों ने मांग की कि बीज खराब बेचने वाले सम्बंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में खूब हो रहा भैंसे का व्यापार

आईपीके, लखनऊः डेयरी किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वह दूध के कारोबार में भैंसे का इस्तेमाल कहां करें। पिछले कुछ वर्षों में गौवंशीय पशुओं को लेकर सरकार की सख्ती का असर रहा है कि गौवंश की कहीं कटान न हो, इसके बाद पशुपालकों की चिंता और बढ़ गई है। ऐसे में भैंसे को पालने व उन्हें दो-तीन साल बाद बेचकर मोटा मुनाफा कमाने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और एक व्यवसाय बन गया है।

भैंस के बच्चों में पड़िया को आने वाले समय के लिए रोक लिया जाता है, लेकिन पड़वा यानी कटरा का इस्तेमाल लखनऊ जैसे शहरों में नहीं है। इसके बाद भी भैंस पालकों के पास यह कटरा नहीं हैं। आखिर यह जाते कहां हैं, इसका जवाब है कि दूध की कीमत के साथ भैंस की कीमत भी तेजी से बढ़ रही है। जो दूध का कारोबार कर रहे हैं, वह कटरा को बेच देते हैं। इन्हें जब तक भैंस दूध देती है, वह अपने पास रखते है। बाद में उन्हें कटरा व्यापारी को बेच देते हैं। व्यापारियों की मानें तो ड्राई बफेलो यानी गैर-दुधारू भैंस की कीमत 175 रुपए प्रति किलोग्राम है। काटी जाने वाली भैंस की कीमत करीब 100 किलो से 450 किलो के बीच होती है। डेयरी मालिकों से इनकी खरीदारी व्यापारी खुद करते हैं और कटरा को एक साल से तीन साल तक अपने पास रखते हैं। दूध कारोबारी राजेश सिंह यादव कहते हैं कि हम या तो कुछ लाभ के साथ इसे बेच सकते हैं या फिर कबाड़ समझकर निकालने में ज्यादा रूचि रखते हैं। हमारे लिए दूध ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें काफी फायदा है। चारे की कीमत और श्रम लागत महंगी पड़ती है, जबकि कटरा व्यवसायी के लिए कटरे में ज्यादा फायदा है। यह व्यापारी गैर-दुधारू यानी बांझ भैंस भी तलाशते रहते हैं। राजेश बताते हैं कि यह ऐसे पशु हैं, जिनका मांस बिकता है। भारत का पशु मांस निर्यात तेजी से बढ़ा है। इसकी खपत जैसे अन्न में बासमती चावल बिकता है, वैसे ही मांस में कटरा है। हालांकि, भैंस का मांस 2018-19 के बाद घटा है। लखनऊ में तमाम ऐसे परिवार हैं, जहां के लोग कटरा व्यवसाय कर रहे हैं। इनमें एक साथ छह से दस तक कटरा हैं। परिवार का एक सदस्य इन्हें लेकर सुबह घर से बाहर नदी, नहर और नालों के किनारे लेकर चला जाता है। इन्हें ज्यादा स्वादिष्ट चारे की जरूरत नहीं पड़ती है। घूमते हुए कटरा ज्यादा हेल्दी रहते हैं और नहर के किनारे यह चरकर अपना पेट भर लेते हैं। इससे किसान का चारे वाला खर्च बच जाता है। किसान का अपना अलग से और कोई खर्च नहीं होता है। एक कटरा जब बिकता है, तब उसकी कीमत पचास हजार तक होती है। इनकी खरीद में भी ज्यादा पैसे नहीं खर्च किए जाते हैं। व्यापारी खुद पशुपालकों के सम्पर्क में रहता है। जैसे ही भैंस दूध देना बंद करती है, किसान इन कटरों को व्यापारियों के हवाले कर देते हैं।

तिल की बुवाई से मालामाल होंगे किसान

आईपीके, लखनऊः बाढ़ और सूखे का सामना करना किसानों की आदत बन गई है। ऐसे में किसान अब ऐसी फसलों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जो उनको हर हाल में मुनाफा देकर ही जाए। इस बार राजधानी के सैकड़ों किसानों ने अपने खेतों में तिल की बुवाई की है। किसानों का मानना है कि दो दशक पहले की तरह ही यदि इसे खेतों में जगह दी गई, तो तिल से अच्छी कमाई होगी।

तिल की मांग लगातार बढ़ रही है। खरीफ सीजन के दौरान इस फसल का रकबा अगर देखना है, तो लखनऊ के सिसेंडी, उन्नाव के पुरवा और रायबरेली के सेमरी क्षेत्र पहुंचना होगा। यहां खेतों में तिल ही तिल दिख रहा है। यह एक ऐसी बेल्ट है, जो तीन जिलों को जोड़ती है। पूरा भौगोलिक क्षेत्र खेती से सम्बंधित है। नौकरी पेशेवर कम हैं, लेकिन खेती में ज्यादा लोग पूरी तन्मयता से समय खपा रहे हैं। इस क्षेत्र में पानी के संसाधन भी प्रोत्साहित करने वाले नहीं हैं, इसलिए लोगों को बारिश के पानी पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। दिसम्बर में भी लोग बारिश के लिए आसमान निहारने लगते हैं। सर्दियों में गेहूं जैसी फसल को सींचने और बोने के लिए ज्यादा किसान बारिश की इच्छा रखते हैं। यदि एक बार भी इस फसल के लिए बारिश हो जाती है, तो सिंचाई में खर्च होने वाला पैसा बच जाता है। बारिश में काफी किसान धान लगाना चाहते हैं। ऐसे भी किसान बड़ी संख्या में हैं, जो गन्ना उत्पादन में रूचि रखते हैं लेकिन इन फसलों के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। फसल से आने वाली रकम तो सिंचाई में ही चली जाती है, इसलिए इनसे किसानों की दूरियां बढ़ गई हैं। अब तिल की खेती में फिर से किसानों का विश्वास जगा है। तमाम ऐसी सड़कें हैं, जिनसे गुजरते समय खेतों में केवल तिल के पौधे ही दिखते हैं। शफीपुर उन्नाव के किसान दवींद्र और केदारनाथखेड़ा के किसान आनंदकंद कहते हैं कि तिल की खेती का भी अपना मजा है। यदि यह घास से बच जाए और फलियां अच्छी तरह से खिलें, तो आमदनी भी काफी होती है। तिल की खेती अनुपजाऊ जमीन में की जाती है। हल्की रेतीली और दोमट मिट्टी उत्पादन के लिए सही होती है।

न मक्के का रकबा बढ़ा और न ही आमदनी

सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया लक्ष्य, हवा-हवाई साबित हो रहा आमदनी दोगुनी करने का दावा

आईपीके, लखनऊः किसानों की आय दोगुनी करने का सरकारी दावा सिर्फ हवा में ही तैर रहा है, क्योंकि इसके लिए किए जाने वाले प्रयास धरातल पर उतर ही नहीं पा रहे हैं। कुछ फसलों के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर रणनीति बनती है और लक्ष्य भी तय किया जाता है, तो वह सटीक निगरानी के अभाव में औंधे मुंह ही गिर पड़ती है।

हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2021-2022 में मक्के का उत्पादन 14.67 लाख टन था, जिसका रकबा पांच साल में बढ़ाकर 27.30 लाख टन करने का लक्ष्य था लेकिन यह सिर्फ आंकड़ेबाजी में ही उलझ कर रह गया। दरअसल, माना जा रहा था कि देश में पांच साल में मक्के का उत्पादन दोगुना किया जा सकता है। यह फसल काफी मुनाफे वाली है। वैज्ञानिकों का तर्क भी है कि मक्के का प्रयोग इथेनाल उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों, कुक्कुट व पशुओं के पोषाहार, दवा, कॉस्मेटिक, गोंद, वस्त्र, पेपर व अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए देश के तमाम राज्यों में जाता है। यही नहीं मक्का विदेशों में भी पसंद किया जाता है। मक्के को रोटियों, ढोकला, बेबी कार्न व पॉपकॉर्न के रूप में खाया जाता है। इसका इस्तेमाल सूप में भी किया जाता है, मगर पोषक तत्व वाले इस मोटे अनाज का उपयोगिता खूब होने के बाद भी इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए तनिक भी रकबा नहीं बढ़ाया जा सका है। बेहतर उपज या सहफसली खेती और औद्योगिक प्रयोग में हर मौसम में मक्का पैदा होता है। यह रबी, खरीफ व जायद के सीजन में भी बाजार में दिख जाता है। बहरहाल यदि हम कागजों की बात न करें और जमीनी हकीकत पर गौर करें तो लखनऊ में जोत जमीन कम हुई है। ऐसे में मक्के का रकबा बढ़ाया जाना स्वाभाविक भी नहीं है। यह सिद्ध होता है कि यहां मक्के की खेती पर सरकारी ध्यान भी नहीं गया।

एक समय में बोएं दूसरी फसल

मक्के की खेती के लिए सिंचाई की सुविधा हो, तो फरवरी के दूसरे हफ्ते में आलू, सरसों और सब्जी की फसलों से खाली खेत में मक्का बो सकते हैं। कई किसान आज भी जायद की मूंग और उड़द की भी फसल मक्के के साथ बोते हैं।

ऐसे होंगे उपाय

बीते महीने कृषि मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि मक्के की बढ़ती मांग का अधिकतम लाभ प्रदेश के किसानों को हो, इसके लिए सरकार भरपूर प्रयास करेगी। मक्के की खेती के प्रति किसानों को जागरूक करेगी और उन्हें खेती के उन्नत तौर-तरीके बताए जाएंगे। उन्नतशील बीज और वाजिब दाम के लिए सरकारी अफसर भी अब प्रयास करेंगे। सरकार पहले ही इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दायरे में ला चुकी है।

पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं घर की सब्जियां

गमले में उगा सकते हैं टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च

आईपीके, लखनऊः इन दिनों अपने घर की छत और बालकनी में लोग खूब पौधे लगा रहे हैं। एक क्यारी की भी अगर जगह है, तो लोग इसमें हरियाली को जरूर स्थान देना चाहते हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वह चाहते हैं कि शहर के लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं।

पुराने लखनऊ को यदि छोड़ दिया जाए, तो नई विकसित कॉलोनियों में अब हर घर तक पौधों की पहुंच बढ़ रही है। किसी खाली जगह पर मनपसंद सब्जियां उगाने वालों की कमी नहीं है। गोमतीनगर, निरालानगर, इंदिरानगर में छतों पर लोग तरोई और लौकी के बीज बोने लगे हैं। फूलों के पौधे तो बालकनी में भरे पड़े हैं। सब्जी उगाने के लिए छत और बालकनी में जगह आसानी से बन जाती है। जिस घर में 15-25 गमले रखे जा सकते हैं, वहां आसानी से सब्जी के एक-एक पौधे को स्थान दिया जा सकता है। इसमें तरोई, लौकी, सेम क्रीपर के रूप में जबकि टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन के दो पौधे एक गमले में लगाए जा सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने बड़े गमले में इनको स्थान दिया है। ज्यादा जगह मिलने पर यह पौधे बड़े हो जाते हैं और अच्छे फल देते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, जो गमले का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं तो वह थोक में प्लास्टिक की बाल्टियों को गमले के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन के लिए मध्यम आकार के गमलों का उपयोग कर सकते है, लेकिन बेल वाली सब्जियों के लिए बड़े गमले की आवश्यकता होती है। इसमें 15 किलो मिट्टी को जगह की जरूरत होती है। गमला बनाते समय बर्तन में नीचे छेद जरूर करें, ताकि इसमें जमा पानी आसानी से निकल सके।

देते रहें पोषक तत्व

गमले में लगाए गए पौधों को पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जमीन पर बोए गए पौधों को ज्यादा भूमि मिलने से उनको काफी पोषक तत्व मिल जाते हैं। ऐसे में पौधों को भरपूर मात्रा में धूप मिले, यह सुनिश्चित करें और हर 15-20 दिन में थोड़ी खाद डालते रहें।

छत पर सब्जी उगाने के फायदे

छत पर सब्जी उगाने से बहुत से फायदे हैं। पहला तो यह कि हरी सब्जी किसी भी समय आपको खाने को मिल जाती है। दूसरा यह कि केमिकल से मुक्त ताजी सब्जी के लिए मंडी की दौड़ नहीं लगानी पड़ती। तीसरा फायदा यह होता है कि घर का वातावरण शुद्ध बना रहता है।

निगम को मिली राहत, 74 एआरएम की होगी भर्ती

547 पदों के प्रस्ताव को अभी भी मंजूरी का इंतजार, 815 मृतक आश्रितों की भर्ती का प्रस्ताव भी शासन में है लम्बित

आईपीके, लखनऊः उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम में अफसरों की कमी को दूर करने के लिए शासन ने 74 सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एआरएम की भर्ती पूर्व में चिह्नित एजेंसी आईआईएम से कराई जाएगी। इनमें एआरएम संचालन, टेक्निकल और लॉ ऑफिसर के पद भी शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने में पूरा कराने का लक्ष्य तय किया गया है, वहीं परिवहन निगम की वर्कशॉप और फील्ड में खाली कर्मियों के पदों को भरने के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव को शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।

परिवहन निगम ने 547 कर्मियों की भर्ती का अलग प्रस्ताव बनाया है, जिसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, 547 कर्मियों के भर्ती प्रस्ताव में अधिकतर पद वर्कशॉप के हैं। इनमें मैकेनिक, सुपरवाइजर समेत अन्य पद शामिल हैं, वहीं बस अड्डों के लिए जेएसआई (जूनियर स्टेशन इंचार्ज) की भर्ती की जाएगी। वर्तमान में जेएसआई पद का काम अन्य कर्मियों के जरिए चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि परिवहन निगम की वर्कशॉप में तकनीकी कर्मियों के आधे से अधिक पद खाली हैं। निगम में वर्कशॉप कर्मियों की लम्बे समय से भर्ती नहीं हुई है। इसके चलते बसों के मेंटीनेंस की व्यवस्था चरमराई हुई है। आउटसोर्सिंग के जरिए किसी तरह काम चलाया जा रहा है। हालांकि, आउटसोर्स कर्मियों को भी निगम की ओर से बहुत कम दिहाड़ी दी जाती है। इसके चलते निगम की वर्कशॉप में काम करने के लिए अच्छे मैकेनिक नहीं मिल पाते हैं। अच्छे मैकेनिक न होने के चलते अक्सर निगम की बसें बीच रास्ते खराब हो जाती हैं और यात्रियों को सफर में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा परिवहन निगम में 815 मृतक आश्रितों की भर्ती का प्रस्ताव भी शासन स्तर से लम्बित है। मृतक आश्रितों के भर्ती प्रस्ताव को भी जल्द मंजूरी मिलने की सम्भावना है।

500 आरटीओ सिपाहियों की होगी भर्ती

परिवहन विभाग में आरटीओ सिपाहियों की भर्ती के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आरटीओ सिपाहियों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए होगी। भर्ती प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब सिपाहियों के बड़े पैमाने पर खाली पड़े पदों को भरा जा सकेगा, वहीं आरटीओ सिपाहियों की भर्ती समूह 'घ' की जगह समूह 'ग' के तहत होगी। इस बदलाव से आरटीओ सिपाहियों को ग्रेड-पे का लाभ मिलने के साथ भविष्य में प्रमोशन का लाभ भी मिल सकेगा। इसके साथ ही उनका वेतन भी अब वन और आबकारी विभाग के प्रवर्तन सिपाहियों की तरह हो जाएगा। अब तक आरटीओ सिपाहियों के प्रमोशन की व्यवस्था नहीं थी। वह सिपाही के पद से ही सेवानिवृत्त हो रहे थे। हालांकि, अब भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग में 500 सिपाहियों की भर्ती के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आरटीओ सिपाहियों के कुल 744 पद हैं, जिनमें से 244 पद भरे हैं।

कैसरबाग में एसी बसों के टिकट काउंटर बंद, यात्री परेशान

लखनऊः राजधानी लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर गुरुवार 01 सितम्बर को एसी बसों के टिकट काउंटर बंद होने से यात्री भटकते रहे। मामले की सूचना परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार के पास पहुंची, तो आनन-फानन में दो कर्मचारियों को तैनाती के निर्देश क्षेत्रीय प्रबंधक को दिए हैं। परिवहन निगम के लखनऊ स्थित कैसरबाग बस अड्डे पर एसी बसों में एडवांस और तत्काल में यात्रियों को मिलने वाली टिकट बुकिंग सेवाएं 31 अगस्त की रात से ठप कर दी गईं। काउंटर पर तैनात सभी चार कर्मियों को हटा दिया गया। ऐसे में गुरुवार को कैसरबाग बस अड्डे के वॉल्वो बस काउंटर पर टिकट बुक कराने गए यात्री भटकते रहे। मामले की सूचना परिवहन निगम के एमडी के पास पहुंची, तो आनन-फानन में दो कर्मचारियों को तैनाती के निर्देश क्षेत्रीय को दिए गए हैं। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि जल्द ही टिकट बुकिंग काउंटर खुल जाएंगे, जहां से यात्री एसी बसों में ऑनलाइन सीटों की बुकिंग करा सकेंगे। दरअसल, परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के आदेश पर चालकों-परिचालकों को मूलपद पर भेज दिया गया है। इस वजह से टिकट काउंटर पर तैनात कर्मियों को हटा दिया गया है।

मिला बजट, तो खिल उठे निगम पार्षदों के चेहरे

आईपीके, लखनऊः शहर में विकास कार्यों की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है। इसका कारण है कि बीते दो सालों कोरोना का कहर घर-घर था। इससे निपटने के लिए लॉकडाउन के कारण नगर निगम के बजट में भी कटौती होती रही है। इसी कारण पार्षद उतना काम नहीं कर पाए, जितनी जनता को उम्मीदें थीं। इसके बाद भी 2022 के शुरुआत में तमाम प्रयास किए गए कि शहर के विकास के लिए पार्षदों को पर्याप्त धन मुहैया कराया जाए। अब इसको लेकर सफलता हाथ लगी है और पार्षदों के चेहरे खिल गए हैं।

दरअसल, निगम में बजट को लेकर कई बैठकें हुईं, लेकिन बात नहीं बन सकी। बीते दिनों इसको लेकर नगर निगम में हंगामा भी हुआ था। वर्तमान में नगर आयुक्त ने पार्षदों को मनाने की कोशिश की, तब जाकर यह बात भी सामने आई कि जिस बजट की घोषणा की गई थी, वह पार्षदों को नहीं मिल रहा है। इसके बाद नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने सभी वार्डों के लिए 125 करोड़ रुपए मुहैया कराने के निर्देश दे दिए। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के तमाम कार्यों में अड़चन आई, इसीलिए अटके हुए काम पार्षद कोटे से पूरे कराए जाएंगे। हालांकि, इसमें बड़े कार्य नहीं हो पाएंगे। कुछ नए क्षेत्र ऐसे हैं, जो वार्ड में शामिल किए गए हैं। जैसे- 88 गांवों का भौगोलिक क्षेत्र। बजट 2022-23 को 13 जून को सदन में पास किया गया था। इसमें आय और व्यय को लेकर चर्चा भी की गई थी। यह बजट 10 दिन के भीतर ही पारित किया जाना था, लेकिन निकाय चुनाव नजदीक होने के बाद भी जुलाई तक इसमें अड़चनें रहीं। कभी फाइल में हस्ताक्षर नहीं होती, तो कभी कोई आपत्ति लग जाती। अब पार्षदों को विकास कार्य कराने के लिए जिस अधिकारी को आगे किया गया है, उसमें अपर नगर आयुक्त राकेश यादव का नाम है। उन्होंने बजट की कार्यवाही रिपोर्ट जारी कर दी है यानी अब विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होगी। पार्षद अपने क्षेत्रों में नाली, साफ-सफाई और स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था कर सकते हैं।

असलहों की तस्करी करने वाले को एसटीएफ ने दबोचा

पुलिस ने रखा था 25 हजार का नकद ईनाम

आईपीके, लखनऊः अंतर्राज्यीय स्तर पर हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के 25 हजार का इनामी अपराधी विनोद वर्मा अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। यूपी एसटीएफ ने बुधवार 31 अगस्त को अपराधी विनोद को एक अदद पिस्टल के साथ राजधानी की सीमा से लगे जिले हरदोई से गिरफ्तार कर लिया। विनोद बलिया जिले के सौरूपुर, रसड़ा का रहने वाला है।

विगत कई दिनों से यूपी एसटीएफ को अपने सूचना तंत्र से अंतर्राज्यीय हथियारों के तस्कर गिरोह के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। एसटीएफ मुख्यालय से इनके विरूद्ध अभिसूचना संकलन एवं प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार नागर के पर्यवेक्षण में निरीक्षक दिलीप कुमार तिवारी के नेतृत्व में एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्रवाई की जा रही थी। अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ को ज्ञात हुआ कि असलहा तस्करों द्वारा मध्य प्रदेश प्रांत के खरगौन जनपद से देशी पिस्टल लाकर लखनऊ व आस-पास के जनपदों में बेचा जा रहा है। एसटीएफ ने सूचना के आधार पर ही इससे पहले तीन अपराधियों को पिस्टल के साथ दबोचा था। बुधवार को एसटीएफ को सूचना मिली कि 25 हजार का इनामी विनोद हेममतुआ तिराहा, डबल नहर पुलिया के पास थाना क्षेत्र, कछौना, हरदोई में मौजूद है, जिसके बाद स्थानीय थाने से सम्पर्क स्थापित करने के बाद उसे दबोच लिया गया।

कानपुर-हरदोई में छिपकर रह रहा था विनोद

पूछताछ में विनोद ने बताया कि वर्ष 2021 मे उसकी मुलाकात जनपद मऊ निवासी राम प्रताप सिंह से हुई थी, जो किसी मुकदमें में रसड़ा में रहकर फरारी काट रहा था। उसी के साथ मिलकर अवैध असलहों की सप्लाई का काम करने लगा। इसमें उसे काफी मुनाफा होने लगा। राम प्रताप सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके ऊपर ईनाम घोषित हो गया। जिसके बाद मैं कानपुर व हरदोई में रहकर असलहों की सप्लाई कर रहा था।

अपराधी विनोद

10 पुलिस उपाधीक्षकों का स्थानांतरण

लखनऊः प्रांतीय पुलिस सेवा सवंर्ग (पीपीएस) 10 पुलिस उपाधीक्षकों का स्थानांतरण गुरुवार 01 सितम्बर को देर रात हुआ। इसके अलावा लखनऊ कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्तों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। पुलिस विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, अभय प्रताप सिंह को खीरी से सहायक पुलिस आयुक्त लखनऊ भेजा गया है। गिरि-जाशंकर त्रिपाठी को मुजफ्फरनगर से जालौन, रामाशीष यादव को सोनभद्र से मुजफ्फरनगर विजय आनंद को जालौन से उन्नाव, जगदीश लाल टम्टा को अम्बेडकर नगर से शाहजहांपुर, पंकज कुमार श्रीवास्तव को लखनऊ कमिश्नरेट से पीटीसी मेरठ भेजा गया है। इसी तरह जयराम को अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ से सिद्धार्थनगर, रमेश चन्द्र पाण्डेय को सिद्धार्थनगर से गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट और पीतम पाल सिंह को गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट से हटाकर जनपद खीरी भेजा गया है।

गृहकर बकाएदारों पर सख्त हुआ नगर निगम

नोटिस के बाद सील किए जा रहे मकान

आईपीके, लखनऊः नगर निगम लखनऊ के पास आय बढ़ाने के लिए कई बड़े स्रोत हैं, लेकिन अधिकारियों ने गृहकर वसूली को मजबूत हथियार बनाया है। इसके लिए तमाम बकाएदारों के खिलाफ सीलिंग कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों निगम ने इसके संकेत भी दिए थे। सीलिंग कार्रवाई से पहले तमाम बकाएदारों को नोटिस भेज दी गई है।

नगर निगम के अधिकारियों को उन बकाएदारों के घरों तक पहुंचना होगा, जो बकाएदार हैं। जिन्होंने गृहकर जमा करने में कंजूसी बरती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सामान्य वसूली की जा रही है। यदि बकाएदार निर्धारित समय पर रकम जमा नहीं करते हैं, तो निगम के अधिकारी बकाएदारों के घरों के बाहर नोटिस चिपका देंगे और लोगों को भुगतान करने के लिए समय दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि बकाएदारों ने गम्भीरता नहीं दिखाई, तो घरों को सील कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि नगर निगम के एक हजार से ज्यादा बड़े बकाएदार हैं, जिन्होंने नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं किया है। इनके लिए भी अधिकारियों ने नोटिस बनवा दी हैं। इनके घरों और प्रतिष्ठानों पर तैयार की गई नोटिस चस्पा की जाएंगी। अब एक तिथि दी जाएगी, उसके बाद सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। निगम के रजिस्टर में करीब 03 लाख लोगों के नाम हैं, जिन्होंने गृहकर जमा नहीं किया है। इनके लिए नगर आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि मुख्यालय के लोग बकाए की वसूली करें। नोटिस भेजने के लिए मुख्य कर अधिकारी अशोक को जिम्मेदारी दी गई है। बकाएदारों को अधिकतम 20 दिन का समय दिया जाएगा।

कई भवन किए गए सील

अभी तक जो बड़ी कार्रवाई की गई हैं, वह निगम के जोन एक, जोन पांच और सात में की गई है। इसमें करीब 300 टीमें लगाई गई हैं। भवन सील करने, कुर्की करने और वसूली करने के लिए जोन के कर अधीक्षक भी मौजूद रहे। जो धन अधिकारियों ने इकट्ठा किया है, उसे निगम के कोष में जमा करा दिया गया है। जोन एक में छह भवन सील किए गए हैं। जोन पांच से करीब 11 लाख रूपये जमा किए हैं। जोन सात में चार दुकानों की कुर्की की गई है और करीब डेढ़ लाख रूपए की वसूली कर निगम के कोष में जमा कराया गया है।

साइबर क्राइम मैनेजमेंट में यूपी पुलिस को मिला सम्मान

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के अभियान के नतीजे अब नजर आने लगे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्की ने दिल्ली में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में यूपी एसटीएफ को साइबर क्राइम मैनेजमेंट के क्षेत्र में स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड-21 से सम्मानित किया है।

फिक्की ने यह अवॉर्ड होमलैंड सिक्योरिटी पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया। यूपी एसटीएफ को यह अवॉर्ड जार्विस सियान सॉफ्टवेयर टूल के लिए दिया गया है। तीन दिन पहले एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट में भी प्रदेश में साइबर क्राइम के मामलों में अच्छी-खासी कमी का उल्लेख किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस को प्रदेश के विभिन्न जिलों में साइबर थाने स्थापित करने के निर्देश दिए थे, ताकि साइबर अपराध पर लगाम लगाई जा सके। इसी के तहत प्रदेश में संचालित दो साइबर थानों की संख्या में इजाफा करते हुए रेंज स्तर पर 18 साइबर थाने शुरू किए गए। इन थानों में दर्ज 1,012 अपराधों में से 379 मामलों में खुलासा हो चुका है, जबकि 700 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 68.69 करोड़ रुपए की धनराशि को खातों में सीज किया गया, साथ ही 6.40 करोड़ रुपए बरामद किए गए। जिसके बाद प्रदेश में साइबर क्राइम के मामलों में कमी देखी गई है। फिक्की ने भी प्रदेश में कम होते साइबर क्राइम के मामलों की सराहना करते हुए दिल्ली में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश और डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह को स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड के लिए सम्मानित किया। एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट में भी साइबर क्राइम के मामले घटकर 8,829 रह गए, जो कि वर्ष 2020 की तुलना में 22.6 फीसदी कम है।

भाजपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को किया बर्बादः अखिलेश

मिशन कायाकल्प के नाम पर फूंके गए करोड़ों रूपए

लखनऊः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार 02 सितम्बर को जारी अपने बयान में कहा है कि भाजपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मिशन कायाकल्प के नाम पर करोड़ों, अरबों रुपए फूंकने के बाद भी सरकारी स्कूलों के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। तमाम स्कूल जर्जर भवनों में चल रहे हैं। शिक्षकों के तमाम पद खाली हैं। भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री केवल वादों के सहारे अपने दिन बिता रहे हैं।

भाजपा सरकार परिषदीय स्कूलों में बच्चों के हित में कोई भी व्यवस्था करने में नाकाम रही है। बच्चों को यूनीफॉर्म, जूते-मोजे मुहैया कराने में बहुत लापरवाही बरती गई। अभी तक सभी स्कूलों में बच्चों को किताबें नहीं बंट पाई हैं। लाखों बच्चे बिना किताब पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बच्चों के खेल-कूद के लिए मैदान नहीं है। स्कूल की साफ-सफाई खुद बच्चों को ही करनी पड़ती है। भाजपा राज में शिक्षा क्षेत्र में घोर अव्यवस्था और अधिकारियों की मनमानी के चलते परिषदीय स्कूलों से बच्चों और अभिभावकों का मोहभंग हो चला है। शिक्षा की खराब गुणवत्ता और मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण अकेले नोएडा में 38 प्रतिशत बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ती ही जा रही है। शिक्षक समय से स्कूल नहीं आते हैं। बहुत से शिक्षक नाम मात्र के शिक्षक बने हैं। सरकारी स्कूलों से मोहभंग का कारण यह भी है कि वहां न तो पेयजल की सुचारू व्यवस्था है और न ही मिड-डे-मील बन रहा है। तिर्वा के प्राथमिक विद्यालय, बरूआ में मिड-डे-मील न मिलने पर छात्र हंगामा कर चुके हैं। वैसे भी बच्चों को दूध, अंडा देने से राज्य सरकार पहले ही किनारा कर चुकी है। श्री यादव ने कहा कि कई स्कूलों में तो पढ़ाई से ज्यादा मेहनत बाहर से पानी लाने में छात्राओं को करनी पड़ रही है। अधिकांश विद्यालयों में शौचालय न होने से छात्राओं को विशेषकर बहुत परेशानी होती है। भाजपा सरकार पता नहीं कहां इज्जतघर बना रही है। सच तो यह है कि भाजपा सरकार की शिक्षा सहित विकास के किसी काम में कोई रुचि नहीं है, भाजपा लगातार सत्ता की राजनीति में व्यस्त रहती है। अपने पिछले पांच साल में उसने जनहित का कोई काम नहीं किया। भाजपा सरकार अब उत्तर प्रदेश के 11 हजार प्राथमिक विद्यालयों को भी पीपीपी मॉडल पर अपने चहेते पूंजीपतियों को देने की योजना बना रही है, जिससे रहा-सहा सरकारी नियंत्रण भी खत्म हो जाएगा। गरीब बच्चे कहां पढ़ेंगे, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। कुछ न करना और झूठे कामों का ढिंढोरा जोरों से पीटना ही भाजपा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

डॉ. उमंग खन्ना दुबई में हुए सम्मानित

लखनऊः लखनऊ के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. उमंग खन्ना का दुबई में एक समारोह में सम्मान हुआ। इस अवसर पर विश्व के कई देशों से आए चिकित्सक भी शामिल हुए। डॉ. खन्ना को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने, फैलाने के लिए टॉप इन्फ्लुएंसर ऑफ होम्योपैथिक अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। शहर के चौक इलाके के निवासी डॉ. उमंग खन्ना ने दुबई से लौटने पर बताया कि अवॉर्ड को देश की जनता को समर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि पुरस्कार मेरे विश्वास की जीत है। डॉ. उमंग ने बताया कि समारोह में देश के नामचीन क्रिकेटर श्रीसंत, क्रिकेटर हरभजन सिंह, भोजपुरी स्टार व सांसद मनोज तिवारी, आजमगढ़ सांसद व अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ, एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, मंदिरा बेदी भी शामिल थीं।

नशे के कारोबार को नेस्तनाबूत करने में जुटी यूपी पुलिस

सात दिनों में बरामद हुए 26 करोड़ से ऊपर के मादक पदार्थ, 34 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति भी की गई जब्त

आईपीके, लखनऊः सरकार की सक्रियता के बाद यूपी पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और लगातार छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब व हुक्का बार के विरूद्ध हो रही छापेमारियों से यह नजर आ रहा है कि जैसे प्रदेश के गली-कूचों में नशे का कारोबार चल रहा है और युवा इसके जाल में फंसकर बर्बाद हो रहे हैं।

प्रदेश के युवाओं को नशे की अंधेरी काल कोठरी में झोंकने वाले इन नशे के तस्करों के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के निर्देशन में पुलिस लगातार इन काले कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मार कर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद कर तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। तस्करों के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस ने पिछले सात दिनों यानी 24 अगस्त से 31 सितम्बर के बीच सक्रिय व संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 1,649 अभियोग पंजीकृत करते हुए 1,773 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की है और 2,080 व्यक्तियों को चिह्नित किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान कुल 26 करोड़ 71 लाख 22 हजार 355 रूपए की अवैध शराब एवं ड्रग्स व मादक पदार्थ की बरामदगी भी की गई है। इस कारोबार में शामिल 261 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 82 अभियोग पंजीकृत किए गए। इस अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुल 34 करोड़ 77 लाख 14 हजार 176 रूपए की सम्पत्ति को जब्त किया गया और न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर 166 प्रकरणों में सजा दिलाई गई।

अवैध व जहरीली शराब कारोबारियों पर शिकंजा

अवैध व जहरीली शराब के अंतर्गत 7,495 अभियोग पंजीकृत कर 7,714 के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 8,416 व्यक्तियों को चिह्नित किया गया। इस अभियान के दौरान 05 करोड़ 63 लाख 54 हजार 450 रूपये की अवैध व जहरीली शराब बरामद की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष रूप से अवैध ड्रग्स व मादक पदार्थों, अवैध शराब व हुक्का बार के विरूद्ध चल रहे अभियान की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। इन कृत्यों में संलिप्त अपराधियों व इन अपराधों का सम्पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित कराए जाने हेतु निर्देश के क्रम में उक्त अभियान को 08 सितम्बर 2022 तक बढ़ाया गया है।

6 महीने में 39 लाख किलो मादक पदार्थ बरामद

मात्र 6 महीने में हो 39 लाख किलोग्राम की अवैध मादक पदार्थों की खेप बरामद कर यूपी पुलिस ने नशे के कारोबारियों में दहशत पैदा कर दी है। गृह विभाग के अनुसार, 01 जनवरी 2022 से 31 जुलाई तक चरस, अफीम, हेरोइन, स्मैक, मॉरफीन, डोडा और गांजा समेत अन्य मादक पदार्थों की सप्लाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह का पर्दाफाश

एसटीएफ यूपी ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन सदस्यों को सोमवार 29 अगस्त को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से करीब 12.17 किलोग्राम अवैध चरस मिली, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रूपए आंकी जा रही है। एसटीएफ कानपुर की टीम को अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि अवैध मादक पदार्थ चरस की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य अवैध चरस की खेप लेकर बिहार, गोरखपुर, लखनऊ होते हुए विधनू क्षेत्रांतर्गत जनपद कानपुर आउटर में आ रहे हैं। यहां से इसकी आपूर्ति स्थानीय स्तर पर एवं आस-पास के जनपदों में की जाएगी। इस सूचना पर निरीक्षक लान सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ कानपुर की एक टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से गिरोह के तीन सदस्यों को दबोच लिया। उनके पास से 12.17 किलो अवैध चरस, 03 मोबाइल फोन और 7,480 रूपए बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए कारोबारियों में सुशील मिश्रा (55) कानपुर के खलासी लाइन का रहने वाला है, जबकि उसके साथ सुनीता देवी (40) व सुमित्रा देवी (40) बिहार के मोतीहारी की रहने वाली हैं। इसी क्रम में जनपद मेरठ में एसटीएफ को एक बड़ी सफलता तब हाथ लगी, जब उसने मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र से अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्कर को दबोच लिया। पकड़े गए तस्कर की पहचान फिरासत अली के रूप में हुई है, जिसके पास से 01 किलो 510 ग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 10 लाख रूपए), एक स्प्लेंडर मोटरसाईकिल नं. यूपी-15वी 330 और 1,120 रूपए नगद की बरामदगी की गई।

- अवैध ड्रग्स व मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान में उत्कृष्ट बरामदगी करने वाले जनपद बाराबंकी, सीतापुर खीरी, फतेहगढ़ रायबरेली हैं।
- अवैध शराब के विरुद्ध अभियान में जनपद देवरिया, झांसी, बलिया, वाराणसी ग्रामीण व उन्नाव ने उत्कृष्ट बरामदगी की है।
- अभियान के दौरान 40 हुक्का बार बंद कराकर 118 संलिप्त व्यक्तियों व संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई की गई।

मादक पदार्थ के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मात्र सात दिनों के भीतर ही 1,649 मुकदमें पंजीकृत करते हुए 26 करोड़ से अधिक मादक पदार्थों की बरामदगी यह बताती है कि पुलिस किस स्तर पर कार्रवाई कर रही है।

प्रशांत कुमार, एडीजी, कानून व्यवस्था

ऐशबाग-मानक नगर के बीच अतिरिक्त लूप लाइन हुई तैयार

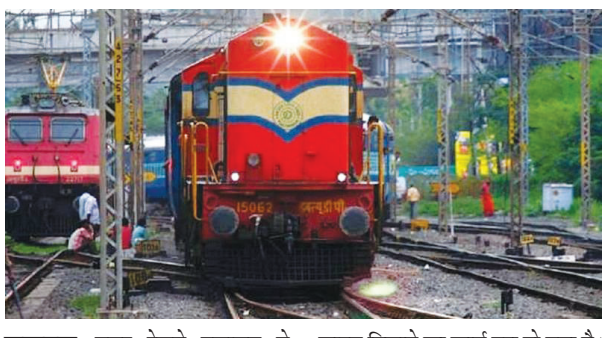

लखनऊः उत्तर रेलवे प्रशासन ने लखनऊ के मानक नगर रेलवे स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग का कार्य पूरा कर लिया है। इंटरलॉकिंग पूरी होने के चलते ऐशबाग से मानकनगर के बीच अतिरिक्त लूप लाइन तैयार हो गई है। इससे आउटर पर अब ट्रेनें लेट नहीं होंगी।

उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल प्रशासन ने मानक नगर रेलवे स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग का कार्य पूरा कर लिया है। इंटरलॉकिंग के चलते कई रद्द ट्रेनें शनिवार 03 सितम्बर से बहाल हो गईं हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की भीड़ होने के चलते कानपुर की ओर से आने वाली ट्रेनों को अमौसी व पिपरसंड स्टेशन पर रोकना पड़ता था। प्लेटफॉर्म खाली नहीं रहने से ट्रेनें आउटर पर लेट हो जाती थीं। इससे यात्रियों को परेशानी होती थी। लखनऊ के मानक नगर रेलवे स्टेशन पर आवागमन के लिए के लिए लूप लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। लूप लाइन तैयार होने से ट्रेनों के संचालन को रफ्तार मिलेगी और आउटर पर ट्रेनें लेट नहीं होंगी। मानक नगर रेलवे स्टेशन के रास्ते ट्रेनों को सीधे गुजारा जा सकेगा, फिलहाल मानक नगर स्टेशन पर एक नया फुटओवर ब्रिज बनाया गया है। प्लेटफॉर्म नम्बर दो व तीन की लम्बाई बढ़ाई गई है, साथ ही चार नम्बर का नया प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के डीआरएम सुरेश कुमार सपरा का कहना है कि मानक नगर रेलवे स्टेशन से करीब 60 जोड़ी ट्रेनों का आवागमन होता है। इसमें मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। मानक नगर स्टेशन पर इंट-रलॉकिंग का कार्य पूरा होने के चलते ऐशबाग से मानक नगर के बीच अब अतिरिक्त लूप लाइन की सुविधा मिलेगी। इससे ट्रेनों के संचालन को और रफ्तार मिलेगी।

दिसम्बर तक तैयार होगा अयोध्या का अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन

लखनऊः त्रेतायुग में सर्वसुविधा सम्पन्न रही श्रीराम की नगरी अयोध्या का प्राचीन वैभव दोबारा वापस लौट रहा है। एक तरफ श्रीराम जन्मभूमि पर नव्य-भव्य मंदिर आकार ले रहा है, तो दूसरी तरफ अयोध्या नगरी को दिव्य स्वरूप प्रदान करने की कवायद तेज गति से चल रही है। मोदी-योगी की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अयोध्या में जहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, वहीं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन की सौगात भी जल्द अयोध्यावासियों को मिलने जा रही है। यह देश के सबसे खूबसूरत और आधुनिक सुविधाओं से संपन्न रेलवे स्टेशनों में से एक होगा।

10 हजार वर्गमीटर में होगी बिल्डिंग

अयोध्या में बन रहे विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन के दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है। इसमें अयोध्या स्टेशन के विस्तार को लेकर रेलवे द्वारा 200 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। स्टेशन को नया लुक दिया जा रहा है। इसमें खूबसूरत भवन, पार्किंग, कर्मचारियों के लिए आवास, रेलवे पुलिस के लिए कार्यालय, तीन नए प्लेटफार्मों का निर्माण, रोड निर्माण, ड्रेनेज सम्बंधी कार्य सहित अन्य काम हो रहे हैं। अयोध्या स्टेशन की बिल्डिंग की बात करें तो यह 10 हजार वर्गमीटर में फैला होगा।

- **वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से होगा लैस**
- **अब तक एक छोटे से रेलवे स्टेशन के रूप में रही है पहचान**
- **200 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा अयोध्या स्टेशन का भव्य भवन**

90 फीसदी काम हो चुका है पूरा

रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (राइट्स) के जेजीएम, एके जौहरी ने बताया कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का काम दिसम्बर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। नए भवन में फिनिशिंग का काम चल रहा है। यहां बुजुर्गों और महिलाओं की सुविधा के लिए लिफ्ट व एस्केलेटर, एसी वेटिंग रूम, वॉशरूम, पेयजल बूथ, फूड प्लाजा समेत अन्य सुविधाएं तैयार हो चुकी हैं। पूरे भवन को एसी बनाया गया है। दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था होगी। स्टेशन करीब तीन किलोमीटर लंबा होगा। रेलवे स्टेशन के नए भवन का काम 90 फीसदी पूरा हो गया है।

अर्श से लेकर फर्श तक दिखेगी भव्यता

अयोध्या रेलवे स्टेशन के विस्तार का काम 2018 में शुरू हुआ था। पहले चरण में बने भवन को श्रीराम मंदिर की तर्ज पर भव्य और आकर्षक बनाया गया है। भवन में लगी टाइल्स, पत्थर, शीशे, दरवाजे, लाइटिंग आदि इसकी भव्यता का एहसास करा रहे हैं। भवन के बीच में लगा भारी-भरकम पंखा व ठीक उसके नीचे बनी फर्श की डिजाइन का आकर्षण यात्रियों का मन मोहने को तैयार है। स्टेशन परिसर के बाहर का विशाल परिसर भी इसकी भव्यता का गवाह बन रहा है।

स्टेशन पर उपलब्ध होंगी ये सुविधाएं

महिला-पुरुष व वीआईपी प्रतीक्षालय, फूड प्लाजा, कियोस्क, किताबों की दुकान, क्लॉक रूम, पर्यटक सूचना, यात्रा डेस्क, वाटर कूलर, दिव्यांगों के लिए अलग शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष, बीमार कक्ष, लिफ्ट, चार एस्केलेटर के अलावा बड़े कॉनकोर्स, वीआईपी लाउंज, प्रतीक्षा क्षेत्र, पर्यटक सूचना कार्यालय, रिटायरिंग रूम और लेडिज-जेंट्स डॉरमेट्री आदि सुविधाएं मिलेंगी।

09 अरब रुपए से होगा जन्मभूमि तक सड़कों का सौन्दर्यीकरण

योगी सरकार लगभग 09 अरब रुपए की लागत से जन्मभूमि तक पहुंचने के लिए सड़कों को चौड़ी, सुंदर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए पहली किश्त के रूप में 107 करोड़ रुपए शासन की ओर से जारी भी कर दिए गए हैं। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा अयोध्या में श्रीराम मंदिर तक पहुंचने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत तीन मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था के लिए शासन द्वारा 899.90 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है।

इसमें प्रथम किश्त के रूप में 107 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। सहादतगंज-नया घाट मार्ग के किलोमीटर 11 से सुग्रीव किला होते हुए श्रीराम जन्मभूमि तक कुल लम्बाई 0.566 किमी के लिए 4 लेन मार्ग के निर्माण की योजना है। इसके लिए कुल 39.43 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है, जिसमें से 3 करोड़ 90 लाख 88 हजार रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा फैजाबाद-अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमान गढ़ी होते हुए जन्मभूमि तक के मार्ग निर्माण और भूमि, भवन के क्रय व पुनर्वास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। अवनीश अवस्थी ने बताया कि इसके लिए 62.78 करोड़ रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें से 3 करोड़ 10 लाख 83 हजार रुपए जारी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य ने बताया कि सहादतगंज से नया घाट मार्ग के मेन स्पाइन रोड, जिसकी लम्बाई तकरीबन 12.940 किलोमीटर है, इसके निर्माण की कुल लागत 7 अरब 97 करोड़ 69 लाख रुपए की है, जिसमें से पहली किश्त के रूप में 1 अरब रुपए की किस्त दे दी गई है।

गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई 88 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति

जिलाधिकारी ने कहा, अपराधियों को नहीं जाएगा बख्शा

आईपीके, झांसीः जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा-14 (1) के अंतर्गत थाना कोतवाली झांसी, विपक्षी/अभियुक्त राहुल यादव पुत्र, राजू यादव व यदुवीर यादव निवासी ग्राम मैरी, थाना नवाबाद, हाल निवासी बड़ागांव गेट बाहर, थाना कोतवाली के विरूद्ध 88 करोड़ से अधिक की चल अचल सम्पत्ति को कुर्क किए जाने के आदेश दिए।

जिलाधिकारी ने कुर्की का आदेश देते हुए कहा कि जनपद में किसी भी दशा में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल यादव पर लगभग 06 मुकदमें थाना कोतवाली, नवाबाद, बड़ागांव आदि में दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त राजू यादव का भी आपराधिक इतिहास है। इन पर विभिन्न थानाओं में 11 मुकदमें विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। यदुवीर यादव पर विभिन्न धाराओं में लगभग 09 मुकदमें नवाबाद कोतवाली आदि थानों में दर्ज हैं। मुकदमों के दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि गिरोहबंद तरीके से अपराधियों द्वारा लगातार अपराध को अंजाम दिया जाता है। इसे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अपराधियों को चिह्नित करते हुए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रकरण में मुख्य रूप से इस तथ्य पर विचारण किया गया है कि अभ्यावेदक द्वारा अपने नाम जो सम्पत्ति अर्जित की गई है, उसकी अवधि तथा काल क्या है। उसे अर्जित करने के लिए उनके पास क्या स्रोत हैं। आपराधिक इतिहास पर गौर करने से पता चलता है कि अभ्यावेदकों का आपराधिक इतिहास वर्ष 1989 से है तथा विपक्षी/अभियुक्तों की जो सम्पत्ति कुर्क की गई है, वह संयुक्त रूप से 1992 में अर्जित की गई है।

उपमुख्यमंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण

आईपीके, प्रयागराजः उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार 30 अगस्त को बक्शी बांध पहुंचकर वहां से नाव के द्वारा बघाड़ा, सलोरी सहित अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बाढ़ राहत पैकेट में लाई, भुना चना, गुड़, मोमबत्ती, माचिस, बिस्किट, साबुन, पीने का पानी वितरित किया।

उपमुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी कम हो रहा है। उपमुख्यमंत्री ने बाढ़ के बाद की समस्याओं से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार एवं प्रशासन की तरफ से बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुनने व प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए ही वे बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच आए हैं। जिलाधिकारी ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि एनडीआरफ की टीम निरंतर बाढ़ क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है तथा बाढ़ से प्रभावित लोगों को रेस्क्यू कर रही है। उन्होंने कहा कि जल पुलिस तथा सामान्य पुलिस भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहकर निगरानी रख रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी उप-जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहकर स्थिति का जायजा लेते रहने का निर्देश दिया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए नांव, दवाइयां, राशन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी निरंतर सुनिश्चित कराई जा रही हैं।

- **पीड़ित लोगों को वितरित की राहत सामग्री**

पंजीकरण के बिना चल रहे अस्पतालों पर होगी कार्रवाई

आईपीके, जौनपुरः जनपद में बिना पंजीकरण के चल रहे निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इनका संचालन रोकने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) डॉ. लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय है। साथ ही जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर तहसील स्तरीय डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इस टीम का उपजिलाधिकारी (एसडीएम) तथा पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहे हैं।

टीम पर आवंटित तहसीलों में निजी अस्पतालों/डायग्नोस्टिक सेंटरों की जांच करने की जिम्मेदारी है। सीएमओ डॉ. लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जांच में अवैध संचालन करते पाए जाने पर टीम ही सम्बंधित अस्पताल के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति में बिना पंजीकरण के निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों का संचालन नहीं होने देगा। उन्होंने बताया कि निजी अस्पताल/डायग्नोस्टिक सेंटर चलवाने या नवीनीकरण करवाने के लिए बायो-मेडिकल वेस्ट का प्रमाणपत्र जरूरी है। पॉल्यूशन बोर्ड का सर्टिफिकेट, अग्निशमन प्रमाणपत्र तथा मानव संसाधन के लिए शपथपत्र भी साथ में लगाना पड़ता है। इसके बिना किसी भी स्थिति में पंजीकरण/नवीनीकरण मान्य नहीं है। उन्होंने बताया कि 45 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी की गई है। एक अस्पताल को सील करते हुए एफ-आईआर किया गया है। 01 मई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक कुल 336 अस्पतालों का पंजीकरण किया गया है। 01 मार्च 2022 से 30 अगस्त 2022 तक 138 अस्पतालों/क्लीनिकों/पैथोलॉजी/डायग्नोस्टिक सेंटरों का पंजीकरण किया गया। 01 अप्रैल 2022 से 30 अगस्त 2022 तक अस्पतालों/डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए कुल 243 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 01 मई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक मिले 193 फार्म जांच प्रक्रिया में हैं। उनका परीक्षण चल रहा है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर इनका पंजीकरण/नवीनीकरण पूर्ण कर दिया जाएगा।

देश का भविष्य संवारने का काम करते हैं शिक्षक

आईपीके, जौनपुरः निपुण भारत मिशन के तहत विकास खण्ड डोभी के बीआरसी पर चल रहे चार दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के अंतिम दिन 01 सितम्बर को मुख्य विकास अधिकारी साईं तेजा सीलम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल, खंड विकास अधिकारी डोभी के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने प्रशिक्षण दे रहे एआरपी संजय दुबे, सतीश यादव, रामसबद सिंह एव पारस नाथ यादव तथा अनुप्रिया पांडेय से प्रशिक्षण के बारे में पूछताछ की और कई सवाल किए।

सवालों से संतुष्ट मुख्य विकास अधिकारी ने प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों से भी उनका तीन दिन का फीडबैक लिया और पूछा कि आप लोगों ने क्या सीखा और अब स्कूलों में आप अपने स्तर से बच्चों को क्या नया सिखाने वाले हैं ? प्रशिक्षण ले रहे अध्यापकों द्वारा शानदार जवाब, सुनकर मुख्य विकास अधिकारी काफी उत्साहित हुए और उन्होंने अपने बचपन में पढ़ाए हुए शिक्षक-शिक्षिकाओं का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा पढ़ाने वाला खासकर बचपन को संवारने वाला गुरु कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि आप लोग निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को स्कूली बच्चों को प्राप्त कराएं। यही हमारी व हमारे लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक देश का भविष्य संवारता है। आप लोगों के कंधों पर इस देश के बच्चों का भविष्य है। आप लोग इसे निखारें व देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाएं। अभिनव प्राथमिक विद्यालय चन्दवक के प्रधानाध्यापक आलोक कुमार रघुवंशी (अध्यक्ष डोभी) ने मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी को अंगवस्त्र पहनाकर एवं स्मृति चिह्न से सम्मानित किया। इस अवसर पर विकास खण्ड डोभी के खंड शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार सिंह एवं आलोक कुमार रघुवंशी, संतोष सिंह, संजय यादव, अरविंद सिंह, अनिल सिंह, सूर्यमणि शास्त्री सहित शिक्षकगण उपस्थित रहे।

- **सम्पन्न हुआ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम**

सभी को उपलब्ध कराई जाएं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएंः डीएम

आईपीके, जौनपुरः जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की बैठक कर स्वास्थ्य योजनाओं के प्रगति की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान कोविड टीकाकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रतिदिन के प्रिकाशन डोज के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्ययोजना बनाकर कोविड प्रिकाशन डोज का टीकाकरण कराना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाने में प्रगति लाने को कहा। उन्होंने इन योजनाओं में कम प्रगति लाने वाले एम.ओ.आई.सी. से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी एम.ओ.आई.सी. सहित मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी का जलस्तर घटने के बाद प्रभावित ग्रामों में पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव एवं संक्रामक बीमारियों के

रोकथाम हेतु प्रत्येक पी.एच.सी. स्तर पर पर्याप्त मात्रा में जीवनोपयोगी दवाइयों की उपलब्धतता सुनिश्चित की जाए। समीक्षा के दौरान ए.एन.सी. पंजीकरण के कम प्रगति पर जिलाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि गर्भवती महिलाओं का चिह्नीकरण करते हुए ए.एन.सी. पंजीकरण की प्रगति बढ़ाई जाए। साथ ही प्रत्येक सभी गर्भवती महिलाओं के हीमोग्लोबिन की जांच की जाए। एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर नवजात बच्चों के वजन की फीडिंग कराई जाए। बैठक में परिवार नियोजन कार्यक्रम, एन.आर.सी., एल.बी.एस.यू., राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा की गई।

मासिक धर्म के बारे में खुलकर चर्चा करने की जरूरतः सीडीपीओ

आईपीके, जौनपुरः नगर के 200 तथा सिरकोनी के 226 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सम्भव अभियान के तहत किशोरी दिवस का आयोजन हुआ। इसके तहत नौ वर्ष से 19 वर्ष तक की किशोरियों को एनीमिया, मासिक धर्म प्रबंधन, साफ-सफाई तथा आयरन युक्त भोजन के बारे में जागरूक किया गया।

सिरकोनी के बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि कुछ शोधों से पता चलता है कि 75 प्रतिशत किशोरियां मासिक धर्म होने को शर्मिंदगी की बात समझती हैं। 72 प्रतिशत किशोरियां मासिक धर्म के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। 27 प्रतिशत खुद सेनेटरी नेपकिन खरीद कर लाती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म एक सर्वव्यापी तथा प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। जरूरत है हर घर में मासिक धर्म के बारे में खुलकर चर्चा की जाए। इसके लिए आंगनबाड़ी के

- **सम्भव अभियान के तहत किशोरी दिवस का हुआ आयोजन**

स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। सिरकोनी ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्र नेवादा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गीता यादव ने किशोरियों को बताया कि किशोरावस्था में तमाम शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसमें मासिक धर्म भी एक प्रमुख परिवर्तन है। मासिक धर्म सर्वव्यापी एवं प्राकृतिक प्रक्रिया है। अहमदपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अमिता ने बताया कि मासिक धर्म के दौरान नेपकिन का प्रयोग करना चाहिए। सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध न होने पर सूखा और साफ कपड़ा प्रयोग करना चाहिए। कल्याणपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इंद्रा प्रजापति ने बताया कि खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसलिए आयरन युक्त भोजन करना जरूरी है। मनहन की गीता यादव ने बताया कि प्रत्येक सप्ताह आयरन की गोली खाना चाहिए। खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए। परियावां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माधुरी ने कहा कि मासिक धर्म में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और साफ-सुधरे कपड़े पहनना चाहिए। इसी तरह से राजेपुर की निर्मला, नाथूपुर की मंजू, सिरकोनी गांव की जयदेवी, समोपुर की मीरा रानी व शाहबड़ेपुर की आरती प्रजापति सहित अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किशोरियों को जानकारी दी। वहीं नगर क्षेत्र में वाजिदपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऊषा, नईगंज की किरन, असीरगढ़ टोला की शहनाज़ बानो, चकप्यार अली की कनीज ने किशोरियों को एनीमिया, मासिक धर्म प्रबंधन, साफ-सफाई तथा आयरन युक्त भोजन के बारे में जानकारी दी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी मतदेय स्थलों की जानकारी

आईपीके, जौनपुरः उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम प्रकाश की अध्यक्षता में मतदेय स्थल सम्भाजन के सम्बंध में विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों तथा सम्बंधित अधिकारियों के साथ बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि सम्भाजनोपरांत मतदेय स्थलों की कुल संख्या 3,495 है।

364 बदलापुर विधानसभा के अंतर्गत पूर्व में मतदान स्थलों की संख्या 402 थी, सम्भाजनोपरांत मतदेय स्थलों की संख्या 345 है। इसी प्रकार 365 शाहगंज विधानसभा में पूर्व मतदेय स्थल 444 थे, सम्भाजनोपरांत मतदेय स्थलों की संख्या 385 है। 366 जौनपुर विधानसभा में पूर्व मध्य स्थलों की संख्या 483 थी, सम्भाजनोपरांत मतदेय स्थलों की संख्या 421 है। 367 मल्हनी में मतदेय स्थलों की संख्या 428 थी, सम्भाजनोपरांत मतदेय स्थलों की संख्या 387 है। 368 मुंगराबादशाहपुर में पूर्व मतदेय स्थलों की संख्या 444 थी, सम्भाजनोपरांत मतदेय स्थलों की संख्या 398 है। 369 मछलीशहर (अ.जा.) में पूर्व मतदेय स्थलों की संख्या 451 थी, सम्भाजनोपरांत मतदेय स्थलों की संख्या 402 है। 370-मड़ियाहूं में पूर्व में मतदेय स्थलों की संख्या 381 थी, सम्भाजनोपरांत मतदेय स्थलों की संख्या 343 हैं। 371 जफराबाद में पूर्व में मतदेय स्थलों संख्या 427 थी, सम्भाजनोपरांत मतदेय स्थलों की संख्या 389 है। 372 केराकत (अ.जा.) में पूर्व मध्य स्थलों की संख्या 488 थी, सम्भाजनोपरांत मतदेय स्थलों की संख्या 425 है।

अपर जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को कहा कि इस सम्भाजन में अगर किसी प्रकार से आप लोगों के सुझाव हों, तो उपलब्ध कराएं ताकि निस्तारित करके समय से चुनाव आयोग को प्रेषित किया जा सके। इस अवसर पर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश चतुर्वेदी, महमूद अली सहित अन्य उपस्थित रहे।

अवैध शराब बिक्री पर होगी सख्त कार्यवाहीः डीएम

जौनपुरः जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट जनपद के अनुज्ञापियों एवं आबकारी निरीक्षकों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अनुज्ञापी अपनी दुकान से वैध माल की बिक्री ही करें। अगर कहीं से भी गड़बड़ी की सूचना मिली या संलिप्तता पाई गई, तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि आस-पास नजर रखें कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से शराब की बिक्री तो नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो तुरंत इसकी जानकारी आबकारी विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों को दें ताकि कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आबकारी विभाग लगातार अभियान चलाकर अवैध शराब के कारोबार में अंकुश लगाने की कार्यवाही करे। सभी अनुज्ञापी नियमों के अनुसार ही दुकानों का संचालन करें। जिलाधिकारी ने कहा कि दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरा शत-प्रतिशत चलते रहें। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान में पुलिस पूरा सहयोग करेगी। इसके साथ ही अगर किसी लाइसेंसी दुकान पर अवैध शराब की बिक्री होती पाई जाती है, तो सेल्स मैन व अनुज्ञापी

- **आबकारी बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश**

पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिया कि अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं/तस्करों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। संदिग्ध वाहनों की सघनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग किया जाना राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबों, जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रुकते हैं, की सघन एवं आकस्मिक जांच की जाए। अवैध मदिरा के संदिग्ध स्थानों/अड्डों पर छापेमारी की कार्यवाही की जाए।

संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए उनकी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए। यह सामने आया है कि अधिकांश देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर अनुज्ञापनों पर समयान्तर्गत उनके एम.जी.क्यू/एम.जी.आर. के सापेक्ष या तो उठान नहीं हो रहा है अथवा उसके बराबर उठान की ही प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक होने के साथ राजस्वहित के विपरीत है। अतः ऐसे सभी अनुज्ञापियों को निर्देशित किया कि सम्बंधित अनुज्ञापनों पर उसकी अपेक्षित बिक्री के अनुसार समयान्तर्गत निकासी कराना सुनिश्चित करें। राजस्व प्राप्ति के परम्परागत स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से राजस्व प्राप्त करने हेतु होटल/रेस्टोरेन्ट के स्वामियों/संचालकों से सम्पर्क कर उनको बार/ओकेजनल बार के अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु नई बार नियमावली के प्रावधानों के संबंध में जानकारी देते हुए उन्हें प्रेरित किया जाए। जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी जी.एस. मिश्र से कहा कि निर्देशों का नियमित क्रियान्वयन करते हुए अवैध मदिरा के कारोबार पर अंकुश लगाकर मंदिरा उपभोग/उठान में अपेक्षित वृद्धि प्राप्त करने का भरपूर प्रयास करना सुनिश्चित करें, जिससे जनपद के निर्धारित राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

सेवानिवृत्त हुए राजर्षि टंडन मुक्त विवि के वित्त अधिकारी

आईपीके, प्रयागराजः उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वित्त अधिकारी अजय कुमार सिंह बुधवार 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने कहा कि वित्त अधिकारी श्री सिंह का कार्यकाल उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा। उन्हें वित्तीय नियमों की गहरी समझ है, जिसका उन्होंने सही ढंग से अनुपालन किया। उनकी जिंदगी सकारात्मकता से भरपूर है। व्हीलचेयर उनके जीवन में कोई बाधा नहीं है। विश्वविद्यालय को जब भी उनकी आवश्यकता होगी, उनके अनुभवों का लाभ लिया जाएगा। उन्होंने वित्त अधिकारी श्री सिंह के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की

इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने वित्त अधिकारी श्री सिंह को अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। तिलक सभागार में विदाई समारोह का संचालन डॉ. देवेश रंजन त्रिपाठी ने किया। स्वागत कुलसचिव प्रोफेसर पी.पी. दुबे ने व धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर आशुतोष गुप्ता

ने किया। इस अवसर पर वित्त अधिकारी अजय कुमार सिंह ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि 4 वर्ष कब बीत गए, उन्हें पता ही नहीं चला। विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों का सहयोग उन्हें हमेशा मिलता रहा। जिस वजह से उन्हें कार्य करने में कभी कोई परेशानी नहीं आई। इस अवसर पर वित्त अधिकारी श्री सिंह अपनी जीवन यात्रा का वृतांत सुनाते हुए भावुक हो गए। विदाई समारोह में अवनीश चंद्रा, प्रोफेसर सत्यपाल तिवारी, डॉ. श्रुति, प्रोफेसर एस. कुमार, प्रोफेसर रुचि बाजपेई आदि ने उद्गार व्यक्त किए। इस मौके पर इंदु भूषण पाण्डेय एवं डॉ. प्रभात चंद्र मिश्र ने वित्त अधिकारी श्री सिंह की विश्वविद्यालय की स्मृतियों को संजोते हुए उन्हें एक कोलॉज भेंट किया।

आईजीआरएस पोर्टल की जानकारियों से अवगत रहें अधिकारी

आईपीके, झांसीः झांसी के मंडलायुक्त संजय गोयल ने तहसील स्तर पर प्राप्त राजस्व सम्बंधी प्रकरणों के निस्तारण की गुणवत्ता खराब होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि तहसील स्तर पर प्राप्त होने वाले राजस्व सम्बंधी आईजीआरएस प्रकरणों को लेकर सभी उपजिलाधिकारी गम्भीर रहें, अन्यथा सम्बंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

मंडलायुक्त ने अफसरों को निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी और सह-नोडल अधिकारी आईजीआरएस पोर्टल की जानकारियों से अवगत रहें। पोर्टल की सही जानकारी के अभाव में निस्तारण की गुणवत्ता में कमी के कारण शिकायतों में वृद्धि होती है, इसलिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पोर्टल की जानकारियों से भली-भांति परिचित होना अतिआवश्यक है। मंडल के तीनों जनपदों के जिलाधिकारी अगले 10 दिनों के भीतर सम्बंधित कार्मिकों का आईजीआरएस पोर्टल सम्बंधी प्रशिक्षण आयोजित कर आख्या उपलब्ध कराएं। मंडलायुक्त श्री गोयल आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति सम्बंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक जनपद

- **राजस्व मामलों के निस्तारण में लापरवाही पर मंडलायुक्त ने जताई नाराजगी**

झांसी, ललितपुर एवं जालौन के नोडल, सह-नोडल अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि तीनों जनपदों में प्राप्त होने वाले आईजीआरएस संदर्भों के निस्तारण के गुणवत्ता की प्रगति की अब आयुक्त कार्यालय से विशेष निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों की आख्या को ही उच्च स्तर पर भेजा जा रहा है, इसलिए अपलोड की जाने वाली आख्याएं सक्षम, नोडल अधिकारी के स्तर से अनुमोदित कराकर अपलोड की जाएं। जिन प्रकरणों में गवाहों के नाम एवं हस्ताक्षर की आवश्यकता है, उनमें गवाहों के नाम एवं हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएं। न्

संपादकीय

आनन्द संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1943, भाद्रपद

स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ी सम्पत्ति, वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है।

समर्थ भारत का प्रतीकः विक्रांत

जब विश्व के अधिकांश देश पिछड़े हुए थे, तब भारत समृद्ध राष्ट्र था। अंग्रेजों के शासन से पूर्व यह विश्व के धनी राष्ट्रों में से एक था। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। केरल के समुद्री तट पर पूरा भारत एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा था। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा यह भव्य आयोजन, विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार था। यदि लक्ष्य दुरंत हो, यात्राएं दिगंत हो, समंदर और चुनौतियां अनंत हों, तो भारत का उत्तर विक्रांत है। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिम्ब है विक्रांत। यह युद्धपोत से ज्यादा तैरता हुआ एयरफील्ड है, जबकि यह तैरता हुआ शहर जैसा है। प्रधानमंत्री मोदी के एक आंकलन के अनुसार, इसमें जितनी बिजली पैदा होती है, उससे 5,000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइंग डेक भी दो फुटबॉल फील्ड से बड़ा है। इसमें जितने तार इस्तेमाल हुए हैं, वह कोचीन से काशी तक पहुंच सकते हैं। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है।

इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है, वो स्टील भी स्वदेशी है वहीं दूसरी तरफ चीन के पास पूरी तरह से सक्रिय दो विमानवाही हैं। उनमें से एक तो नए विक्रांत से करीब दोगुना बड़े आकार का है और पूरी तरह से देसी है, जो न केवल ज्यादा विमान ढो सकता है बल्कि जे-15 या एसयू-30 के चीनी संस्करणों जितना शक्तिशाली है। तीसरा विमानवाही युद्धपोत चीन अपनी गति से अगले वर्ष ही कमीशन कर सकता है और यह एक लाख टन वाला होगा। ऐसी राष्ट्रीय उपलब्धि की अनदेखी दुर्लभ किस्म का कोई भारतीय ही कर सकता है या फिर युद्ध से नफरत करने और शांति की पैरवी करने वाली दुर्लभ जमात का कोई शख्स ही कर सकता है। हम इन लोगों में से नहीं हैं इसलिए भारतीय नौसेना, इसके जहीन तथा प्रगतिशील डिजाइन ब्यूरो, इंजीनियरों, समुद्री युद्ध के मामले में दूरदर्शिता रखने वालों और बेशक पिछले 25 वर्षों में भारत का नेतृत्व करने वाले तीन प्रधानमंत्रियों (अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू करके नरेंद्र मोदी तक) के कार्यकाल को बधाई। वाजपेयी के कार्यकाल में ही इस 'मेक-इन-इंडिया' या 'आत्मनिर्भर' युद्धपोत की डिजाइनिंग शुरू हुई थी। उनके नेतृत्व में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमिटी ने इसके निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी थी। सवाल उठाया जा सकता है कि देश में इंजीनियरिंग का विशाल आधार होने के बावजूद इस युद्धपोत को नौसेना के बेड़े में शामिल करने में 23 साल क्यों लग गए ? खासकर तब जबकि चीन इससे कहीं बड़ा युद्धपोत तीन-चार वर्षों में तैयार कर लेता है और वैसे भी नए 'विक्रांत' का इंजन अमेरिका की जीई कम्पनी से आयात किया गया है। लगभग पांच दशकों तक भारत का झंडा लहराने वाले भारतीय नौसेना के प्रथम विमानवाही युद्धपोत आईएनएस-विक्रांत के नए अवतार की कमीशनिंग देश के लिए जश्न मनाने का मौका है और इसकी वजह भी है। मूल पोत तो 16,000 टन का था, मगर यह उससे तीन गुना अधिक 42,800 टन का है। यह न केवल भारत में डिजाइन किया गया, बल्कि स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। यह बेहद गौरव की बात है क्योंकि इसने भारत को उन विशिष्ट देशों की जमात में शामिल कर दिया है, जो इस तरह के युद्धपोत बनाने में सक्षम हैं। यह जमात इतनी विशिष्ट है कि उन्हें आप अपने एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं। वैसे, फिलहाल हम ब्रिटेन को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं।

शिक्षक की गरिमा

भारतीय संस्कृति में गुरु या शिक्षक को ऐसे प्रकाश के स्रोत के रूप में ग्रहण किया गया है, जो ज्ञान की दीप्ति से अज्ञान के आवरण को दूर कर जीवन को सही मार्ग पर ले चलता है। उसका स्थान सर्वोपरि होता है, उसे 'साक्षात परब्रह्म' तक कहा गया है। आज भी सामाजिक, आध्यात्मिक और निजी जीवन में बहुत सारे लोग किसी न किसी गुरु से जुड़े मिलते हैं। गुरु से प्रेरणा पाने और उनके आशीर्वाद से मनोरथों की पूर्ति की कामना आम बात है यद्यपि गुरु की संस्था में इस तरह के विश्वास का कुछ छद्म गुरु नाजायज फायदा भी उठाते हैं और गुरु-शिष्य के पावन सम्बंध को लांछित करते हैं। शिक्षा के औपचारिक क्षेत्र में गुरु या शिक्षक एक अनिवार्य कड़ी है, जिसके अभाव में ज्ञान का अर्जन, सृजन और विस्तार सम्भव नहीं है। भारत में शिक्षक दिवस डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति को जीवंत करता है, वे एक महान अध्यापक और राजनयिक थे जिन्होंने अपने अध्यवसाय से एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर देश-विदेश में दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित की और राष्ट्रपति के शीर्ष पद को सुशोभित किया। वे आज भी वैदुष्य की दृष्टि से प्रेरणा-स्रोत हैं। भारतीय समाज की स्मृति में धौम्य-उद्दालक, चाणक्य-चंद्रगुप्त, समर्थ गुरु रामदास-शिवा जी महाराज और रामकृष्ण परमहंस-विवेकानंद जैसी गुरु-शिष्य की जोड़ियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने युगांतरकारी उपलब्धियां हासिल कीं और देश काल की धारा बदल दी। यह सूची बड़ी लम्बी है। गुरु निश्छल, प्रपंचों से दूर और वीतराग तपस्वी हुआ करते थे। समय बीतने के साथ शिक्षण और दीक्षा के स्वरूप और गरिमा में बदलाव आता गया। गुरु की संस्था समाज का दायित्व थी और गुरु स्वतंत्र रहता था। उसका कार्य चिंतन, मनन और लोक-कल्याण के लिए अपनी साधना से ज्ञान को उपलब्ध कराना था। बदलते दौर में गुरु की महिमा घटनी शुरू हुई। व्यवस्था के अंतर्गत वह नौकर-चाकर बन गया। उसकी प्रवृत्ति बदलने लगी और ज्ञान अर्जित करने की जगह वह कमाई करने लगा। शैक्षिक संस्थाओं के सरकारीकरण और फिर निजीकरण के साथ शिक्षा जगत पर बाजार का असर शुरू हुआ। शिक्षा व्यापार का रूप लेने लगी और विद्यार्थी अंततः धनार्थी बनता गया। अर्थ की अंतहीन स्पृहा ने शिक्षा जगत को आग़ोश में लेना शुरू किया। धर्म की परिधि में विद्या और अर्थ की चिंता करने की हिदायत बिसरती गई। आज प्रवेश, परीक्षा, उपाधि, नौकरी और शोध-प्रकाशन हर क्षेत्र में शॉर्टकट से काम हो जाए, इसके जुगाड़ में शिक्षक और शिक्षार्थी व्यस्त हो रहे हैं। साहित्यिक चोरी (प्लैगेरिज्म) किस तरह रोग की तरह फैला है सर्वविदित है। इन सबके फलस्वरूप शिक्षा के मानक गिरते जा रहे हैं। इन सबके बीच शिक्षक की भूमिका प्रश्नांकित होने लगी है।

आत्मनिर्भर भारतः स्वदेशी से स्वावलम्बन का संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 02 सितम्बर को देश के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित कर ऐतिहासिक पल में बदल दिया है। नए नौसेना ध्वज का अनावरण किया है। यह आत्मनिर्भर भारत की प्रगति का स्वर्णिम सोपान है। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान शानदार तरीके से सफलताओं का आसमान चूम रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसमें स्वदेशी से स्वावलम्बन का संकल्प समाहित है। इस अभियान के अंतर्गत हुए अनेक कार्य विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित हुए हैं। दुनिया भारत के सामर्थ्य को देख रही है। कोरोना वैक्सीन के अलावा रक्षा उत्पाद में भी भारत की विशिष्ट पहचान बनी है। आठ वर्ष पहले तक इस प्रकार की उपलब्धियों की कल्पना करना भी सम्भव नहीं था। पहले की सरकारें वैक्सीन या रक्षा सामग्री के क्षेत्र में आयात पर निर्भर रहती थी। तब आयात करने को ही बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया जाता था। अनेक उत्पाद तो भारत कई दशक के बाद भी आयात करता था। ऐसा नहीं कि उस समय हमारे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों में प्रतिभा नहीं थी, किन्तु पहले की सरकारों में इच्छाशक्ति का अभाव था। देश को आत्मनिर्भर बनाने का मंसूबा नहीं था। नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की क्षमताओं को पहचाना। उनको सम्मान दिया। आमजन को भी प्रेरणा दी। इनके बल पर ही नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारम्भ किया था। इसके पीछे उनका आत्मविश्वास था, इसलिए सरकार ने सड़कों की संख्या में रक्षा सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। आत्मविश्वास यह था कि अब इनका उत्पादन भारत में होगा। सेना को जरूरी रक्षा सामग्री कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

कुछ देशों को निर्यात के साथ शुरू हुई यह यात्रा अब तक 75 देशों तक पहुंच चुकी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य पूरा हो रहा है। इसके दो पहलू हैं। एक भारत को स्वदेशी की भावना से सामरिक महाशक्ति बनाना, दूसरा भारत को रक्षा उत्पाद का बड़ा निर्यातक बनाना। भारत को आर्थिक और शक्तिशाली बनाने के लिए सौ लाख करोड़ रुपए की योजना के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के सिस्टम में बदलाव से घोटालों को रोका गया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस सरकार में कोई भी घोटाले का प्रयास नहीं कर सकता है। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया योजना सफलता के साथ आगे बढ़ रही है। अगले तीन वर्षों में 13 हजार करोड़ रुपए का निर्यात 50 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। 300 सुरक्षा यंत्र अब भारत में ही बनेंगे। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से देश को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बीते वर्ष में वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग लगभग दो ट्रिलियन यूएस डॉलर पर पहुंच चुकी थी। डिफेंस रिलेटेड डोमेस्टिक डिमांड में भी बढ़ोत्तरी होगी। देश का विकास पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच समन्वय से हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 20 साल पहले डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के सौ प्रतिशत प्रतिभागिता की व्यवस्था की थी। कास्टिंग और फोर्जिंग के क्षेत्र में जिन भारतीय कम्पनियों ने दुनिया में बड़ा नाम कमाया है पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड उनमें से एक है। पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एयरोस्पेस और एयरोस्पेस में टाइटेनियम और निकिल के आलाय बनाने वाली पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया था। भारत के अलावा अमेरिका, फिनलैंड, चीन, नॉर्वे व स्वीडन की बड़ी और प्रतिष्ठित कम्पनियों को पीटीसी द्वारा अपने उत्पाद उपलब्ध कराए

जा रहे हैं। रक्षा विनिर्माण सुविधा विमान के इंजन, हेलीकॉप्टर इंजन, विमानों के लिए संरचनात्मक भागों, ड्रोन और यूएवी, पनडुब्बियों, अल्ट्रा लाइट आर्टिलरी गन, स्पेस लॉन्च व्हीकल और स्ट्रैटेजी सिस्टम आदि का निर्माण करेगी। कई भूमिकाओं में काम आने वाले दस टन के भारतीय हेलीकॉप्टर के डिजाइन और विकास में तेजी लाई जा रही है। हेलीकॉप्टर प्रौद्योगिकी में प्रगति रक्षा क्षेत्र के लिए प्रभावी होगी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी। अब तक निर्मित लगभग 700 चेतकों ने पूरे समर्पण के साथ युद्ध और शांति के समय में राष्ट्र की सेवा की है।

भारत ने स्वदेश में डिजाइन और विकसित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव और इसके वेरिएंट का निर्माण किया। पांच टन की श्रेणी में हेलीकॉप्टरों के डिजाइन, विकास और संचालन में अपनी ताकत दिखाई है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को युद्ध अभियानों के लिए हल्के हेलीकॉप्टरों में देश की क्षमता का यह एक उदाहरण है। वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए रक्षा उत्पादन और तैयारियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने का सरकार ने संकल्प लिया है। गत वर्ष डीआरडीओ ने उद्योग के साथ सवा दो सौ लाइसेंस समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की है। अब भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर रहा है। फाइटर प्लेन हेलीकॉप्टर, टैंक और पनडुब्बियों सहित के निर्माण के अवसर भी मेगा डिफेंस प्रोग्राम के तहत शुरू किए हैं। डीआरडीओ के माध्यम से निःशुल्क ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यूपी और तमिलनाडु के बीच शुरू की गई है। ट्रांसपोर्ट प्लेन सी का 22 हजार करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। इनमें अधिकांश प्लेन इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाए जाएंगे। विगत सात वर्षों में डिफेंस एक्सपोर्ट का 38 हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। 10 हजार एमएसएमई का डिफेंस सेक्टर से जुड़ना प्रगति का

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य पूरा हो रहा है। इसके दो पहलू हैं। एक भारत को स्वदेशी की भावना से सामरिक महाशक्ति बनाना, दूसरा भारत को रक्षा उत्पाद का बड़ा निर्यातक बनाना। भारत को आर्थिक और शक्तिशाली बनाने के लिए सौ लाख करोड़ रुपए की योजना के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के सिस्टम में बदलाव से घोटालों को रोका गया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस सरकार में कोई भी घोटाले का प्रयास नहीं कर सकता है। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया योजना सफलता के साथ आगे बढ़ रही है। अगले तीन वर्षों में 13 हजार करोड़ रुपए का निर्यात 50 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। 300 सुरक्षा यंत्र अब भारत में ही बनेंगे। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से देश को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बीते वर्ष में वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग लगभग दो ट्रिलियन यूएस डॉलर पर पहुंच चुकी थी। डिफेंस रिलेटेड डोमेस्टिक डिमांड में भी बढ़ोत्तरी होगी। देश का विकास पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच समन्वय से हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 20 साल पहले डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के सौ प्रतिशत प्रतिभागिता की व्यवस्था की थी। कास्टिंग और फोर्जिंग के क्षेत्र में जिन भारतीय कम्पनियों ने दुनिया में बड़ा नाम कमाया है पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड उनमें से एक है। पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एयरोस्पेस और एयरोस्पेस में टाइटेनियम और निकिल के आलाय बनाने वाली पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया था।

उदाहरण है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भारत का रक्षा निर्यात करीब 40 प्रतिशत बढ़ा है। दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में शुमार लाइट काम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क टू एलसीए के अगले साल के अंत में पहली उड़ान भरने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इस लड़ाकू विमान विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस मंजूरी से उन्नत साढ़े सत्रह टन एकल इंजन विमान विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। नए विमानों का विकास अगले पांच साल तक पूरा होगा। इसके बाद तेजस डिफेंसिव एयरक्राफ्ट का तमगा खोकर अटैक करने वाले लड़ाकू विमानों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा सम्बंधी कैबिनेट समिति ने स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करने के लिए की जा रही पहलों को बढ़ावा देने के लिए एलसीए मार्क टू लड़ाकू विमान के प्रोटोटाइप विकास को मंजूरी दे दी, जो वायु सेना में मिराज-2000 जगुआर और मिग लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ विमान को जीई-414 इंजन के साथ विकसित करेगा, जो जीई-404 का उन्नत संस्करण है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऑर्डर किए गए 80 से अधिक एलसीए मार्क वन में जीई-404 इंजन लगाया गया है। तेजस मार्क टू की गति मैक टू यानी करीब साढ़े तीन हजार किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसकी मारक रेंज ढाई हजार किलोमीटर होगी। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली सात मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली चार मिसाइलें, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल व पांच बम लगाए जा सकते हैं। तेजस मार्क टू में ब्रह्मोस-एनजी मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा निर्भय, स्टॉर्म शैडो, अस्त्र, मीटियोर, असराम और क्रिस्टल मेज जैसी मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं।

-डॉ. दिलीप अग्निहोत्री
(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

डरावनी तस्वीर पेश करते आत्महत्या के आंकड़े

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने वर्ष 2021 में भारत में विभिन्न कारणों से आत्महत्याओं के मामलों को लेकर जो रिपोर्ट जारी की, वह बेहद डरावनी है। दरअसल, देश में आत्महत्या के मामलों में हर साल बढ़ोत्तरी हो रही है और रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज देश भर में 450 व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या के ये आंकड़े डराने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि जहां वर्ष 2021 में पूरे देश में हुए करीब 4.22 लाख सड़क हादसों में कुल 1.73 लाख लोगों की मौत हुई, वहीं कम से कम 1,64,033 लोगों ने तो आत्महत्या करके ही अपनी जीवनलीला समाप्त कर डाली। समाज विज्ञान के जानकारों के अनुसार, बढ़ती महंगाई तथा आम आदमी की लगातार घटती कमाई आत्महत्या के मामले बढ़ने का प्रमुख कारण है। कमाई कम होने या रोजगार नहीं होने के कारण लोगों में तनाव बहुत बढ़ गया है, जिससे बहुत से मामलों में पारिवारिक क्लेश पैदा होता है और परिणामस्वरूप आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। वर्ष 2016 में जहां आत्महत्या के कुल 10,64,033 मामले दर्ज हुए थे और 2017 में 1.29 लाख लोगों ने आत्महत्या की थी, वहीं 2017 से 2021 तक ये मामले 26 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 1.64 लाख से भी ज्यादा हो गए। विशेषज्ञों के मुताबिक, अवसाद और तनाव के कारण लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है और जब व्यक्ति को परेशानियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वह आत्महत्या जैसा हृदयविदारक कदम उठा बैठता है। हालांकि, जिन लोगों का मनोबल मजबूत होता है, वे प्रायः विकट परिस्थितियों से उबर भी जाते हैं लेकिन अवसाद के शिकार कुछ लोग विषम परिस्थितियों से लड़ने के बजाय हालात के समक्ष घुटने टेक स्वयं को मौत के हवाले कर देते हैं। आत्महत्या करने वालों में करीब 64 फीसदी यानी 1.05 लाख लोग ऐसे हैं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम थी।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते वर्ष देश में कुल 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से 1,18,979 पुरुष, 45,026 महिलाएं और 28 ट्रांसजेंडर थे। आत्महत्या करने वाली आधी से भी ज्यादा 23,178 गृहणियां थी जबकि 5,693 छात्राओं और 4,246 दैनिक वेतनभोगी महिलाओं ने आत्महत्या की। गृहणियों द्वारा आत्महत्या के सर्वाधिक मामले तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रमशः 3221, 3055, 2861 दर्ज किए गए, जो गृहणियों द्वारा की गई आत्महत्या के मामलों का क्रमशः 13.9, 13.2 और 12.3 फीसदी है। आत्महत्या के मामलों में महिला पीड़ितों का अनुपात दहेज जैसे विवाह सम्बंधी मुद्दों, नपुंसकता और बांझपन में अधिक देखा गया। पेशेवर समूहों में स्वरोजगार करने वालों में भी आत्महत्या के मामले करीब 16.73 फीसदी बढ़े हैं। देश में 2020 में आत्महत्या के कुल

आत्महत्या के मामलों का विश्लेषण करें तो सर्वाधिक चिंता देश के युवा वर्ग और 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर होती है। मनोचिकित्सकों का मानना है कि वर्तमान में भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर मानसिक तनाव में रहते हैं और तनाव की वजह से ही आत्महत्या करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। कोई पारिवारिक कलह को लेकर तो कोई व्यवसाय को लेकर तनाव में है और ऐसी स्थिति में लोग अपनी बेशकीमती जिंदगी को ही दांव पर लगा रहे हैं। यह प्रवृत्ति न केवल ऐसे व्यक्ति के परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है।

1,53,052 मामले दर्ज हुए थे और 2021 में आत्महत्या की दर में 7.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, 33.2 फीसदी लोगों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण, जबकि 18.6 फीसदी ने बीमारी के कारण मौत को गले लगाया। आत्महत्या के अन्य मुख्य कारणों में 6.4 फीसदी मादक पदार्थों का सेवन और शराब की लत, 4.8 फीसदी विवाह सम्बंधी मुद्दे, 4.6 फीसदी प्रेम-प्रसंग, 3.9 फीसदी दिवालियापन या कर्ज, 2.2 फीसदी बेरोजगारी, 1.6 फीसदी पेशेवर करियर की समस्या, 1.1 फीसदी गरीबी और 01 फीसदी परीक्षा में असफलता शामिल रहे। आत्महत्या करने वालों में 18-30 वर्ष से कम आयु वर्ग के 34.5 फीसदी और 30-45 वर्ष से कम आयु के 31.7 फीसदी लोग शामिल हैं, जबकि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में 3,233 आत्महत्याएं पारिवारिक समस्याओं के कारण, 1,495 प्रेम सम्बंध और 1,408 बीमारी के कारण हुई। एनसीआरबी के मुताबिक, आत्महत्या की सर्वाधिक प्रवृत्ति महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में देखी गई है। केवल इन पांच राज्यों में ही देश भर में आत्महत्या के कुल मामलों में से 50.4 फीसदी मामले दर्ज हुए जबकि 49.6 फीसदी मामले 23 अन्य राज्यों और 08 केंद्रशासित प्रदेशों में सामने आए। पिछले एक साल में उपरोक्त पांच राज्यों में क्रमशः 22207, 18925, 14965, 13500, 13056 लोगों ने आत्महत्या की, जो कुल मामलों का क्रमशः 13.5, 11.5, 9.1, 8.2 और 08 फीसदी है। प्रति एक लाख की आबादी पर आत्महत्या के मामलों की राष्ट्रीय दर हालांकि 12 रही, लेकिन कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थिति बेहद चिंताजनक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह दर 39.7, सिक्किम में 39.2, पुडुचेरी में 31.8, तेलंगाना 26.9 और केरल में 26.9 दर्ज की गई।

एनसीआरबी की रिपोर्ट में दिहाड़ी मजदूरों और कृषि श्रमिकों की आत्महत्या के मामले भी मन को विचलित करने वाले हैं। रिपोर्ट में यह चिंताजनक खुलासा हुआ है कि देश भर में आत्महत्या करने वालों में सबसे ज्यादा 25 फीसदी लोग दिहाड़ी मजदूर ही थे। 2020 में जहां कुल 33,164 दिहाड़ी मजदूरों ने जीवन की परेशानियों से निजात पाने के लिए आत्महत्या का रास्ता चुना, वहीं 2021 में कुल 42,004 दिहाड़ी मजदूरों ने खुदकुशी की। कृषि क्षेत्र से सम्बद्ध कुल 10,881 लोगों ने आत्महत्या की, जो कुल मामलों का 6.6 फीसदी है। इनमें 2019 में 5,957 और 2020 में 5,579 किसानों की आत्महत्या के मुकाबले यह आंकड़ा 2021 में कम होकर 5,318 दर्ज हुआ, लेकिन कृषि श्रमिकों में आत्महत्या की दर लगातार बढ़ रही है। 2021 में कुल 5,563 कृषि श्रमिकों ने आत्महत्या की और उनकी आत्महत्या की दर 2020 के मुकाबले 09 फीसदी और 2019 के मुकाबले 29 प्रतिशत अधिक रही। बीते वर्ष के दौरान हर दो घंटे में कम से कम एक कृषि श्रमिक ने मौत को गले लगाया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, किसान वह है, जिनका व्यवसाय कृषि है और जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं या पट्टे की जमीन पर बिना कृषि मजदूरों की मदद के खेती करते हैं जबकि कृषि श्रमिक वे हैं, जो मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी आय का स्रोत कृषि मजदूरी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि विगत दो वर्षों के दौरान जब कई आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई और शहरों से गांवों की ओर पलायन हुआ, तब कई दिहाड़ी मजदूरों ने कृषि श्रमिक के रूप में भी काम किया क्योंकि उनके आय के अन्य स्रोत बंद थे। अपनी रिपोर्ट में एनसीआरबी ने आत्महत्या की घटनाओं के पीछे पेशेवर या करियर सम्बंधी समस्याओं, अलगाव की भावना, दुर्व्यवहार, हिंसा, पारिवारिक समस्याओं, मानसिक विकार, शराब की लत, वित्तीय नुकसान, पुराने दर्द इत्यादि को मुख्य कारण माना है। हालांकि, आत्महत्या के मामलों का विश्लेषण करें तो सर्वाधिक चिंता देश के युवा वर्ग और 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर होती है। मनोचिकित्सकों का मानना है कि वर्तमान में भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर मानसिक तनाव में रहते हैं और तनाव की वजह से ही आत्महत्या करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। कोई पारिवारिक कलह को लेकर तो कोई व्यवसाय को लेकर तनाव में है और ऐसी स्थिति में लोग अपनी बेशकीमती जिंदगी को ही दांव पर लगा रहे हैं। यह प्रवृत्ति न केवल ऐसे व्यक्ति के परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है। हालांकि, माना जाता रहा है कि आत्महत्याओं को रोकना सरकार का काम नहीं है बल्कि इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज और परिवार की है लेकिन आत्महत्या के बीते वर्ष के आंकड़े समाज के साथ-साथ सरकार के समक्ष भी गम्भीर सवाल खड़े कर रहे हैं।

-योगेश कुमार गोयल

बंदरों का दुख

व्यंग्य

अभी हाल में ही अचानक एक दिन मेरा ध्यान बंदरों के उस गुट की ओर चला गया, जो दशकों तक कद्दावर रहे और अपने समाज की भलाई के लिए हमेशा उछल-कूद करते रहे लेकिन अब कुछ महीनों से यह मौन धारण किए हुए हैं। इनकी तमाम समस्याओं के बारे में भी मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला, सो मैं सच्चाई परखने के लिए हर पहलू का मंथन करने लगा। सवाल यह था कि ये लोग जो कह रहे थे, वह सही था या नहीं ? आखिर बंदरों का भी अपना मान-सम्मान होता है। वह भी दलबाजी में विश्वास करते हैं। इनका भी हर दल में एक सरदार होता है और उसकी बिरादरी के लोग उससे अदब से पेश आते हैं। राजनीति कहती है कि जो दल का नेतृत्व करता है, वह उसके विस्तार के लिए संघर्ष करता रहता है, लेकिन इस दल के बूढ़े बुद्धिजीवियों का दुख है कि उनका दल साल दर साल सिमटता जा रहा है। इसमें जो सरदार है, उसके कुछ सिपहसलार हैं। इनके करीबी ही कह रहे हैं कि वह न तो ढाल हैं और न ही तलवार हैं।

दूसरी तरफ और भी दल हैं, जो फर्श से अर्स तक पहुंच रहे हैं। इसी दुख के कारण एक दिन ऐसा भी आ गया, जब बंदरों ने एक पंचायत बुलाई। इसमें कुछ खास पुराने लोगों को ही बुलाया गया था। पंचों ने मीडिया के लोगों को एक विज्ञप्ति जारी कर कवरेज से मना कर दिया था, लिहाजा मीडिया वालों में इसके प्रति विशेष रूचि पैदा हो गई। बंदरों ने अपनी पंचायत रेल पटरी पर बुलाई थी। इसकी जानकारी के लिए मैंने दल के एक प्रवक्ता से सम्पर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने पंचायत आयोजकों को बागी कह खरी-खोटी सुनाई और फिर फोन काट दिया। आखिर में मैं मंच के पीछे लगे पर्दे के पास पहुंचा और बंदरों की कहासुनी रिकॉर्ड करने लगा। पहला चिंतन का विषय तो यहां यही था कि ट्रैक पर पंचायत क्यों बुलाई गई। यहां यह बता देना उचित होगा कि इस सभा के पंचों में राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और कानून की पीएचडी जैसा ज्ञान भरा था। तपाक से आयोजकों में एक बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मर रहे दल से अच्छा है कि हम दल के लिए मर जाएं और यहां इसके लिए संसाधन भी हैं। मैं उनकी परेशानी को बड़ी आसानी से समझ गया और फोन बंद कर ट्रैक से बाहर आ गया। एक पंच अपनी बात पूरा कर ही रहा था कि ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ी। दूसरे पंच ने बात जारी रखने के लिए कहा। उसने बताया कि अभी इसके यहां पहुंचने में तीन मिनट बाकी हैं। इतने में तीसरा पंच बोल पड़ा। उसका तर्क था कि अब किसी और दल का ड्राइवर ट्रेन दौड़ाता है, इसलिए यह समय से पहुंच रही है। इतने में पंचायत के सभी सदस्य ट्रैक से बाहर हो गए। बाहर आते ही सबकी राय बदल गई। कुछ तो अर्श की ओर जाने वाले दल से सम्पर्क साधने के सूत्र पूछने लगे, तो कुछ अपना अलग दल बनाने के लिए समर्थन मांगने लगे। आखिर में निष्कर्ष यही निकाला गया कि दल ही नहीं रहेगा तो सरदार का क्या ? हम उसी दल के हो लें, जो दल रहे और उसमें दमदार सरदार।

-शरद त्रिपाठी

पितृ पक्षः तर्पण की तिथियां व महत्व

आध्यात्म

हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का काफी महत्व होता है और इस दौरान पितरों का तर्पण व श्राद्ध करना शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक, भाद्रपद के शुक्ल पक्

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश को लगा करारा झटका

नई दिल्ली: अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को झटका लगने वाली खबर है। देश के आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर यानी उत्पादन जुलाई महीने में धीमा पड़कर 4.5 फीसदी रहा, जबकि जून महीने में यह 13.2 फीसदी रहा। बुनियादी उद्योगों की उत्पादन की यह वृद्धि दर पिछले छह महीने में सबसे कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बुधवार 31 अगस्त को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक, आठ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन जुलाई महीने में 4.5 फीसदी रहा है। एक साल पहले इसी महीने में आठ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 9.9 फीसदी रहा था। बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जून में 13.2 फीसदी, मई में 19.3 फीसदी, अप्रैल में 9.5 फीसदी, मार्च में 4.8 फीसदी, फरवरी में 5.9 फीसदी और जनवरी में 4 फीसदी रही थी। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में सालाना आधार पर कोयले का उत्पादन 11.4 फीसदी बढ़ा है जबकि बिजली का उत्पादन 2.2 प्रतिशत बढ़ा। एक साल पहले की तुलना में जुलाई में रिफाइनरी और उर्वरक के उत्पादन में 6.2 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह जुलाई में सीमेंट का उत्पादन 2.1 फीसदी बढ़ा है, जबकि इस्पात का उत्पादन 5.7 फीसदी बढ़ा। हालांकि, कच्चे तेल के उत्पादन में एक साल पहले के मुकाबले 3.8 फीसदी की गिरावट आई है, जबकि जुलाई में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 0.3 फीसदी की गिरावट आई है। आठ बुनियादी उद्योगों- जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं, इनकी चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीने अप्रैल-जुलाई में वृद्धि दर 11.5 फीसदी रही है। एक साल पहले यानी वित्त वर्ष 2021-22 की इसी अवधि में यह 21.4 फीसदी थी। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में आठ बुनियादी उद्योगों का 40.27 फीसदी हिस्सेदारी है। देश के 8 बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है।

- **4.5 फीसदी पर पहुंचा आठ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन**

2047 तक 20 हजार अरब डॉलर तक पहुंचेगी इकोनॉमी

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने देश की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2047 तक 20 हजार अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान जताया है। उनका यह भी कहना है कि यह तभी हो सकता है, जब अगले 25 साल में औसत वार्षिक वृद्धि 07 से लेकर 7.5 फीसदी हो। देबरॉय ने भारत के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता का मसौदा/100 जारी करते हुए बताया कि अगर भारत अगले 25 साल में 07 से लेकर 7.5 फीसदी की औसत आर्थिक वृद्धि दर से आगे बढ़ता है, तो देश की सालाना प्रति व्यक्ति आय 10 हजार अमेरिकी डॉलर से ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में वर्ष 2047 तक भारत भी उच्च मानव विकास श्रेणी के देशों में शामिल हो जाएगा। इस अवसर पर देबरॉय ने कहा कि रूपरेखा में 2047 तक भारत को अत्यधिक समृद्ध देश बनने के लिए आर्थिक पहलुओं के महत्व को दर्शाया गया है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि इस दिशा में क्या करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खपत, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात आर्थिक वृद्धि के संचालक हैं। इसके लिए केंद्र सरकार 2014 से आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम और उज्ज्वला जैसी कई योजनाओं के जरिए असमानता को दूर करने के लिए कई कदम उठा रही है। इस मौके पर देबरॉय के अलावा जी-20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत और परिषद के सदस्य संजीव सान्याल और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की ओर से डॉक्टर क्रिश्चियन केटेल्स भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि भारत इस समय 2,700 अरब अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश को वर्तमान में एक विकासशील राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर रखा है।

चीनी गणेश मूर्तियों का हुआ शून्य आयात

गणेश उत्सव के 10 दिवसीय भव्य समारोह के साथ त्यौहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। जिससे इस साल बड़े कारोबारियों के लिए बड़ी उम्मीद जगी है। इस त्यौहार के साथ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीए-आईटी) ने एक बार फिर चीनी सामानों के बहिष्कार के अभियान को फिर से जारी रखा है। सीएआईटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक, देश में हर साल 20 करोड़ से ज्यादा गणेश प्रतिमाएं खरीदी जाती हैं, जिससे अनुमानित कारोबार 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से देश भर में बड़ी मात्रा में भगवान गणेश की पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियों को स्थापित करने का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, पत्थर, संगमरमर और अन्य वस्तुओं से बनी गणेश मूर्तियों को सस्ते दामों के कारण चीन से आयात किया जाता था, लेकिन पिछले दो सालों में सीएआईटी द्वारा चीनी सामानों के बहिष्कार के अभियान के कारण मूर्तियों का शून्य आयात हुआ है। देश भर के शहरों में अपने घरों में काम करने वाले स्थानीय शिल्पकार, कारीगर और कुम्हार अपने परिवार की महिलाओं को शामिल करते हुए मिट्टी और गाय के गोबर से मूर्तियां बनाते हैं, जिन्हें आसानी से विसर्जित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिन्हें विसर्जित करने के बजाय पेड़ों और पौधों में मिला दिया जाता है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है। इन मूर्तियों की वजह से देश भर में लाखों लोगों को कारोबार मिलता है।

सीट बेल्ट न लगाने और तेज स्पीड की वजह से हुआ था हादसा

- टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत का मामला
- लग्जरी कार ने महज 09 मिनट में तय की थी 20 किमी की दूरी

मुम्बई: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार 04 सितम्बर को एक कार दुर्घटना में मौत की प्राथमिक जांच में पता चला है कि यह हादसा सीट बेल्ट न लगाने और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से हुआ है। इस हादसे की उच्चस्तरीय जांच की जा रही है और हादसे में दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

इस हादसे की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुम्बई से 120 किमी दूर पालघर जिले में चरोटी चेकपोस्ट को पार करने के बाद लग्जरी कार ने महज 09 मिनट में 20 किमी की दूरी तय की। इस आधार पर शुरुआती जांच में पता चला कि कार की गति काफी तेज थी। सूर्या नदी पर बने पुल पर कार के डिवाइडर से टकराने से मिस्त्री और जहांगीर पंडोले की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा दोपहर 2:30 बजे हुआ, जब मिस्त्री अहमदाबाद से मुम्बई लौट रहे थे। मुम्बई की स्त्री रोग विशेषज्ञ अनाहिता पंडोले (55) कार चला रही थीं। इस हादसे में अनाहिता और उनके पति गम्भीर रूप से घायल हो गए। अधिकारी ने कहा कि प्रारम्भिक जांच के अनुसार तेज गति और चालक के गलत निर्णय के कारण कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। दोनों मृतकों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। अधिकारी ने कहा कि चारोटी चेक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज से पता चला है कि कार दोपहर लगभग 2:21 बजे चेक पोस्ट को पार कर गई थी और दुर्घटना 20 किमी आगे (मुम्बई की ओर) हुई थी, यानी मर्सिडीज कार ने सिर्फ 09 मिनट में 20 किमी (चेक पोस्ट से) की दूरी तय की थी। पुलिस ने बताया कि पिछली सीट पर मिस्त्री और जहांगीर पंडोले थे। डेरियस अनाहिता के साथ आगे की सीट पर था। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि एक महिला कार चला रही थी और उसने बाईं ओर एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन नियंत्रण बिगड़ने पर कार सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना के 10 मिनट के भीतर मदद पहुंच गई। दोनों घायलों को कार से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। इस मामले की हाईलेवल जांच जारी है।

भारत में 2025 तक होंगे 45 बड़े डेटा सेंटर

मुम्बई के अग्रणी रहने की है सम्भावना

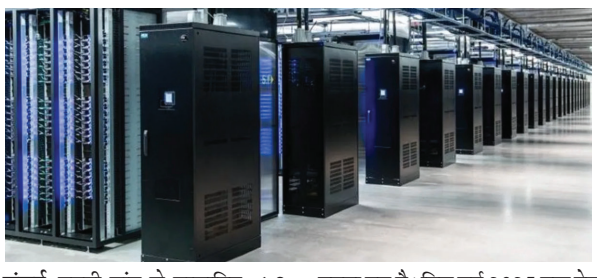

मुंबई: बढ़ती मांग से उत्साहित, 1.3 करोड़ वर्ग फुट और 1,015 मेगावाट की आईटी क्षमता वाले 45 से अधिक डेटा सेंटर 2025 तक भारत में होंगे। मंगलवार 30 अगस्त को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

एनारॉक-बिंग्सवेंगर की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक देश में 2.4 करोड़ वर्ग फुट और कुल आईटी क्षमता के 1,752 मेगावाट के साथ 183 डेटा सेंटर होंगे। आईटी क्षमता (लगभग 1,015 मेगावाट) के संदर्भ में नई आपूर्ति का 69 प्रतिशत से अधिक केवल मुम्बई और चेन्नई में आएगा, उसमें से 51 प्रतिशत तो सिर्फ मुम्बई में। वर्तमान में देश भर में 1.1 करोड़ वर्ग फुट में फैले 138 डेटा केंद्र हैं और 737 मेगावाट की आईटी क्षमता (बिल्डिंग तैयार) है। मौजूदा आईटी क्षमता का कम से कम 57 प्रतिशत सामूहिक रूप से मुम्बई और चेन्नई में है। एनारॉक कैपिटल में औद्योगिक और लॉजिस्टिक और डेटा केंद्र के प्रेसिडेंट देवी शंकर ने कहा कि भारत के डेटा सेंटर उद्योग का वर्तमान आकार लगभग 5.6 अरब डॉलर है और यह बढ़ना तय है। वित्त वर्ष 2025 तक देश के कुल अनुमानित डेटा सेंटर की मांग 2,100 मेगावाट होने की उम्मीद है, जिसमें हाइपरस्केलर्स और उद्यमों के बीच का मिश्रण है। इस बीच रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 2,688 मेगावाट भविष्य की अनियोजित आपूर्ति की अतिरिक्त सम्भावना है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इस आपूर्ति के लिए जमीन डीसी ऑपरेटरों ने दे दी है, लेकिन परियोजनाओं की वास्तविक मांग या पहले के नियोजित चरणों के परिणाम के आधार पर योजना बनाई जाएगी। इस अनियोजित आईटी क्षमता का लगभग 78 प्रतिशत मुम्बई और हैदराबाद में केंद्रित किया जाना है। बिन्सवांगर के मैनेजिंग पार्टनर जेफ बिनवांगर ने कहा कि डेटा सेंटर का होना बहुत सारे निर्णय लेने के लिए एक आधार है। जहां 30 प्रतिशत कंपनियां डेटा प्रबंधन के लिए हाइब्रिड (क्लाउड प्लस डेटा सेंटर) होस्टिंग सेवाओं की ओर देख रही हैं, वहीं 72 प्रतिशत पेशेवरों ने कोविड-19 के बाद डेटा वृद्धि देखी है।

ट्विन टावर के मलबे से बनेंगी टाइल्स

नोएडा: नोएडा के ट्विन टावर के मलबे के निस्तारण को लेकर अब काम शुरू हो गया है। सेक्टर-80 में बने सीआईडी वेस्ट प्लांट में ट्विन टावर के वेस्ट का निस्तारण किया जाएगा। सेक्टर-80 सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में जाएगा। ये प्लांट रैमकी कम्पनी चला रही है।

नोएडा का रोजाना का करीब 250 से 300 मैट्रिक टन मलबे का निस्तारण यहीं किया जाता है। अब इस प्लांट में ट्विन टावर के मलबे का निस्तारण होगा। मलबा निस्तारण के लिए इस प्लांट पर काम दो शिफ्टों में होगा। प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक आर. के. शर्मा ने बताया कि प्लांट की क्षमता 850 टन की है, लेकिन नोएडा में मलबा निकलने के हिसाब से निस्तारित कराया जाता है। अब दो शिफ्टों में काम किया जाएगा। जिसके लिए मैनपावर को बढ़ाया जा सकता है। इस मलबे से टाइल्स, क्लिंकर, ईंट और अन्य उत्पाद बनाए जाएंगे। रोजाना ट्विन टावर की साइट से 250 मीट्रिक टन मलबा डम्पर के जरिए साइट पर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 20 डम्पर लगाए गए हैं। प्रति डंपर क्षमता 10 से 12 मीट्रिक टन की है। एनजीटी के नियमों के पालन करते हुए इस मलबे को ग्रीम शीट और उस पर पानी डालकर ले जाया जाएगा, ताकि धूल नहीं उड़े। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद जो मलबा निकला है, उसका आंकलन करीब 80 हजार मीट्रिक टन है। इसमें 52 हजार मीट्रिक टन मलबा बेसमेंट और आसपास को भरने में काम आएगा। 28 हजार मीट्रिक टन मलबे का निस्तारण होगा।

गौतम अडानी बने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति

एलन मस्क और जेफ बेजोस ही हैं आगे

नई दिल्ली: ब्लूमबर्ग और इसके अरबपतियों के सूचकांक के अनुसार, गौतम अडानी पहले से ही एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अब वह एलवीएमएच के अध्यक्ष बर्नार्ड अरनॉल्ट को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। यह स्थान लेने वाले वो पहले एशियाई व्यक्ति भी बन गए हैं। भारत के शीर्ष समूहों को चलाने वाले अडानी की सम्पत्ति लगभग 137 अरब डॉलर है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस सप्ताह उन्हें टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस से पीछे रखा गया है, जिनकी खुद की संपत्ति क्रमशः 251 अरब डॉलर और 153 अरब डॉलर आंकी गई है। दुनिया भर के अन्य अरबपतियों की तरह, अडानी की सम्पत्ति भी महामारी के दौरान कई गुना बढ़ गई। अडानी ग्रुप बंदरगाह और एयरोस्पेस से लेकर सौर ऊर्जा और कोयले तक की कम्पनियों को नियंत्रित करता है। कोरोना वायरस संकट की शुरुआत के बाद से उनका ग्राफ तेजी से बढ़ा। निवेशकों ने उन क्षेत्रों में अपना व्यवसाय बढ़ाने की उनकी क्षमता पर दांव लगाया, जिन्हें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के लिए प्राथमिकता दी। ब्लूमबर्ग के अनुसार, कोयले के उपयोग में तेजी से भी अडानी को फायदा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, वो इस साल फरवरी में सबसे धनी व्यक्ति बन गए। जुलाई में माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने घोषणा की थी कि वह बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की बंदोबस्ती के लिए 20 अरब डॉलर समर्पित करेंगे और 'दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची से बाहर' निकलने के अपने इरादे को दोहराया। ब्लूमबर्ग के सूचकांक के अनुसार, बिल गेट्स वर्तमान में दुनिया के पांचवें सबसे सम्पन्न व्यक्ति हैं, जिनकी कुल सम्पत्ति 117 अरब डॉलर है।

कानपुर हवाई अड्डे पर बनेगा नया टर्मिनल भवन और एप्रन

नई दिल्ली: यात्री यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने 143.6 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार के लिए कानपुर हवाई अड्डे पर विकास का काम शुरू किया है।

एएआई ने गुरुवार 01 सितम्बर को एक बयान में कहा कि विकास परियोजना में एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण और तीन ए-321 प्रकार के विमानों की पार्किंग के लिए उपयुक्त एप्रन शामिल है। 6,248 वर्गमीटर के क्षेत्र में निर्मित सिविल एन्क्लेव के नए टर्मिनल भवन को व्यस्त समय के दौरान 300 यात्रियों को संसाधित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। सभी आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस टर्मिनल में आने वाले यात्रियों के लिए आठ चेक-इन काउंटर, कन्वेयर बेल्ट होंगे। एक पार्किंग क्षेत्र की भी योजना बनाई गई है, जिसमें 150 कारें रखी जा सकती हैं। टर्मिनल भवन स्थिरता सुविधाओं के साथ एक चार सितारा ऊर्जा कुशल भवन होगा। टर्मिनल का सबसे अगला हिस्सा कानपुर के प्रसिद्ध जेके मंदिर से प्रेरित स्थानीय कला और स्थान की विरासत को दिखाएगा। विकास परियोजना के 31 दिसम्बर, 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। बढ़ी हुई क्षमता के साथ कानपुर हवाई अड्डे के सिविल एन्क्लेव के विकास से इस शहर से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी। कानपुर शहर उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है और चमड़ा, कपड़ा, रक्षा उत्पादन का केंद्र है। कानपुर ऐतिहासिक तीर्थ स्थानों और विभिन्न प्रमुख संस्थानों के लिए भी जाना जाता है और यह शहर बड़ी संख्या में हवाई यात्रियों को आकर्षित करता है। वर्तमान में कानपुर हवाई अड्डा चार शहरों- दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरू और गोरखपुर से सीधे जुड़ा हुआ है।

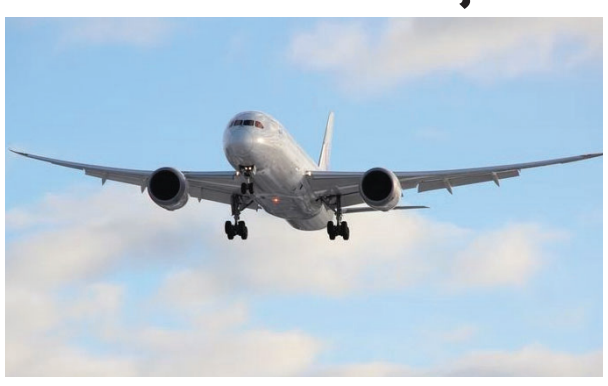

- **यात्री सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार**

अगस्त में 1,43,612 करोड़ रुपए हुआ जीएसटी कलेक्शन

नई दिल्ली: अगस्त में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह में साल-दर-साल आधार पर 28 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई। यह महीने के दौरान 1,43,612 करोड़ रुपए रहा।

वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार 01 सितम्बर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1,12,020 करोड़ रुपए था। कुल संग्रह में से सीजीएसटी 24,710 करोड़ रुपए (वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 42,067 करोड़ रुपए सहित) जबकि उपकर 10,168 करोड़ रुपए (वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 1,018 करोड़ रुपए सहित) था। मंत्रालय के एक बयान में कहा कि जीएसटी राजस्व में वृद्धि जीएसटी परिषद द्वारा अतीत में बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का स्पष्ट प्रभाव है। आर्थिक सुधार के साथ बेहतर रिपोर्टिंग का जीएसटी राजस्व पर लगातार सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

ब्रिटेन को छोड़ भारत बना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली: आजादी के अमृतकाल में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक महामारी को मात देकर भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। खास बात यह है कि ब्रिटेन को पछाड़ कर भारत इस मुकाम तक पहुंचा है। पिछले 10 वर्षों में 11वें पायदान से यहां तक का सफर भारत ने तय किया है। इस लिहाज से भी यह बेहद शानदार और प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व करने वाला क्षण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की जारी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत साल 2021 के आखिरी तीन महीने में ब्रिटेन से आगे निकला। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों में भारत की ये बढ़त वित्त वर्ष 2022-23 में भी जारी है। भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर रही, जबकि इसी अवधि में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर रही। इस लिहाज से अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी रह गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, रोजमर्रा की चीजें महंगी होने से ब्रिटेन ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का तमगा खो दिया। दरअसल, ब्रिटेन पिछले चार दशकों में सबसे तेज महंगाई और मंदी के बढ़ते रिस्क का सामना कर रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अनुमान जताया है कि यह स्थिति 2024 तक रहेगी, वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था के इस वर्ष 07 फीसदी से ज्यादा की दर से बढ़ने का अनुमान है।

ट्रम्प के ट्रथ सोशल ऐप को नहीं मिली मंजूरी

सैन फ्रांसिस्को: ट्रथ सोशल, ट्विटर का मुकाबला करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा शुरू किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अभी तक गूगल प्ले स्टोर से मंजूरी नहीं मिली है।

गूगल ने ट्रथ सोशल को 'उनके वर्तमान ऐप सबमिशन में मानक नीतियों के कई उल्लंघनों' के बारे में सूचित किया है, यह दोहराते हुए कि 'यूजर-जेनरेटिड कंटेंट को मॉडरेट करने के लिए प्रभावी सिस्टम होना किसी भी ऐप के लिए गूगल प्ले पर लाइव होने के लिए हमारी सेवा की शर्तों की एक शर्त है।' ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप (टीएमटीजी) ने एक बयान में कहा कि उसकी 'सार्वजनिक क्षेत्र में अपने व्यावसायिक मामलों पर मुकदमा चलाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड के लिए गूगल से सभी पूछताछ का तुरंत जवाब दिया है।' इसने कहा कि ट्रथ सोशल एंड्रॉइड ऐप 'फ्री स्पीच के लिए एक स्वर्ग' होने के वादे से समझौता किए बिना गूगल की नीतियों का अनुपालन करता है। कम्पनी ने कहा कि जैसा कि हमारे उपयोगकर्ता जानते हैं, ट्रथ सोशल एक जीवंत, परिवार के अनुकूल वातावरण का निर्माण कर रहा है, जो इसकी सेवा की शर्तों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाने के लिए तेजी से काम कर रहा है, जिसे स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने नोट किया है कि उद्योग में सबसे मजबूत हैं। इसने आरोप लगाया कि उसके कुछ प्रतिस्पर्धियों के ऐप्स को 'यौन सामग्री और अन्य नीतियों पर गूगल के निषेध का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने के बावजूद, गूगल प्ले स्टोर में अनुमति दी गई है, जबकि ट्रथ सोशल में यौन स्पष्ट सामग्री के लिए शून्य सहिष्णुता है। ट्रथ सोशल को 21 फरवरी को एप्पल ऐप स्टोर में लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रथ सोशल नकदी के लिए परेशान है और तकनीकी और कानूनी परेशानियों का सामना कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, सबसे तात्कालिक समस्या प्लेटफॉर्म का रुका हुआ एसपीएसी है, जिसे शुरू में नई कम्पनी में सार्वजनिक रूप से शेयरों का व्यापार करने की योजना बनाई गई थी। एक एसईसी फाइलिंग से पता चलता है कि कम्पनी को इस साल की पहली छमाही में 60 लाख डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है और कोई राजस्व उत्पन्न नहीं हुआ है।

2030 तक सड़कों पर दिखेंगी 4-5 करोड़ ईवी गाड़ियां

- **तेजी से बढ़ रही भारत की ई-मोबिलिटी यात्रा**
- **मजबूत चार्जिंग नेटवर्क के विकास से बढ़ी सम्भावना**

नई दिल्ली: भारत की ई-मोबिलिटी यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है और 2030 तक अनुमानित 45-50 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सड़क पर दिखने की उम्मीद की जा रही है। मंगलवार 30 अगस्त को एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

केपीएमजी इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जैसे-जैसे ईवी पारिस्थितिकी तंत्र तीव्र गति से परिपक्व हो रहा है, ईवी अपनाने का एक महत्वपूर्ण सूत्रधार धीमी और तेज चार्जर की उपलब्धता है, जो कुशल और लागत प्रभावी चार्जिंग तक आसान पहुंच सुनिश्चित करता है। भारत में केपीएमजी के एम एंड ए कंसल्टिंग के पार्टनर रोहन राव ने कहा कि दुनिया भर में त्वरित ईवी अपनाने के साथ एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क का विकास हुआ है और हमारा मानना है कि इसी तरह की प्रवृत्ति भारत में देखे जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, चार्जिंग तकनीक अलग-अलग वाहन खंडों के अनुसार अलग-अलग होगी और सार्वजनिक और निजी चार्जिंग समाधान अलग-अलग ग्राहक खंडों और उपयोग के मामलों की सेवा के लिए तैनात किए जाएंगे। 2डब्ल्यू और 3डब्ल्यू एसी धीमी चार्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त हैं। बैटरी की अदला-बदली उन मामलों के लिए अधिक प्रचलित मॉडल होने की सम्भावना है, जिनमें त्वरित चार्जिंग टर्नअराउंड की आवश्यकता होती है। भारतीय बाजार में एसी निजी और सार्वजनिक चार्जर्स और डीसी चार्जर्स का एक घना नेटवर्क होने की सम्भावना है, जो बसों तक सीमित हैं और 4डब्ल्यू और एलसीवी के लिए कुछ उपयोग के मामले हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, होम/वर्कप्लेस चार्जिंग से उम्मीदें डेस्टिनेशन चार्जिंग या ऑन गो चार्जिंग से अलग हो सकती हैं, जो फ्लीट चार्जिंग से अलग होगी। निष्कर्षों से पता चलता है कि रियल एस्टेट के लिए रणनीतिक साझेदारी और सीपीओ/सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर-संचालन ग्राहक प्रस्ताव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। राव ने कहा कि 2030 तक भारतीय सड़कों पर अनुमानित 5 करोड़ ईवी के साथ, शुद्ध प्ले चार्जिंग व्यवसाय के लिए संभावित अवसर बहुत अधिक हैं।

लोगों का मददगार बनेगा लाइव सुरक्षा एजेंट

उबर ने अपने सुरक्षा टूलकिट को बदल दिया है और अब सवारी जरूरत पड़ने पर अमेरिका में घरेलू सुरक्षा कम्पनी एडीटी के लाइव सुरक्षा एजेंट से फोन या टेक्स्ट के जरिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जब कॉल या टेक्स्ट एक्सचेंज का अनुरोध किया जाता है, तो एजेंट चल रही यात्रा की निगरानी कर सकता है, यात्रा की अवधि के दौरान सम्पर्क में रह सकता है और यहां तक कि उपयोगकर्ता की ओर से 911 फीचर तक पहुंच सकता है। कम्पनी ने ग्राहकों को 911 टेक्स्ट करने के लिए सक्षम करने वाले फीचर की उपलब्धता का भी विस्तार किया है। उबर में लीड सेफ्टी प्रोडक्ट मैनेजर रेबेका पायने ने कहा कि सुरक्षा कवच पर टैप करने के बाद, सवारों को अपने क्षेत्र में उपलब्ध सभी सुरक्षा सहायता विकल्पों के साथ बड़ी टाइलें दिखाई देंगी। सुरक्षा टूलकिट में सवारों और ड्राइवरों के पास आपातकालीन बटन तक पहुंच होती है और यात्रा के दौरान सीधे हमें सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। उबर ने अपने यूजर्स को सुरक्षा विशेषज्ञ का समर्थन दिलाने के लिए एडीटी के साथ साझेदारी की है। पायने ने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह नई सुविधा यूजर्स को यह जानकर अतिरिक्त मानसिक शांति देगी कि किसी भी सुरक्षा स्थिति के लिए ऐप में सहायता उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अब हम कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क शहर सहित पूरे अमेरिका में टेक्स्ट को 911 से बढ़ाकर लगभग 60 प्रतिशत कर रहे हैं, जहां टेक्स्ट संदेश प्राप्त करने के लिए 911 केंद्रों के लिए तकनीक मौजूद है। जब कोई व्यक्ति 911 फीचर के लिए टेक्स्ट का उपयोग करता है, तो उबर ऐप वाहन के विवरण, स्थान और गंतव्य जानकारी के साथ प्रारम्भिक संदेश को प्री-पॉप्युलेट करेगा, ताकि आप उस जानकारी को आपातकालीन डिस्पैचर्स को जल्दी से सम्वाद कर सकें।

खेलों में वैश्विक स्तर पर छाने को तैयार यूपी-हरियाणा

उत्तर प्रदेश में तैयार किया जा रहा खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे वातावरण और सरकारी सहयोग से हरियाणा बन रहा स्पोर्ट हब

आईपीके, लखनऊ: वर्तमान समय में देश में खेलों को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। वैसे तो हमेशा से ही भारत में कई ऐसे खेल हैं, जिन्हें काफी पसंद किया जाता रहा है, लेकिन उन्हें विश्व स्तर पर उतनी पहचान नहीं मिल पाती थी। फिर एक समय ऐसा है, जब क्रिकेट की लोकप्रियता ने बाकी सभी खेलों को अपने अंदर ढक लिया।

अब पिछले कुछ सालों से देश में न सिर्फ क्रिकेट, बल्कि हर तरह के खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ताकि विश्व स्तर पर भारत का परचम लहरा सके। इस क्षेत्र में अब राज्य सरकारें भी लगातार अपने सूबे से खेलों को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर हो रही हैं। इस क्रम में हरियाणा हमेशा से खेल के क्षेत्र में काफी आगे रहा है और इसकी झलक ओलम्पिक से लेकर कॉमनवेल्थ तक देखने को मिल जाती है, जहां हरियाणा से आया खिलाड़ी देश का नाम रोशन करता है। हरियाणा के अलावा अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसकी झलक भी विश्व स्तर पर दिखनी शुरू हो गई है।

यूपी में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा बदलाव

उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी देश और दुनिया सभी जगह अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या में और इजाफा होने जा रहा है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों से खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल बदलाव किए जा रहे हैं। खेल निदेशालय की तरफ से राज्य के कई जिलों में नए खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, तो प्रदेश सरकार के आग्रह पर कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। इसका फायदा प्रदेश के खिलाड़ियों और खेलों को मिलेगा और वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के निदेशक आरपी सिंह के मुताबिक, राज्य में बड़े स्तर पर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। इसके तहत, सिर्फ लखनऊ में ही स्विमिंग पूल और वेलोड्रम का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी अलग-अलग खेलों से जुड़े कोर्ट व स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। मिजार्पुर, अलीगढ़, बस्ती, देवीपाटन और मुरादाबाद जैसे शहरों में 50-50 खिलाड़ियों की क्षमता वाले स्पोर्ट हॉस्टल का निर्माण हो रहा है तो शामली और हापुड़ जैसे शहरों में स्टेडियम बनाया जा रहा है। वाराणसी में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। इसका फायदा सीधे तौर पर खिलाड़ियों को मिलेगा। साथ ही, अंशकालिक कोच भी बढ़ाए जाएंगे, जिससे रोजगार सृजन भी होगा।

बनाए जा रहे कई स्टेडियम और स्पोर्ट क्लब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत कानपुर और वाराणसी में दो अत्याधुनिक मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य में भूमि उपलब्ध कराई है। सरकार के फैसले के फलस्वरूप इन मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, स्क्वॉश, स्विमिंग पूल, हॉकी, बॉक्सिंग समेत 22 से ज्यादा खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा। कानपुर में पालिका स्टेडियम में बनाए

जा रहे इस मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जिम, जकूजी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्पोर्ट हॉल भी होगा, जबकि स्पा और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। 315 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस स्टेडियम का पहला फेज तकरीबन पूरा हो गया है और अक्टूबर में मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। दूसरी तरफ, वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में भी 87 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी के तहत मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यह कॉम्प्लेक्स तमाम खूबियों के साथ-साथ दिव्यांगजनों के अनुकूल होगा। यहां पैरा स्पोर्ट भी कराए जाने की योजना है। खेल विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के बाद विभिन्न केंद्रों में सम्बंधित खेलों के प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इससे एनआईएस कर चुके तमाम युवाओं को नई प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलेगा। वहीं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी एनआईएस कोच व अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेलों को प्रमोट करने

के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को न सिर्फ नकद पुरस्कार दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें राजपत्रित अधिकारी के पद पर सीधे नियुक्ति देने का फैसला किया गया है। हाल ही में सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले 8 खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार के अनुसार, स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को एक करोड़, रजत पदक विजेताओं को 75 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। सहभागिता राशि के तौर पर पदक न जीत पाने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं।

कॉमनवेल्थ और ओलम्पिक में रहता है हरियाणा का दबदबा

बर्मिंघम में हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में, भारत ने 215 खिलाड़ियों का दल भेजा था। इनमें से 42 खिलाड़ी हरियाणा के थे और उन्होंने देश को मिले 61 में से 20 पदक दिलाए। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक देश को दिलाने में मदद की। आंकड़े भारतीय खेल परिदृश्य में हरियाणा के वर्चस्व की कहानी बताते हैं। हर प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। राष्ट्रीय खेल हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। कुल मिलाकर, अपने पूरे ओलम्पिक इतिहास में भारत के व्यक्तिगत पदकों में से 30 प्रतिशत से अधिक राज्य के खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। हॉकी के अलावा, भारत ने अब तक ओलम्पिक में 23 व्यक्तिगत पदक जीते हैं, जिनमें से हरियाणा ने सात पदक हासिल किए हैं। इस साल टोक्यो ओलम्पिक में भारत का सबसे सफल अभियान था, क्योंकि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक स्वर्ण सहित भारत ने सात पदक जीते थे। टोक्यो ओलम्पिक के लिए भारत के दल में 126 एथलीट शामिल थे, जिनमें से 31 हरियाणा से थे। हरियाणा को इतने मेडल क्यों मिलते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ा हरियाणा की संस्कृति पर विचार करना होगा।

हरियाणा में हमेशा से है खेल संस्कृति

ओलम्पिक पदक विजेता सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त जैसे पहलवानों से जुड़े रहे राजस्थान के चिड़ावा के पहलवान और द्रोणाचार्य अवार्डी कुश्ती कोच महासिंह राव के पास इसके लिए कुछ अलग जवाब हैं। महासिंह राव ने कहा कि खेल में राज्य का वर्चस्व किसी भी तरह से लोगों की सामूहिक प्राथमिकता से जुड़ा हुआ है जो उन्हें तेज धूप के तहत खेतों में काम करने, सेना में नौकरी पाने और खेल गतिविधियों में शामिल होने में मदद करता है, जो कि कुश्ती की अधिक सम्भावना है। खेल हमेशा से ग्रामीण हरियाणा का एक अभिन्न अंग रहा है, जहां पहलवान पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसने खेल संस्कृति के लिए माहौल बनाया है। लगभग हर जिले में मुक्केबाजी और कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र हैं और फिर, स्थानीय स्तर पर संगठित दंगल जो भविष्य के पहलवानों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। महा सिंह राव ने कहा कि टोक्यो के बाद, नीरज चोपड़ा रातोंरात सनसनी बन गए और मुझे यकीन है कि उन्होंने हरियाणा के कई युवा बच्चों को भाला लेने के लिए प्रेरित किया है।

मेरा लक्ष्य पेरिस ओलम्पिक में मेडल जीतना : लिंथोई चनंबम

नई दिल्ली: हाल ही में जूडो में विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनीं 16 वर्षीय लिंथोई चनंबम ने कहा कि वह ओलम्पिक में पदक जीतना चाहती हैं और उनकी निगाहें पेरिस 2024 पर टिकी हैं।

अपने लक्ष्यों के बारे में बोलते हुए 16 वर्षीय विश्व कैडेट चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता ने कहा कि उनकी निगाहें पेरिस 2024 पर मजबूती से टिकी हैं। उन्होंने कहा कि मैं ओलम्पिक में जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक विजेता बनना चाहती हूं और मेरी निगाहें पेरिस 2024 पर टिकी हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के महानिदेशक संदीप प्रधान ने सोमवार 29 अगस्त को यहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लिंथोई को सम्मानित किया। मणिपुर के जुडोका ने 57 किग्रा भार वर्ग में ब्राजील की रीस बियांका को 1-0 से हराकर साराजेवो में विश्व कैडेट चैम्पियनशिप 2022 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। लिंथोई चनंबम के साथ उनके जॉर्जियाई कोच मामुका किज़िलाशवी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए, लिंथोई ने कहा कि साई ने हमेशा मेरी मदद की है और मेरे सभी प्रयासों में मेरा समर्थन किया है। मैं संदीप प्रधान और साई के अटूट समर्थन के लिए बेहद आभारी हूं। यह स्वर्ण पदक जीतने पर मुझे अपार खुशी हो रही है।

कॉमनवेल्थ में कांस्य जीतना बड़ी उपलब्धि: दीप ग्रेस एक्का

बर्मिंघम: भारत की शीर्ष महिला हॉकी डिफेंडर दीप ग्रेस एक्का ने खुलासा किया है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल के फाइनल में खेलना बहुत बड़ी बात होती, लेकिन कांस्य पदक के साथ पोडियम पर खड़ा होना भी एक उपलब्धि है, जो टीम का मनोबल बढ़ाने वाला है। दीप ग्रेस एक्का के साथ महिला टीम इस साल के अंत में वालेंसिया (स्पेन) में एफआईएच महिला हॉकी राष्ट्र कप की तैयारी शुरू करने के लिए बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण के परिसर में लौटेंगी।

डिफेंडर ने कहा कि हम निश्चित रूप से बर्मिंघम में फाइनल खेलना पसंद करते, लेकिन कांस्य पदक जीतना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। पोडियम पर खड़ा होना एक ऐसा क्षण है, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। यह पूरी टीम के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला है। टोक्यो में महत्वपूर्ण ओलम्पिक खेलों 2020 से शुरू होकर बर्मिंघम राष्ट्रमंडल गेम्स में कांस्य पदक के साथ समाप्त करने वाली महिला हॉकी टीम के लिए पिछले 12 महीने काफी अच्छे रहे हैं। वे अब अपना ध्यान वालेंसिया, स्पेन में 10 दिसम्बर से शुरू होने वाले महिला हॉकी राष्ट्र कप पर लगाएंगे। ग्रेस एक्का को उम्मीद है कि टीम आगे भी अपनी इस तरह की जीत को जारी रख सकती है। उन्होंने कहा कि हमने बर्मिंघम में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब वह गुजर चुका है। हमें एक अच्छा ब्रेक मिला है और अब हमें आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा। मुझे यकीन है कि मुख्य कोच जेनेक शोपमैन हमारे पिछले प्रदर्शन का आंकलन करेंगे और शिविर में आने वाले दिनों की योजना बनाएंगे। सविता की कप्तानी वाली टीम अगले दौरे से पहले एक लम्बे कैम्प के लिए तैयार है और अनुभवी डिफेंडर को अपने अगले टूर्नामेंट से पहले कड़ी मेहनत करने की उम्मीद है।

कल्याण चौबे बने एआईएफएफ के नए अध्यक्ष

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय फुटबॉलर कल्याण चौबे इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हुए नए एआईएफएफ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब उनके हाथों में भारतीय फुटबॉल का भविष्य आ गया है। कल्याण चौबे दिग्गज फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया को हराकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पहले खिलाड़ी-अध्यक्ष बने। चुनाव में कल्याण ने भूटिया को 33-1 से हराया है, यानी कल्याण को 33 वोट मिले। जबकि भूटिया को सिर्फ एक वोट मिल सका। 45 साल के कल्याण चौबे ने फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद राजनीति जॉइन की। वह पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्हें पहले से ही जीत का दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि उन्हें गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों से समर्थन मिल रहा था। कल्याण चौबे पूर्व भारतीय गोलकीपर रहे हैं। उन्होंने 2019 में कृष्णानगर से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इसमें उन्हें हार मिली थी। कल्याण चौबे 1997-98 और 2001-02 में भारतीय गोलकीपर ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। वह कोलकाता जायंट्स मोहन बागान और ईस्ट बंगाल दोनों के लिए खेल चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने गोवा की सलगांवकर टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है।

फिनिशिंग और तालमेल में सुधार पर है टीम का ध्यान: हरमनप्रीत

बेंगलुरु: भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह ने कहा है कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहले टीम का ध्यान फिनिशिंग और तालमेल में सुधार करना है। भारत को बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 0-7 से करारी हार मिली थी। टीम प्रो लीग 2022/23 सीजन से पहले बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) केंद्र में प्रशिक्षण पर लौट आई, जो 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। टीम एफएचआई मेन्स हॉकी विश्व कप 2023 की तैयारी के लिए प्रो लीग खेलों का उपयोग करेगी। हरमनप्रीत ने ओडिशा द्वारा आयोजित किए जा रहे मेगा इवेंट की तैयारी में खेलों के महत्व पर जोर दिया।

हरमनप्रीत ने बुधवार 31 अगस्त को कहा कि हमारे पास अच्छे अभ्यास सत्र होंगे और हमारा प्राथमिक ध्यान सुधार करने और खिलाड़ियों के बीच तालमेल बढ़ाने पर होगा। हम इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि हम खिलाड़ियों के बीच गेंद को पास करने के समय में सुधार कैसे कर सकते हैं। कैम्प में टीम के फोकस पर हरमनप्रीत ने कहा कि हमारे पास प्रशिक्षण का पहला दिन है। जब हमारी बैठकें होंगी, तो हम अपने खेल के उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिन पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हम उन टूर्नामेंटों के वीडियो देखेंगे जो हम हाल ही में खेले हैं। हम पीछे मुड़कर देखेंगे कि हमने क्या अच्छा किया और किन क्षेत्रों में हम सुधार कर सकते हैं। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2023 के लिए पूल ड्रॉ 08 सितम्बर को होने वाला है। लेकिन हरमनप्रीत ने कहा कि टीम उसी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए खुद को तैयार करेगी।

आईओए कोषाध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज

लखनऊ: राजस्थान के भिवाड़ी थाने में यूपी ओलम्पिक संघ के महासचिव आनंदेश्वर पांडेय के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। एक हैंडबॉल खिलाड़ी ने भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) के कोषाध्यक्ष पांडेय के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की पूर्व राष्ट्रीय स्तर की हैंडबॉल खिलाड़ी सीमा शर्मा ने पांडेय के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जो 2013 से 2020 तक हैंडबॉल फेडरेशन आफ इंडिया (एचएफआई) के महासचिव भी थे। राजस्थान के भिवाड़ी में महिला पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 511 (अपराध करने का प्रयास) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। सीमा शर्मा ने अपनी शिकायत में पांडेय पर इस साल मार्च में लखनऊ में यूपीओए के कार्यालय में बलात्कार की कोशिश करने का आरोप लगाया है। जीरो एफआईआर अब लखनऊ के हजरतगंज थाने में ट्रांसफर कर दी गई है। महिला पुलिस स्टेशन भिवाड़ी के एसएचओ ने कहा कि यह एक शून्य

प्राथमिकी थी और इसमें यौन उत्पीड़न की धाराएं हैं। मामले को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है। यहां मोहनलालगंज में एसएसबी की चौथी बटालियन की सिपाही शर्मा ने भी 31 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा था, जिसमें घटना का विवरण दिया गया था और मामले में हस्तक्षेप करने का आह्वान किया था। शिकायत के अनुसार, 28 वर्षीय शर्मा ने कहा कि वह राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल चैम्पियनशिप के लिए चयन ट्रायल के दौरान पांडेय से मिलीं। 12 मार्च को परीक्षणों का आयोजन के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया था। उन्होंने कहा कि वह शिविर में आई थीं और 26 मार्च को अंतिम चयन से पहले उन्हें उनके कोच ने पांडेय के कार्यालय जाने के लिए कहा, जहां उन्होंने कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और छेड़छाड़ की। शर्मा ने अपनी शिकायत में लिखा है कि उन्होंने उनके इस कदम का विरोध किया, जिस दौरान उनकी जर्सी फट गई। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने मुझे गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और कहा कि वह बहुत शक्तिशाली हैं और मेरे खेल करियर को समाप्त कर देंगे। उप-जूनियर, जूनियर और सीनियर स्तर की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली शर्मा ने कहा कि मैंने इस घटना के बारे में अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया। शर्मा ने आरोप लगाया कि पांडेय बार-बार यौन उत्पीड़न की कोशिश करते रहे थे और उन्होंने कई हैंडबॉल खिलाड़ियों के करियर को समाप्त कर दिया है, लेकिन किसी ने भी उनके खिलाफ रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह शक्तिशाली और कई अधिकारियों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। एक पूर्व राष्ट्रीय स्तर के धावक, पांडेय ने एक हैंडबॉल खिलाड़ी के रूप में अपना करियर शुरू किया और पहली बार 1977-78 में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। वह 27 सितम्बर से अहमदाबाद में होने वाले आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए समन्वय समिति के अध्यक्ष भी हैं।

टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने घोषित की टीम

पैट कमिंस की वापसी, टिम डेविड ने मिचेल स्वेप्सन की ली जगह, भारत दौरे पर नहीं खेलेंगे डेविड वार्नर

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मेजबानी में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है, जिसमें सिंगापुर में जन्मे और पर्थ में पले-बढ़े टिम डेविड को लेग स्पिनर मिचेल स्वेप्सन की जगह टीम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया टी20 विश्व कप का पिछला चैम्पियन है। पैट कमिंस न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज चूकने के बाद टीम में लौटे हैं, जबकि एडम जम्पा भी अपने बेटे यूजीन के जन्म के बाद टीम में शामिल किए गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने मध्यक्रम के बल्लेबाज टिम डेविड को टीम में शामिल किया है। विश्व कप से पहले सितम्बर में भारत में तीन टी20 मैचों के दौरे पर भी डेविड टीम में रहेंगे और यह उन्हें पहली बार ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का मौका मिलेगा। सिंगापुर में जन्मे डेविड बीबीएल समेत विश्व की कई टी20 लीग में धाकड़ बल्लेबाजी के लिए नाम कमा चुके हैं और वह ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय या राजकीय अनुबंध के ढांचे से बाहर टीम में चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। वर्तमान में उनका ऑस्ट्रेलिया में इकलौता करार होबार्ट हरिकेंस टीम के साथ है और वह इससे पहले सिंगापुर के लिए 14 टी20 अंतर्राष्ट्रीय खेल चुके हैं। राष्ट्रीय चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा कि वह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और नैसर्गिक रूप से बड़े शॉट लगाते हैं। उनके आने से हमारी टी20 टीम में बल्लेबाजी की गहराई और बढ़ेगी। इससे पहले भी पिछले सीजन श्रीलंका के विरुद्ध टीम में उन्हें शामिल करने की बात हुई थी, लेकिन फिर यह फैसला लिया गया था कि उन्हें पीएसएल में मुल्तान सुल्तांस में खेलने दिया जाए ताकि उन्हें निरंतर मैच खेलने का मौका मिले। उस टूर्नामेंट में उन्होंने 194.40 के स्ट्राइक रेट और 39.71 के औसत से 278 रन बनाए थे और उसी दौरान उन्हें आईपएल में मुम्बई इंडियंस ने 8.25 करोड़ रुपये देकर अपने साथ जोड़ा। डेविड पिछले साल यूएई में विश्व कप जीतने वाली टीम से इकलौते बदलाव होंगे। वह उस टीम से लेग स्पिनर मिचेल स्वेप्सन की जगह लेंगे। चयनकर्ताओं के अनुसार घरेलू परिस्थितियों में अतिरिक्त स्पिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बड़ा सवाल यही होगा कि एकादश में डेविड को कैसे जगह दी जाए। एंडयू मैकडोनाल्ड के मुख्य कोच बनने के बाद स्टीवन स्मिथ, जिनकी बल्लेबाजी की शैली शायद टी20 क्रिकेट में उन्हें सबसे ज्यादा दबाव का पात्र बनाती है, अधिक स्वतंत्रता के साथ बल्लेबाजी करने लगे हैं। कार्यभार प्रबंधन के लिए डेविड वार्नर को भारत में होने वाले टी20 मैचों में आराम दिया गया है और टीम में उनकी जगह कैमरन ग्रीन खेलेंगे। 25 सितम्बर को खत्म होने वाली इस सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया विश्व कप की तैयारी के तहत अपने घर में अक्टूबर की शुरूआत में वेस्टइंडीज के साथ दो मैच और इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैच खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया विश्व कप में अपने अभियान की शुरूआत 22 अक्टूबर को सिडनी में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से करेगा।

ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप टीम: आरोन फिंच (कप्तान), एश्टन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिस, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, एडम जम्पा।

भारत को 15 सितम्बर तक करना होगा टीम का ऐलान

एशिया कप में विजय रथ पर सवार टीम इंडिया इस टूर्नामेंट को इसी साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों के तौर पर देख रही है। क्योंकि इस समय भारत की नजर में टी20 विश्व कप का खिताब ही घूम रहा है। ऐसे में अब टूर्नामेंट में काफी कम समय बचा है, जिसके चलते मेजबान ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपनी विश्व कप टीम का ऐलान भी कर दिया गया। भारत के पास भी टी20 विश्व कप के लिए अपनी टीम को घोषित करने के लिए कुछ दिन का समय ही शेष रहा गया है। ऐसे में ये साफ है कि एशिया कप के अंत में या इसके तुरंत बाद चयनकर्ताओं द्वारा टीम का ऐलान किया जा सकता है। इसलिए एशिया कप में खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी अहम हो गया है।

टी-20 वर्ल्डकप इस बार ऑस्ट्रेलिया में होना है, जिसके लिए टीम का ऐलान करने के लिए 15 सितम्बर की डेडलाइन है। ऐसे में हर किसी की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि भारतीय टीम में किसको जगह मिलती है। आईसीसी ने पहले ही यह बता दिया था कि सभी क्रिकेट बोर्ड को 15 सितम्बर तक अपने स्क्वॉड की जानकारी देनी होगी, जो टी-20 वर्ल्डकप में हिस्सा लेंगे। वर्ल्डकप के होस्ट ऑस्ट्रेलिया ने तो टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर भी दिया है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम वर्ल्डकप की तैयारियों में जुटी है, ऐसे में यह देखना होगा कि आखिर वर्ल्डकप में जगह कौन बना पाता है। अगर भारतीय टीम के स्क्वॉड को देखें तो अधिकतर प्लेयर्स का सिलेक्ट होना तय है, सिर्फ 2-3 प्लेयर्स के मामले में ही मंथन हो सकता है या कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है।

जर्मनी की एंड्रिया पेटकोविच ने टेनिस को कहा अलविदा

न्यूयॉर्क: जर्मनी की एंड्रिया पेटकोविच ने मंगलवार 30 अगस्त को यूएस ओपन में स्विस ओलम्पिक चैम्पियन बेलिंडा बेनसिक के खिलाफ मुकाबला 6-2, 4-6, 6-4 से हारकर टेनिस को अलविदा कह दिया। पूर्व शीर्ष 10 खिलाड़ी और फ्रेंच ओपन सेमीफाइनलिस्ट पेटकोविच ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि न्यूयॉर्क ग्रैंड स्लैम उनका आखिरी मेजर टूर्नामेंट होगा। हालांकि, वह दोस्तों और परिवार को अपना खेल देखने का अंतिम मौका देने के लिए यूरोप में एक छोटे से कार्यक्रम में एक बार फिर टेनिस खेलती दिखाई दे सकती हैं।

पहले दौर की हार के बाद पेटकोविच ने कहा कि मैं पिछले पांच दिनों में वास्तव में खराब दौर से गुजरी हूं। पेटकोविच ने कहा कि वह शुरू में कुछ सप्ताह पहले अपनी संन्यास की घोषणा करना चाहती थीं, लेकिन यह विचार उन्होंने तब छोड़ दिया, जब अमेरिकी आइकन सेरेना विलियम्स ने कहा कि यूएस ओपन उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि सेरेना यूएस ओपन के बाद संन्यास ले लेंगी, तो मैंने खेल से संन्यास की घोषणा कुछ दिनों के लिए टाल दी थी। पेटकोविच ने कहा कि वह 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता विलियम्स का बहुत सम्मान करती हैं, जो सोमवार को दूसरे दौर में आगे बढ़ीं।

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण ओलम्पिक पर विचार : बघेल

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में ग्रामीण और पारम्परिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलम्पिक के आयोजन के सम्बंध में विचार कर रही है। राज्य सरकार की मंशा है कि इस आयोजन में बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्ग सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हों, जिससे गांव-गांव में खेलों के प्रति एक अच्छा वातावरण बने।

राजधानी में 'खेलगढ़-छत्तीसगढ़, खेलबो, जीतबो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में खेल अकादमियों की स्थापना की जा रही है। खेलों को बढ़ावा देने उद्योगों को खेलों से जोड़ा जा रहा है। खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया कराने छत्तीसगढ़ सरकार ठोस कदम उठा रही है। इससे प्रदेश में खेल के लिए माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि मोबाइल के आने से बच्चे पारम्परिक खेलों और खेल मैदानों से दूर होते जा रहे हैं। खेलों का बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि बड़े और बुजुर्ग बच्चों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करें और उन्हें स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं दिलाने का प्रयास करें, तो बच्चों में खेलों के प्रति जुनून की भावना उत्पन्न होगी, जो उन्हें काफी आगे तक ले जाने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग अभावों में भी मनोरंजन के साधन जुटा लेते हैं। छत की टूटी खपरैल से पिट्ठुल बनाकर और घर के रद्दी कपड़े से गेंद बनाकर खेल और मनोरंजन का साधन जुटा लेते हैं।

राज्य सरकार खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जिससे खेलों के क्षेत्र में हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों में खेल प्रतिभा की कमी नहीं है जरूरत उन्हें एक अच्छा मंच दिलाने, उनके लिए बेहतर प्रशिक्षण और कोच की व्यवस्था करने की है। साथ ही खिलाड़ियों की डाइट और खेल आयोजनों की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है। कोरोना के कारण खेल प्राधिकरण की गतिविधियां गति नहीं पकड़ सकीं, जिन्हें अब बढ़ाया जाएगा। खेलों से विभिन्न औद्योगिक घरानों को जोड़ने की पहल भी की गई है। उनसे बस्तर के आदिवासी अंचल से लेकर बिलासपुर और राजधानी रायपुर में स्थापित विभिन्न खेल अकादमियों के स्थापना, उनके संचालन, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण-कोच की सुविधा, बेहतर डाइट उपलब्ध कराने में सहयोग लिया जाएगा। मु

टेक-टॉक

आधार कार्ड से इस तरह पता करें अपना बैंक बैलेंस

वर्तमान समय में आधार कार्ड हमारे देश के नागरिक के लिए सबसे अहम व प्रमुख डॉक्यूमेंट है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भारतीय नागरिकों को आधार नामक एक 12-अंकीय संख्या जारी करता है, जो उनके पहचान और निवास के प्रमाण की तरह काम करता है। आधार से हमारा हर अन्य डॉक्यूमेंट लिंक है। नागरिकों के पते, बायोमेट्रिक डेटा और फोन नम्बर से लिंक होने के अलावा ये उनके बैंक खातों से भी जुड़ा हुआ है। यह कनेक्शन भारत में नागरिकों को अपने आधार नम्बर से जुड़े अपने बैंक खातों में बची हुए बैलेंस की ऑनलाइन जांच करने देता है। आधार नम्बर का उपयोग करने से नागरिकों को अपने बैंकों के वेब पोर्टल में लॉग इन किए बिना अपने बैंक अकाउंट बैलेंस की जांच करने की जरूरत भी नहीं रह जाती है। इसलिए, अगर आप अपने आधार से जुड़े अकाउंट बैलेंस की जांच करना चाहते हैं, तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है।

आधार से ऐसे पता करें अपना बैंक बैलेंस

इंटरनेट कनेक्शन न होने की स्थिति में ये तरीका विशेष रूप से उपयोगी होगा। इसके अलावा, आप इस तकनीक का उपयोग स्मार्टफोन के साथ-साथ फीचर फोन पर भी अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए कर सकते हैं।

- सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से *99*99*1# डायल करें।
- इसके बाद अपना 12 अंकों का आधार नम्बर दर्ज करें।
- फिर अपना आधार नम्बर वैरिफाई करने के लिए इसे फिर से दर्ज करें।
- इसके बाद UIDAI आपको एक फ्लैश SMS भेजेगा। वह फ्लैश मैसेज स्क्रीन पर बैंक बैलेंस दिखाएगा।

बता दें कि आधार यूजर्स न केवल 12 अंकों की संख्या का उपयोग करके अपने बैंक बैलेंस जांच कर सकते हैं। बल्कि पैसे भेजने, सरकार की सब्सिडी के लिए आवेदन करने और यहां तक कि आधार का उपयोग करके पैन कार्ड के लिए आवेदन करने जैसे कई कार्य भी कर सकते हैं। पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार का उपयोग करने से कई डॉक्यूमेंट जमा करने की परेशानी कम हो जाती है, क्योंकि इसका उपयोग पहचान और पते के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।

2023 से उड़ान भरेगा स्वदेशी एलसीए मार्क-2 लड़ाकू विमान

- 17.5 टन एकल-इंजन विमान विकसित करने का रास्ता हुआ साफ
- वायु सेना में मिराज 2000, जगुआर और मिग-29 लड़ाकू विमानों की लेगा जगह

नई दिल्ली: दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में शुमार लाइट काम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क-2 (एलसीए) के अगले साल 2023 के अंत में पहली उड़ान भरने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने एलसीए एमके-2 लड़ाकू विमान विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस मंजूरी से उन्नत 17.5 टन एकल-इंजन विमान विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। नए विमानों का विकास 2027 तक पूरा होगा। इसके बाद तेजस डिफेंसिव एयरक्राफ्ट का तमगा खोकर अटैक करने वाले लड़ाकू विमानों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा सम्बंधी कैबिनेट समिति ने स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करने के लिए की जा रही पहलों को बढ़ावा देने के लिए एलसीए मार्क-2 लड़ाकू विमान के प्रोटोटाइप विकास को मंजूरी दे दी, जो वायु सेना में मिराज 2000, जगुआर और मिग-29 लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। एलसीए मार्क-2 का प्रोटोटाइप वर्जन अगले साल 2023 के अंत में पहली उड़ान भरेगा। व्यापक उड़ान परीक्षणों के बाद यह परियोजना वर्ष 2027 तक पूरी होगी। सरकार ने यह भी मंजूरी दे दी है कि विमान में इस्तेमाल होने वाले इंजन प्रारम्भिक विकास चरण के बाद 'मेड इन इंडिया' होने चाहिए।

2027 तक वायु सेना को मिल जाएंगे सभी तेजस एमके-1ए विमान

वैमानिकी विकास एजेंसी (एडीए) के प्रमुख गिरीश देवधर के मुताबिक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) विमान को जीई-414 इंजन के साथ विकसित करेगा, जो जीई-404 का उन्नत संस्करण है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को ऑर्डर किए गए 83 एलसीए मार्क-1 में जीई-404 इंजन लगाया गया है। 'टू फ्रंट वार' की तैयारियां कर रही वायु सेना को एचएएल स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके-1ए की आपूर्ति 2023 से शुरू करेगा और 2027 तक सभी विमान वायु सेना को मिल जाएंगे। इसी तरह 40 तेजस एमके-1 विमानों की भी आपूर्ति 2023 के मध्य तक पूरी की जाएगी। एचएएल के मुताबिक, तेजस मार्क-2 की गति मैक 2 यानी 3,457 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसकी मारक रेंज 2,500 किलोमीटर होगी। यह 56 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 23 मिलीमीटर की जीएसएच-23 गन होगी। साथ ही इसमें हवा से हवा में मार करने वाली सात मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली चार मिसाइलें, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल, पांच बम लगाए जा सकते हैं। तेजस मार्क-2 में ब्रह्मोस-एनजी मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा निर्भय, स्टॉर्म शैडो, अस्त्र, मीटियोर, असराम और क्रिस्टल मेज जैसी मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं।

दोगुनी शक्तियों के साथ मिलेगा नया तेजस

तेजस फाइटर के जनक चीफ डिजाइनर डॉ. कोटा हरिनारायण ने बताया कि इस विमान में प्रीसिशन गाइडेड बम, लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम और स्वार्म बम लगाए जा सकते हैं। तेजस का दूसरा पार्ट दोगुनी शक्ति के साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। नई पीढ़ी के एयरक्राफ्ट में मिसाइलों को लगाने की क्षमता दोगुना तक बढ़ाई गई है। पहले 04 टन युद्धक सामग्री ही ले जा सकते थे, लेकिन अब 07 टन तक क्षमता बढ़ा दी गई है। नए तेजस में 09 के बजाए 11 हार्ड प्वाइंट्स लगाए गए हैं। इसके विंग तेजस की तुलना में 30 सेंटीमीटर बड़े हैं। विंग्स के आगे दोनों ओर कनॉट दिए गए हैं, जिससे दुश्मन के अटैक से बचाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। पीछे से अटैक होने पर विमान बैक साइड में इतना घना धुआं छोड़ देगा कि दुश्मन की मिसाइल कंफ्यूज होकर निशाने से चूक जाएगी। तेजस मार्क-2 के कॉकपिट में वाइस कमांड भी दिया गया है, ताकि पायलट को बटन पुश करने का समय न होने पर वह आवाज देकर ही मिसाइल अटैक कर सकता है। इस तरह के अटैक में राफेल फाइटर प्लेन से ज्यादा प्रभावी होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस का नया वर्जन मार्क-2 वायु सेना में मिग-29, जगुआर और मिराज फाइटर प्लेन की जगह लेगा।

नौसेना को मिला महाबली आईएनएस विक्रांत

नई दिल्ली: देश के लिए शुक्रवार 02 सितम्बर का दिन ऐतिहासिक रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर 'आईएनएस विक्रांत' भारतीय नौसेना को सौंपा। आईएनएस विक्रांत की खास बात ये है कि यह एक स्वदेशी युद्धपोत है। इस उपलब्धि के साथ ही भारत अब उन देशों के एलीट समूह में शामिल हो गया, जो एयरक्राफ्ट करियर बनाने में सक्षम हैं। फिलहाल, इन देशों की सूची में अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन का नाम शामिल है। इतना ही नहीं यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा करियर होगा।

इस मौके पर पीएम ने कहा, 02 सितम्बर, 2022 की ऐतिहासिक तारीख को, इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने, गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। दरअसल, एयरक्राफ्ट करियर मतलब समुद्र में तैरता एयरफोर्स स्टेशन। जहां से फाइटर जेट्स, मिसाइलें, ड्रोन्स उड़कर दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं। ये जल, जमीन और आसमान में शोले बरसा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईएसी विक्रांत दुनिया के दस सबसे ताकतवर विमानवाहक युद्धपोतों में शामिल है। बता दें कि आईए-नएस विक्रांत को 2009 में बनाना शुरू किया गया था। अब 13 साल बाद ये नौसेना को मिला है। INS विक्रांत एयरक्राफ्ट करियर समुद्र के ऊपर तैरता एक एयरफोर्स स्टेशन है जहां से फाइटर जेट्स, मिसाइलें, ड्रोन के जरिए दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूत किया जा सकता है। विक्रांत से 32 बराक-8 मिसाइलें दागी जा सकेंगी। 44,570 टन से अधिक वजनी, यह युद्धपोत 30 लड़ाकू जेट विमानों को समायोजित करने में सक्षम है और दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और निर्देशित बमों और रॉकेटों से परे जहाज-रोधी मिसाइलों से लैस है। यह विभिन्न विमानों को सम्भालने के लिए आधुनिक लॉन्च और रिकवरी सिस्टम से भी लैस है जैसे मिग -29 के लिए लूना लैंडिंग सिस्टम और सी हैरियर के लिए डीएपीएस लैंडिंग सिस्टम। इसकी अधिकतम गति 2469 किमी प्रतिघंटा होती है। विमानवाहक पोत के 2,300 डिब्बों में 1,700 नाविकों के लिए जगह है, साथ ही महिला अधिकारियों के लिए विशेष केबिन भी हैं और यह एक छोटे से शहर को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करने में सक्षम है। इसके अलावा आईएसी विक्रांत के अंदर 16 बेड का अस्पताल है। दो ऑपरेशन थिएटर हैं। प्राइमरी मेडिकल कॉम्प्लेक्स हैं। नौसेना ने जानकारी दी है कि इसके निर्माण में 76 फीसदी स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल हुआ है। 20 हजार करोड़ रुपये में आईएनएस विक्रांत को तैयार करने में 2 हजार सीएसएल कर्मी और अप्रत्यक्ष रूप से 13 हजार अन्य लोग भी शामिल रहे। आईए-नएस विक्रांत के फ्लाइट ट्रायल्स नवंबर तक शुरू हो जाएंगे और यह कैरियर साल 2023 के मध्य तक संचालन के लिए पूरी तरह तैयार होगा।

भारत ने अफगानिस्तान को भेजा 40 हजार मीट्रिक टन गेहूं

संयुक्त राष्ट्र: भारत ने क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि उसने अफगा-निस्तान को 40 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं भेजा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अफगानिस्तान को देश की ओर से पहुंचाई जा रही मदद का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने काबुल के पड़ोसी और पुराने साझेदार के रूप में अपनी स्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने वहां के गुरुद्वारों पर हो रहे हमलों पर भी चिंता जताई।

रुचिरा ने कहा कि हमने सुरक्षा परिषद में बार-बार कहा है कि शांति और स्थिरता की वापसी सुनिश्चित करने का भारत पक्षधर है। अफगान लोगों से हमारे मजबूत ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से की गई अपील के जवाब में हमने कदम उठाए हैं। भारत ने अफगा-निस्तान को मानवीय सहायता के कई शिपमेंट भेजे हैं। 10 बैचों में 32 टन चिकित्सा सहायता भेजी गई है। इसमें कोरोना टीकों की 5,00,000 खुराक शामिल हैं। यह चिकित्सा खेप विश्व स्वास्थ्य संगठन और काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल को सौंपी गई है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि काबुल में 18 जून को सिख गुरुद्वारे पर हमला हुआ। इसके बाद 27 जुलाई को उसी गुरुद्वारे के पास एक और बम विस्फोट हुआ। अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर हमलों की यह श्रृंखला बेहद खतरनाक है।

अजब-गजब

इस शहर में सांस लेने भर से हो जाती है मौत

दुनिया में कई जगहें अलग-अलग कारणों से मशहूर हैं। कुछ अपनी खूबसूरती की वजह से, कोई इतिहास तो कोई कुछ और ही कारण से। मगर क्या आपने कभी किसी जगह के बारे में सुना है, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो। इतना ही नहीं ये ऐसी जगह है, जहां पर सांस लेने भर से ही आप अपनी जिंदगी से हाथ धो सकते हैं। यही कारण है कि इस पूरे शहर को खाली करवा दिया गया है। अथॉरिटी द्वारा 31 अगस्त तक लोगों से पूरे शहर को खाली करने को कह दिया गया था। अब ये शहर पूरी तरह से वीरान है।

हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के विट्टेनुम शहर की। इसे माइनिंग टाउन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब इसे ऑस्ट्रेलिया का चेर्नोबिल कहा जाने लगा है। बताया जा रहा है कि इस शहर की हवा इतनी जहरीली हो गई थी कि यहां सांस लेना मुश्किल हो गया था। यहां सांस लेने पर जान जाने की भी सम्भावना से इंकार नहीं किया जा रहा था। इस वजह से टाउन से सारे रेसिडेंट्स को निकाल कर इसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। अब इस टाउन को मैप से हटाने की भी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। विट्टेनुम क्लोजर एक्ट के तहत लोगों को 31 अगस्त तक शहर खाली करने का अल्टीमेटम मिला था। लोगों को वार्निंग दी गई थी कि या तो खुद शहर छोड़ दें या उन्हें जबरदस्ती निकाला जाएगा। इस टाउन में 1943 से कई परिवार आकर बसने लगे थे। माइनिंग एरिया होने की वजह से यहां कई तरह जहरीली गैसों का रिसाव होता था। इस वजह धीरे-धीरे कई लोगों की जान जाने लगी। 1966 में लॉस और हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से विट्टेनुम माइन को बंद कर दिया गया। यहां माइनिंग को बैन कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक़, इसके बाद भी लोगों ने एरिया को खाली नहीं किया। नतीजा कि यहां रहने वालों में करीब दो हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई, यानी यहां रह रहे हर दस में एक की मौत हो गई। स्टडीज के मुताबिक़, माइन में काम करने वाले लगभग हर कर्मी की मौत हो चुकी है। इसके बाद 2006 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि विट्टेनुम से टाउन का तमगा छीन लिया जाएगा। 2007 में इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

श्रीलंका की मदद को राजी आईएमएफ

कोलंबो: ऐतिहासिक आर्थिक संकट से त्रस्त श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से सहारा मिला है। पिछले तीन महीने से चल रही कोशिशों और आईएमएफ टीम के श्रीलंका दौरे के बाद प्रारम्भिक समझौते के तहत श्रीलंका को 2.9 अरब डॉलर का कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

आजादी के बाद से श्रीलंका इस समय सर्वाधिक गम्भीर आर्थिक संकट झेल रहा है। देश के पास विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो गई है। इस कारण श्रीलंका में आवश्यक वस्तुओं का आयात तक रुक गया है। आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका ने भयावह राजनीतिक संकट भी देखा है, जिसमें न सिर्फ राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के आवासों पर आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया, बल्कि उनके दबाव में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को पद तक छोड़ने पड़े। आर्थिक संकट से निपटने के लिए श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई-एमएफ) से मदद की गुहार लगा रहा था। आईएमएफ की टीम तीन माह में दो बार श्रीलंका का दौरा कर चुकी है। पिछले कुछ दिनों से दूसरे दौर की चर्चा में जुटे आईएमएफ के अधिकारियों ने ऋण स्थिरता बहाल करने के उपायों पर पूरा जोर दिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने ने आईएमएफ टीम के साथ बैठक में देश में आर्थिक रूप से कमजोर समूहों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया था। आईएमएफ के वार्ता पैनल के प्रमुख पीटर ब्रेउर ने कहा कि उनकी टीम ने सरकार, विपक्ष और अन्य दलों के साथ चर्चा की और वाशिंगटन में मुख्यालय को तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट भेजी। आईएमएफ के प्रतिनिधियों ने ऋण पुनर्गठन और आर्थिक पुनरुद्धार की योजना तैयार करने में कमजोर समूहों के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने के बारे में तथ्यों को भी समझाया। इसके बाद आईएमएफ और श्रीलंका के अधिकारियों के बीच 2.9 अरब डॉलर कर्ज पर सहमति बनी। इस कर्ज की अवधि 48 माह निर्धारित की गई है।

पाकिस्तान से व्यापार सम्बंधों को फिर शुरू नहीं करना चाहता भारत

दिल्ली: भारत-पाकिस्तान व्यापार को फिर से शुरू करने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है, जिसने 2019 में एकतरफा वाणिज्यिक सम्बंधों को तोड़ दिया। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने इस सप्ताह की शुरूआत में कहा था कि व्यापार और मानवीय सहायता दोनों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि इस्लामाबाद भारत से सब्जियों और खाद्य पदार्थों के आयात पर विचार कर सकता है, ताकि बाढ़ के कारण होने वाली कमी से निपटने के लिए, जिसमें 1,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और 33 लाख प्रभावित हैं।

हालांकि, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मंगलवार 30 अगस्त को की गई टिप्पणी, जिसमें कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए व्यापार की बहाली को जोड़ा गया था, भारत के पक्ष में अच्छा नहीं रहा है। इस दौरान जब उनसे मानवीय सहायता और व्यापार के मुद्दों के बारे में पूछा गया, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताअरिंदम बागची गैर-प्रतिबद्ध थे। बागची के मुताबिक, पाकिस्तान में आई बाढ़ के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से हुई तबाही पर अपना दुख साझा किया है। आपने उनकी टिप्पणियां देखी हैं। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों, घायलों और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। फिलहाल, सहायता के मुद्दे पर मुझे बस इतना ही कहना है।

गरीबी की चपेट में आ सकती है पाकिस्तान की 37 फीसदी आबादी

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ ने जान-माल के नुकसान के अलावा 10 अरब डॉलर से लेकर 12.5 अरब डॉलर तक का आर्थिक नुकसान किया है। चालू वित्त वर्ष में यह नुकसान 30 प्रतिशत है, यह जानकारी सरकारी सूत्रों के जरिए सामने आई है।

वित्त मंत्रालय, योजना मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एफबीआर, पीआईडीई और अन्य के प्रतिनिधित्व वाली एक हाई-प्रोफाइल समिति ने मूल्यांकन किया कि गरीबी और बेरोजगारी कई गुना बढ़ गई है, जो 21.9 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत से अधिक हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, देश के 118 जिलों में भयंकर बाढ़ आने के बाद से लगभग 37 प्रतिशत आबादी गरीबी की चपेट में आ गई है। बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, लेकिन सरकार ने सम्बंधित हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद किसी भी संख्या को साझा करने का निर्णय लिया है। हाल ही में आई भीषण बाढ़ से पहले बेरोजगारी दर छह प्रतिशत थी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर पांच फीसदी से घटाकर दो फीसदी की जाएगी। बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुलासा किया कि चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर 04 प्रतिशत से घटाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया जाएगा। बाढ़ के बाद कृषि विकास को बहुत गम्भीर प्रभाव का सामना करना पड़ा और चालू वित्त वर्ष में 500 अरब रुपए से अधिक की कृषि वृद्धि का मूल्यवर्धन लुप्त हो सकता है। कृषि विकास लक्ष्य और सेवा क्षेत्र को गंभीर प्रभावों का सामना करना पड़ा। 2022-23 के बजट की पूर्व संध्या पर देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में तीन प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया गया है और यह जीडीपी के लगभग 02 प्रतिशत के आस-पास रहेगा। इसी तरह आर्थिक मोर्चे पर भारी नुकसान बढ़ सकता है, क्योंकि एसबीपी के मॉडल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी जिलों और तहसीलों में प्रभावित आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने के आधार पर नुकसान का पता लगाने का अनुमान है। एसबीपी कृषि क्षेत्र को होने वाले नुकसान का सटीक आंकलन करने के लिए सुपार्को की उपग्रह छवियों का उपयोग कर रहा है। गूगल ने सरकार को कृषि और भौतिक बुनियादी ढांचे को कुल संचित नुकसान का पता लगाने के लिए अपनी सेवाएं प्राप्त करने की भी पेशकश की है। देश में 2010 में आई पिछली बाढ़ ने 78 जिलों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन हाल की बाढ़ की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे उन क्षेत्रों के 118 जिलों में नुकसान हुआ है, जो आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के एक अनुमान के मुताबिक, अब तक लगभग 1,290 नागरिकों ने बाढ़ की चपेट में आकर अपनी जान गंवाई है।

उइगर मुस्लिमों का दमन कर रहा चीन

बीजिंग: चीन में रहने वाले मुस्लिम सुरक्षित नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार रिपोर्ट में चीन में रहने वाले उइगर मुस्लिमों का दमन किए जाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में मुस्लिम महिलाओं से दुष्कर्म और पुरुषों की जबरन नसबंदी जैसे जुल्म ढहाए जा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बैचलेट ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन 31 अगस्त को चीन में मानवाधिकारों को लेकर बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट जारी कर दी। 48 पेज की इस रिपोर्ट में चीन पर मानवा-धिकारों के जबर्दस्त उल्लंघन की बात कही गई है। चीन की गतिविधियों को गम्भीर बताते हुए उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया गया है। चीन के सुदूर शिनजियांग प्रांत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर आई इस रिपोर्ट में बड़ी संख्या में उइगर मुस्लिमों के लापता होने का भी दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, उइगर और अन्य प्रमुख मुस्लिम जातियों को मनमाने और भेदभावपूर्ण ढंग से हिरासत में रखा जा रहा है। चीन अपने सुरक्षा कानूनों का मनमाने ढंग से अमल करते हुए अल्पसंख्यकों का दमन कर रहा है। चीन के बंदी शिविरों में 10 लाख उइगर मुसलमान कैद हैं। रिपोर्ट में चीन की इस हरकत को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्राप्त मौलिक अधिकारों का हनन करार देकर मानवता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध बताया गया है। रिपोर्ट में चीन से अपील की गई है कि वह अवैध और मनमाने ढंग से कैद सभी उइगर मुस्लिमों को तत्काल रिहा करे। चीन ने इस रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह रिपोर्ट चीन विरोधी ताकतों की गढ़ी गई गलत सूचना और झूठ पर आधारित है।

और मजबूत होगी भारत-फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर हुई चर्चा

पेरिस: भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी और मबजूत की जाएगी। पेरिस में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में परस्पर हित के कई मुद्दों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

सितम्बर माह में फ्रांस और उसके बाद दिसम्बर में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का दायित्व सम्भालना है। उससे पहले पेरिस में भारत और फ्रांस के उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने व्यापक विचार विमर्श किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के संयुक्त सचिव श्रीप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस के यूरोप और विदेशी मामलों के मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निदेशक फेबियन पेनोन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना और परस्पर हित के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में अपने सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। कहा गया कि दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। सितम्बर और दिसम्बर में फ्रांस और भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किए जाने को लेकर भी दोनों देशों के नेताओं व अधिकारियों ने एक-दूसरे को जानकारी दी। उन्होंने इसी माह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के दौरान सप्ताह भर चलने वाली उच्चस्तरीय गतिविधियों पर गहन विचार-विमर्श किया।

भारत ने 10 महीने बाद काबुल में खोला दूतावास

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार 01 सितम्बर को कहा कि कुछ राजनयिक देश की तकनीकी टीम का भी हिस्सा हैं, जिसे काबुल स्थित दूतावास में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि काबुल में हमारी एक तकनीकी टीम है, जिसमें कुछ राजनयिक हैं। हमारा ध्यान उनके साथ मिलने वाली मानवीय सहायता पर है। जून में, भारत ने घोषणा की कि मानवीय सहायता के वितरण के लिए हितधारकों के प्रयासों के समन्वय के लिए काबुल में दूतावास में एक तकनीकी टीम तैनात की गई है।

मानवीय सहायता के प्रभावी वितरण के लिए विभिन्न हितधारकों के प्रयासों की बारीकी से निगरानी और समन्वय करने के लिए और अफगान लोगों के साथ हमारे जुड़ाव को जारी रखने के लिए एक भारतीय तकनीकी टीम आज काबुल पहुंच गई है और वहां हमारे दूतावास में तैनात की गई है। तालिबान ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता जारी रखने के लिए काबुल में अपने दूतावास में अपनी तकनीकी टीम को वापस करने के भारत के फैसले का स्वागत किया था। तालिबान के प्रवक्ता अब्दुल कहार बल्खी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात (एलईए) ने अफगान लोगों के साथ अपने सम्बंधों और उनकी मानवीय सहायता को जारी रखने के लिए काबुल में राजनयिकों और तकनीकी टीम को उनके दूतावास में वापस करने के भारत के फैसले का स्वागत किया है। अफगानिस्तान में भारतीय राजनयिकों की वापसी और दूतावास को फिर से खोलना दर्शाता है कि देश में सुरक्षा स्थापित है और सभी राजनीतिक और राजनयिक अधिकारों का सम्मान किया जाता है। तालिबान के प्रवक्ता ने अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक प्रथाओं के अनुरूप सभी मौजूदा दूतावासों के लिए सुरक्षा का आश्वासन दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगान समाज के साथ भारत के लम्बे समय से सम्बंध और अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता सहित दोनों देशों के बीच विकास साझेदारी आगे बढ़ने के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करना जारी रखेगी। अफगानिस्तान का समर्थन करने के लिए, भारत की भूकम्प राहत सहायता की विभिन्न खेप काबुल पहुंची। भूकम्प से प्रभावित अफगान नागरिकों की सहायता के लिए भारतीय टीम द्वारा खेप सौंपी गई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में 6.1 तीव्रता के भूकम्प के बाद 1,000 से अधिक लोगों की जान जाने के बाद यह समर्थन बढ़ाया गया था।

नौसेना को मिला नया ध्वज व निशान

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 02 सितम्बर को आईएनएस विक्रांत को नौसेना के बेड़े में शामिल करने के साथ नौसेना के नए ध्वज का अनावरण करके औपनिवेशिक काल की गुलाम मानसिकता के प्रतीक से छुटकारा भी दिलाया। नौसेना का नया निशान (ध्वज) औपनिवेशिक अतीत को पीछे छोड़ते हुए समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के अधिकतर देशों ने अब अपने नौसेना के निशान को बदल दिया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हैं। इन सभी देशों के ध्वज पर पहले ब्रिटिश झंडा लगा रहता था।

भारतीय नौसेना के नए ध्वज में सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर का प्रतिनिधित्व करने वाले अष्टकोण में संलग्न एक गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर भारतीय नौसेना शिखा का परिचय देता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहले ही एक बयान जारी करके कहा था नया निशान 'औपनि-वेशिक अतीत से दूर.. समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप' होगा। देश की आजादी से अब तक नौसेना के निशान को चार बार बदला जा चुका है। अब फिर इसी निशान या ध्वज को प्रधानमंत्री मोदी ने बदलकर औपनि-वेशिक काल की गुलामी की मानसिकता के प्रतीक से छुटकारा दिलाया है। दरअसल, किसी भी देश की नौसेना का एक ध्वज होता है जो युद्धपोतों, ग्राउंड स्टेशनों और हवाई अड्डों सहित सभी नौसैनिक प्रतिष्ठानों के ऊपर फहराया जाता है। भारतीय नौसेना का भी अपना निशान या ध्वज है, जिसमें अब तक सफेद रंग के आधार पर लाल रंग का क्रॉस बना हुआ था जो सेंट जॉर्ज का प्रतीक है। ध्वज के ऊपरी कोने में तिरंगा और साथ ही क्रॉस के बीच में अशोक चिह्न बना हुआ था। भारतीय नौसेना के इतिहास को देखा जाए, तो 02 अक्टूबर 1934 को नेवल सर्विस को रॉयल इंडियन नेवी का नाम दिया गया। देश का विभाजन होने के बाद जब भारत और पाकिस्तान की अलग-अलग सेनाएं बनीं, तो नौसेना रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल पाकि

'ब्रह्मास्त्र' से दूर होगा बॉलीवुड पर लगा फ्लॉप का ग्रहण !

रणबीर, ऋतिक और सैफ जैसे सुपरस्टार दिखाएंगे अपनी ताकत, बॉलीवुड को है एक बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट की दरकार

आईपीके, लखनऊः बॉलीवुड पर लगा फ्लॉप का ग्रहण हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। आधे से ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी बॉलीवुड के खाते में सिर्फ 2 से 3 हिट फिल्में ही आई हैं। इस बीच बड़े बैनर और बड़े स्टार्स की फिल्में भी रिलीज हुईं, मगर वो भी दर्शकों को रिझा पाने में पूरी तरह से नाकाम ही साबित हुई हैं। आलम ये है कि इस समय न एक्शन का तड़का काम आ रहा है, न हीरो का टशन, न कॉमेडी चल रही है और न ही इमोशन। इसके चलते अब इंडस्ट्री में भी एक टेंशन का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अब सितम्बर के महीने से पूरे बॉलीवुड को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस महीने कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली हैं।

सितम्बर के महीने में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, ऋतिक रोशन जैसे सितारे बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखाने वाले हैं। इस बीच सबसे ज्यादा नजरें जिस फिल्म पर टिकी हैं वो है रणबीर-आलिया की साल की सबसे बड़ी फिल्म 'ब्रह्मास्त्र'। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म से पूरी इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं। हर किसी को उम्मीद है कि बॉलीवुड पर लगा फ्लॉप का ग्रहण ब्रह्मास्त्र हटा देगी और इंडस्ट्री के लिए एक नया जीवन देने वाली फिल्म साबित होगी। इसके अलावा इस महीने सैफ अली खान और ऋतिक रोशन स्टारर 'विक्रम वेधा' भी सिनेमाघरों में दस्तक देगी। एक्शन से भरपूर इस फिल्म से भी अच्छी कमाई की काफी उम्मीदें हैं। इनके अलावा इस महीने कई ऐसी फिल्में रिलीज होंगी, जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका साबित हो सकती हैं। सिनेमाघरों से इतर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कुछ बॉलीवुड फिल्में इस महीने रिलीज होंगी। जानते हैं इस महीने रिलीज होने वाली फिल्मों की पूरी लिस्ट।

कठपुतली

इस महीने की शुरूआत बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' कहे जाने वाले अभिनेता सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म 'कठपुतली' से हुई। अक्षय के लिए ये साल काफी निराश करने वाला रहा है। इस साल उनकी बैक टू बैक तीन बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हुईं हैं। इसलिए इस बार अक्षय ने अपनी फिल्म 'कठपुतली' को सिनेमाघरों में न रिलीज करके ओटीटी पर लाने का फैसला किया है। मर्डर मिस्ट्री पर आधारित अक्षय की ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 02 सितम्बर से ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। फिल्म में अक्षय एक बार फिर पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे हैं, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री सुलाझाते हुए सीरियल किलर को पकड़ रहे हैं। 'कठपुतली' 2018 में आई तमिल की सुपरहिट क्राइम थ्रिलर 'रतसासन' का हिंदी रीमेक है। उस फिल्म में विष्णु विशाल और अमाला पॉल लीड रोल में नजर आए थे। वहीं 'कठपुतली' में अक्षय के अपोजिट एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह हैं।

ब्रह्मास्त्र- पार्ट वनः शिवा

बॉलीवुड पर लगे फ्लॉप के ग्रहण को दूर करने की जिम्मेदारी अब इस साल की सबसे बड़ी व बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' पर है। कई सालों से बन रही इस फिल्म को लेकर सभी के बीच काफी क्रेज दिखाई दे रहा है। अब ये मोस्ट अवेटेड फिल्म 09 सितम्बर को सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है। अब तक फिल्म के ट्रेलर और गानों को भी लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। ऐसे में सभी को उम्मीद है कि रणबीर-आलिया की ये साई-फाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल बिखेर सकी है। इस मल्टी स्टारर फिल्म को बनाने में निर्देशक अयान मुखर्जी ने काफी मेहनत की है, जो फिल्म के ट्रेलर में दिखाई देती है। फिल्म के विजुअल्स और वीएफएक्स को काफी अच्छे से तैयार किया गया है। इस फिल्म में हिट होने के कई गुण नजर आते हैं। फिल्म में पहली बार रियल कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक साथ नजर आने वाले हैं। इन दोनों के अलावा फिल्म में आमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय जैसे सितारे भी नजर आएंगे। हालांकि, सारा दारोमदार फिल्म की कहानी पर टिका हुआ है, क्योंकि ये तो साफ है कि ब्रह्मास्त्र एक निगेटिव माहौल में रिलीज हो रही है। इस समय पूरे बॉलीवुड को ही बायकॉट करने की मांग की जा रही है। ऐसे में इतने लम्बे समय से बन रही इस बहु-प्रतीक्षित फिल्म पर पहले से ही काफी दबाव है। ब्रह्मास्त्र निर्देशक अयान मुखर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर वो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। यह एक ट्राइलॉजी फिल्म है, जिसे तीन पार्ट में रिलीज किया जाएगा। ब्रह्मास्त्र में अस्त्रों की कहानी बताई गई है। फिल्म के पोस्टर से साफ पता चलता है कि हर कैरेक्टर की कहानी एक अस्त्र पर आधारित है। वारणसी से शुरू हुई थी ब्रह्मस्त्र की कहानी। फिलहाल फिल्म को लेकर क्रेज तो काफी है, अब देखना है इस बायकॉट के दौर में 'ब्रह्मास्त्र' दर्शकों के दिलों पर छा पाती और बॉलीवुड पर लगा फ्लॉप का ठप्पा हटा पाती है या नहीं।

सिया

बड़े बजट और सुपरस्टार्स के बीच एक छोटे बजट की दमदार कहानी वाली फिल्म 'सिया' भी इस महीने रिलीज हो रही है। न्यूटन और मसान जैसी दमदार कंटेंट वाली फिल्में दे चुके दृश्य फिल्म्स द्वारा निर्मित 'सिया' यह एक छोटे से शहर की लड़की की कहानी है, जो सभी बाधाओं का सामना करते हुए न्याय के लिए लड़ने का फैसला करती है और शातिर पुरुष प्रधान व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करती है। अभिनेत्री पूजा पांडेय और रंगबाज के स्टार विनीत कुमार सिंह ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। मनीष मुंद्रा द्वारा निर्देशित ये फिल्म 16 सितम्बर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

चुप : रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट

बॉलीवुड के एक्शन स्टार और ढाई किलो के हाथ वाले सनी देओल इस महीने एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। अपनी फिल्मों में कुछ अलग और हटकर करने के लिए जाने जाने वाले इंडस्ट्री के मशहूर निर्देशक आर. बाल्की अब एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है 'चुप : रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट'। इस फिल्म में सनी देओल, दुलकर सलमान, श्रेया धनवंतरी और पूजा भट्ट प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। आर बाल्की की साइकोलॉजिकल थ्रिलर यह फिल्म 23 सितम्बर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म के माध्यम से दिग्गज फिल्म निर्माता गुरु दत्त और उनकी क्लासिकल फिल्म 'कागज के फूल' को श्रद्धांजलि देने की कोशिश की गई है। इस फिल्म की एक खास बात ये भी है कि इस फिल्म से इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन बतौर म्यूजिक कम्पोजर अपना डेब्यू कर रहे हैं।

धोखा

अपनी फिल्म 'रॉकेट्री : द नंबी इफेक्ट' से चारों तरफ प्रशंसा बटोरने के बाद अब अभिनेता आर. माधवन अपनी नई फिल्म को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। अभिनेता इस महीने रिलीज होने वाली नई फिल्म 'धोखा राउंड डी कॉर्नर' में नजर आने वाले हैं। यह एक सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें माधवन के अलावा अभिनेता अपारशक्ति खुराना और दर्शन कुमार भी नजर आने वाले हैं। ट्विस्ट और टर्न से भरपूर ये फिल्म एक कपल की जिंदगी पर आधारित है।

विक्रम वेधा

इस महीने की दूसरी बड़ी फिल्म है 'विक्रम वेधा'। ये फिल्म साउथ की इसी नाम से बनी फिल्म का ऑफिशियली रीमेक है, जिसमें सुपरस्टार ऋतिक रोशन और अभिनेता सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। अभी हाल ही में रिलीज किए गए फिल्म के टीजर को लोगों ने काफी पसंद किया। ताबड़तोड़ एक्शन से भरपूर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने की पूरी उम्मीद है। विक्रम वेधा 30 सितम्बर को सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

फिर दी जाएगी शाहरुख और आईएफएफएम की स्कॉलरशिप

मुंबईः बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के लाखों चाहने वाले हैं। कोई उनकी एक्टिंग का फैन है, तो उन लोगों की भी कमी नहीं है जो रील से इतर रियल लाइफ शाहरुख के दीवाने हैं। अक्सर अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाने वाले किंग खान अपनी स्कॉलरशिप के साथ दोबारा लौट आए हैं, जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेल्बर्न और ला ट्रोब विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में है।

इस स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन हाल ही में 18 अगस्त से शुरू हुआ और 23 सितम्बर तक चलेगा। पहली बार स्कॉलरशिप की घोषणा 2019 के उत्सव में की गई थी, जिसमें शाहरुख मुख्य अतिथि थे और इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय गए थे। इसके तुरंत बाद, केरल के त्रिशूर की भारत की गोपिका कोट्टंथरायिल भासी को पहली स्कॉलरशिप से

सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय ने व्यक्त किया कि यह 800 से अधिक आवेदकों के साथ स्कॉलरशिप के लिए उनका सबसे अधिक आवेदन किया गया था और इसलिए स्कॉलरशिप को फेस्टिवल के सौजन्य से वापस पेश किया गया, जिसने इसे सुविधाजनक बनाया। चयन के लिए टॉप मानदंड यह है कि उम्मीदवार को एक महिला भारतीय नागरिक होना चाहिए, जो भारत में रह रही हो और पिछले 10 वर्षों के भीतर मास्टर ऑफ रिसर्च की डिग्री पूरी कर ली हो। चयनित छात्रा को चार साल की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी फुल-फीस रिसर्च स्कॉलरशिप मिलेगी। फेस्टिवल के डायरेक्टर मीतू भौमिक लांगे ने कहा कि शाहरुख का दिल बहुत बड़ा है और उन्होंने इसे एक बार फिर साबित कर दिया है। स्कॉलरशिप भारत की एक महिला शोधकर्ता के लिए जीवन बदलने वाला अवसर है। भारत प्रतिभा से भरा है और बस उस चिंगारी को प्रज्वलित करने की जरूरत है। आईएफएफएम के फिजिकल इवेंट के दौरान 2019 में स्कॉलरशिप की घोषणा की गई थी, लेकिन महामारी और यात्रा प्रतिबंधों के कारण इसे पिछले साल के लिए रोक दिया गया था। दुनिया के टॉप विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में नामित, ला ट्रोब विश्वविद्यालय ने भारत के कुछ प्रसिद्ध गणमान्य व्यक्तियों की मेज़बानी की है, जैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कपिल देव, मलाइका अरोरा, अमिताभ बच्चन, राजकुमार हिरानी।

इंडस्ट्री में पहचान बनाना नहीं आसानः विजय वर्मा

मंबईः अभिनेता विजय वर्मा को हिंदी फिल्म उद्योग में एक दशक हो गया है और उन्होंने 'चटगांव', 'पिंक', 'गली बॉय', 'मिर्जापुर' और अपनी नवीनतम रिलीज 'डार्लिंग्स' में अपने प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरीं। बॉलीवुड अभिनेता का कहना है कि इंडस्ट्री में नाम बनाना आसान नहीं है और उन्हें अपने काम से खुद को साबित करना होता है।

उद्योग में बाधाओं का सामना करने के बारे में बात करते हुए विजय ने कहा कि कई सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन अंततः आप समझ सकते हैं कि यही बाधाएं आपके बढ़ने और आपकी जिंदगी की यात्रा का हिस्सा हैं। बेशक यह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को सलाम जो सालों से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपकी एक फिल्म या एक प्रदर्शन आपके बारे में पूरी राय तरह से बदल सकता है। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे गैर-फिल्मी पृष्ठभूमि से आने वाले और बाहरी व्यक्ति के लिए अवसर प्राप्त करना भी आसान नहीं है। मुझे वास्तव में अपने काम के माध्यम से साबित करना था। मुझे बस अवसरों की उम्मीद थी और जब मुझे अवसर मिले तो मैंने पूरी लगन से काम किया। 36 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि यह उनका काम ही है, जो उनके लिए बोलता है। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि अपने काम की वजह से ही मुझे और काम मिल रहा है।

फिल्मफेयर अवॉर्ड में दिखा 'शेरशाह' और 'सरदार उधम' का जलवा

रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर और कृति सेनन बनीं बेस्ट एक्ट्रेस

मुंबईः फिल्म जगत के सबसे लोकप्रिय अवॉर्ड 67वें फिल्मफेयर अवॉर्ड की घोषणा मंगलवार 30 अगस्त को कर दी गई। इस बार शो को रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर ने होस्ट किया। रेड कार्पेट पर कियारा आडवाणी, कार्तिक आर्यन, विक्की कौशल और दिया मिर्जा का खूबसूरत अवतार देखने को मिला। इस बार के अवॉर्ड समारोह में सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'शेरशाह' और विक्की कौशल की 'सरदार उधम' का दबदबा देखने को मिला। वहीं रणवीर सिंह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कृति सेनन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर की 'ब्लैक लेडी' को अपने साथ घर ले गए। 'शेरशाह' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म (लोकप्रिय) और निर्देशक विष्णु वर्धन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला।

इन्होंने मारी बाजी

अभिनेता रणवीर सिंह ने एक बार फिर अपने अभिनय से प्रभावित किया, जिसका नतीजा रहा कि उन्हें फिल्म '83' के लिए बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल (मेल) का फिल्मफेयर अवॉर्ड, जबकि फिल्म 'मिमी' के लिए कृति सेनन को बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल (फीमेल) का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला। क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड में 'सरदार उधम' के लिए विक्की कौशल को मिला बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स) का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला, जबकि फिल्म 'शेरनी' के लिए विद्या बालन को मिला बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स) का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला।

67वें फिल्मफेयर अवॉर्ड के विजेता

सर्वश्रेष्ठ अभिनेताः रणवीर सिंह (83)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीः कृति सेनन (मिमी)
सर्वश्रेष्ठ फिल्मः शेरशाह
सर्वश्रेष्ठ फिल्म (क्रिटिक्स): शूजीत सरकार (सरदार उधम)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (क्रिटिक्स): विक्की कौशल (सरदार उधम)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (क्रिटिक्स): विद्या बालन (शेरनी)
सर्वश्रेष्ठ कहानीः अभिषेक कपूर, सुप्रतीक सेन और तुषार परांजपे (चंडीगढ़ करे आशिकी)
बेस्ट डायलॉगः दिबाकर बनर्जी और वरुण ग्रोवर (संदीप और पिंकी फरार)
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेलः साई तम्हंकर (मिमी)
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेलः पंकज त्रिपाठी (मिमी)
बेस्ट कोरियोग्राफीः विजय सिंह (चका-चक, अतरंगी रे)
बेस्ट एक्शनः शेरशाह
बेस्ट कॉस्ट्यूमः सरदार उधम
बेस्ट वीएफएक्सः सरदार उधम
बैकग्राउंड स्कोरः सरदार उधम
बेस्ट एडिटिंगः शेरशाह
बेस्ट साउंड डिसाइनः सरदार उधम
सर्वश्रेष्ठ गीतकारः कौसर मुनीर फॉर सॉन्ग लहरा दो (83)
बेस्ट प्लेबैक सिंगर : बी प्राक (मन भरया, शेरशाह)
बेस्ट डेब्यूः शरवरी वाघ (बंटी और बबली 2)
बेस्ट डेब्यू मेलः एहान भट (99 सॉन्ग्स)
सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशकः सीमा पाहवा (रामप्रसाद की तेहरवीं)
बेस्ट स्क्रीनप्लेः शुभेंदु भट्टाचार्य और रितेश शाह (सरदार उधम)
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्डः सुभाष घई

'मडगांव एक्सप्रेस' से निर्देशन की शुरूआत करेंगे कुणाल खेमू

मुंबईः बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू वह हैं, जिन्हें दर्शकों ने सेल्युलाइड पर बड़े होते देखा है। अभिनेता अब फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' के साथ अपने निर्देशन की शुरूआत करने के लिए तैयार हैं। अभिनेता ने 'जख्म', 'राजा हिंदुस्तानी' और 'हम हैं राही प्यार के' जैसी फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और 'कलयुग', 'गो गोवा गॉन', 'ढोल' और कई फिल्मों में सुर्खियों में रहे।

कुणाल ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर ट्विटर पर अपने निर्देशन की शुरूआत की खबर अपने प्रशंसकों के साथ साझा की, क्योंकि उन्होंने फिल्म की घोषणा का पोस्टर लगाया था। उन्होंने लिखा कि गणपति बप्पा मोरिया। जैसा कि सभी अच्छी चीजें उनके नाम से शुरू होती हैं, मैं इसे आप सभी के साथ साझा करने के लिए बेहतर दिन नहीं सोच सकता। फिल्म की यात्रा को अपने दिमाग में एक विचार से एक विशेषता बनने तक एक साथ जोड़ते हुए उन्होंने आगे लिखा कि यह मेरे दिमाग में एक विचार के साथ शुरू हुआ जो एक सपने में विकसित हुआ जो मेरी उंगलियों से मेरे लैपटॉप पर शब्दों में बह गया और अब यह बन रहा है सिल्वर स्क्रीन के रास्ते पर एक वास्तविकता। उन्होंने एक्सेल एंटरटे-नमेंट के निर्माता रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर के प्रति भी आभार व्यक्त किया।

जबरन वसूली मामले में 26 सितम्बर को जैकलीन कोर्ट में तलब

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार 31 अगस्त को अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीस को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कथित जबरन वसूली मामले में 26 सितम्बर को पेश होने के लिए समन जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडीस का नाम लेने के बाद ये समन जारी किया गया है।

ईडी द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश परवीन सिंह ने अभिनेत्री को 26 सितम्बर को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है। हाल ही में ईडी ने जैकलिन की कई फिक्सड डिपोजिट को यह कहते हुए कुर्क कर लिया कि पैसे गलत तरीके से अर्जित किए गए हैं। ईडी ने अभिनेत्री के खिलाफ 17 अगस्त को दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। जांच एजेंसी ने जैकलिन की 7.2 करोड़ रुपये की एफडी को अपराध की आय बताते हुए कुर्क कर दिया था। फरवरी में, ईडी ने चंद्रशेखर की कथित सहयोगी पिंकी ईरानी के खिलाफ अपनी पहली पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की थी, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड अभिनेत्रियों से मिलवाया था। चार्जशीट के अनुसार, पिंकी जैकलिन के लिए महंगे उपहार लाती थी जिसका भुगतान चंद्रशेखर करता था। ईडी ने पिछले साल दिसम्बर में इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। चंद्रशेखर ने मॉडलों और बॉलीवुड हस्तियों के लिए गिफ्ट खरीदने पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किए। जैकलिन ने चंद्रशेखर से महंगे तोहफे मिलने की बात कबूल की है।

लाइफस्टाइल फंडा

लोगों में तेजी से बढ़ रही थायराइड की समस्या

कई तरह की होती है थायराइड, जोड़ों में दर्द और चेहरे पर सूजन है प्रमुख लक्षण

आईपीके, लखनऊः आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य खुद की तरफ कम ध्यान दे पाता है। जब तक वो अपनी ओर ध्यान देना शुरू करता है, तब तक वह कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो चुका होता है। उसकी जिंदगी दवाइयों पर निर्भर हो जाती है। कुछ रोग ऐसे हो जाते हैं, जिनमें उसे सारी उम्र दवा खानी पड़ती है।

इसी प्रकार की एक समस्या या बीमारी है थायराइड। थायराइड ऐसी समस्या है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पुरुष हो या महिला हर कोई बड़ी तेजी से इस बीमारी का शिकार हो रहा है। हर व्यक्ति के गले के सामने के भाग में तितली के आकर की एक ग्रंथि होती है, जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इससे हार्मोंस का स्राव होते हैं। टी-3 यानी त्रिआईडोथायरॉनिन और टी-4 यानी थायरॉक्सिन मुख्य हार्मोन होते हैं और इन हार्मोन्स को ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन नियंत्रित करता है। टी-3 और टी-4 शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। इन हार्मोंस के अलावा केल्सिटॉनिन नामक हार्मोन भी स्रावित होता है। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है। ये हार्मोंस शरीर में बहुत सी क्रियायों को नियंत्रित करते हैं,

जैसे- डेवलपमेंट, मेटाबॉलिजम, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना आदि।

कई तरह की होती है थायराइड डिजीज

घेंघा - यह शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। इसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है।
हाइपरथायरॉडिज्म - इसमें थायराइड हार्मोन का बहुत ज्यादा स्त्राव होता है।
हाइपोथायरॉडिज्म - इसमें थायराइड हार्मोन का स्राव कम होता है।
ग्रेव्स डिजीज - इसमें थायराइड ग्लैंड हॉर्मोन बनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं।
थायराडाइटिस - इसमें समय बीतने के साथ सूजन के कारण हार्मोन बनने बंद हो जाते हैं।
थायराइड कैंसर - इसमें थायराइड ग्रंथि का कैंसर हो जाता है।
थायराइड नोड्यूल - इसमें थायराइड ग्लैंड में गांठ हो जाती हैं।

थायराइड के लक्षण

थायराइड के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो कब्ज होना, डिप्रेशन होना, शरीर का तापमान बढ़ना, कम होना, भूख ज्यादा लगना, हाथों में कंपन होना, पसीना ज्यादा आना, बाल सफेद होना एवं झड़ना, थकान होना, चिड़चिड़ाहट होना, खुजली होना, सांस लेने में तकलीफ होना, नर्वस होना, धड़कन बढ़ना या कम होना, वजन बढ़ना या कम होना, उच्च रक्तचाप, त्वचा रूखी होना, धड़कन कम होना, चेहरे पर सूजन रहना, महिलाओं में माहवारी से सम्बंधित तकलीफ होना, मसल्स में कमजोरी और अकड़न, जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन, नींद की समस्या होना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं।

थायराइड बढ़ने के कारण

हॉर्मोन्स की गड़बड़ी। शरीर में आयोडीन की मात्रा सही होने के बाद भी नमक के माध्यम से शरीर में अतिरिक्त आयोडीन जाना। किसी दवाई के साइड इफेक्ट के कारण थायराइड की समस्या पैदा हो सकती है।

पोषक तत्वों से भरपूर अरबी के पत्ते, कई तरह के रोगों को रखें दूर

आईपीके, लखनऊः प्रकृति ने हर मौसम के अनुसार सेहत को चुस्त-दुरूस्त बनाए रखने के लिए कई चीजें हमें दी हैं। बारिश के मौसम में वातावरण में नमी के चलते कई तरह के बैक्टीरिया और बीमारियां फैलती हैं। इसलिए इनसे बचे रहने के लिए इस मौसम में अरबी की पत्तियां बहुतायत मात्रा में मिलती हैं। जो कि सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। अरबी के पत्तों में विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, पोटैशियम और एंटीऑ-क्सिडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बाजारों में अरबी आने के बाद से इसके पत्तों की सब्जी या पकौड़ियां हर किसी के घर में आपको आसानी से मिल जाएंगे। सब्जी से ज्यादा अरबी के पत्तों के पकौड़े लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं। अरबी की पत्ती स्वाद के साथ ही सेहत के लिए भी सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। आयुर्वेद में भी इसे सेहत के लिए लाभकारी माना गया है। आइए जानते हैं अरबी के पत्तों के सेवन के ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में-

एसिडिटी की समस्या को करे दूर

स्वाद के सेहत के लिए भी लाभकारी माने जाने वाले अरबी के पत्ते पेट सम्बंधी आपकी बीमारी में काफी लाभकारी साबित हो सकते हैं। दरअसल, अरबी के पत्तों में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे पाचन क्रिया दुरूस्त रहती है। साथ ही यह एसिडिटी की समस्या को भी दूर रखती है।

- विटामिन्स, कैल्शियम, पोटैशियम और एंटीऑ-क्सिडेंट जैसे गुणों से भरपूर
- हार्ट सम्बंधी रोगों में भी दिलाए राहत
- गर्भवती महिलाएं अवश्य करें इनका सेवन

आंखों की समस्याओं को करे दूर

अरबी के पत्ते आंखों की सेहत का भी ध्यान रखते हैं। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन जो शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। यह आंखों की समस्याओं को दूर रखता है। इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है।

हार्ट के गुड फ्रेंड हैं ये पत्ते

आजकल हार्ट सम्बंधित बीमारियां लोगों में काफी तेजी से बढ़ रही हैं। बुजुर्गों के अलावा आजकल के युवा इसके भारी संख्या में रोगी बन रहे हैं। यही कारण है कि ये काफी तेजी से युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में अरबी के पत्ते हार्ट सम्बंधी बीमारी में भी आपकी मदद कर सकते हैं। अरबी के पत्ते और दिल की आकृति एक जैसी होती है। इसलिए यह हार्ट का भी गुड फ्रेंड है। इसके पत्तों में फोलेट पाया जाता है, जो ब्लड वेसेल्स को अंदर से स्वस्थ रखते हैं और आर्टरी के ब्लड सर्कुलेशन को सही करने में भी

सहायक होते है।

वजन को करे कंट्रोल

अरबी के पत्ते वजन को भी कम करने में मददगार साबित होते हैं, क्योंकि इसके पत्तों में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है। जिससे वजन कंट्रोल होता है। अरबी के पत्तों में आयरन भी पाया जाता है। इसलिए एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को इसके पत्तों की सब्जी का सेवन जरूर करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को इसकी सब्जी जरूर खानी चाहिए क्योंकि उन्हें प्रेग्नेंसी के दौरान आयरन की काफी जरूरत होती है।

बालों व स्किन के लिए फायदेमंद

अरबी के पत्तों में विटामिन ए, सी और बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि बालों और स्किन के लिए बेहद जरूरी होते है। इसके पत्तों की सब्जी का सेवन करें और अपने बालों को मजबूत बनाए रखें। अरबी के पत्तों में एंटी फंगल गुण भी पाया जाता है। इसलिए इसके सेवन से डैंड्रफ की समस्या दूर होती है।